NAMATI

Grassroots Justice Network

कार्बन परियोजना डेवलपर्स के साथ बातचीत कैसे करें

ज़मीनी स्तर के अधिवक्ताओं के लिए एक व्यावहारिक मार्गदर्शिका

अभिस्वीकृतियां

इस मार्गदर्शिका को Namati और Grassroots Justice Network ने सह-विकसित किया था। इस पर सैम्युअल नाई, इरिन किल, ऐन न्योरोगे और रेबेका आइवर्क्स ने रिसर्च करके इसका मसौदा तैयार किया था।

केस स्टडी में राफेल पहरेस, ELAC (Escuela Latinoamericana de Abogacía Comunitaria y Activismo Jurídico); जोनाथन डब्ल्यू. ये, SDI (संधारणीय विकास संस्थान); पाउलो इलिच बाका, सेंटर फ़ॉर द स्टडी ऑफ़ लॉ, जस्टिस एंड सोसाइटी (कानून,न्याय और समाज अध्ययन केंद्र) - डेजुस्टिसिया एंड जूलियन ट्रुहिलो गरेरो, कानून और प्रदेश संबंधी कानूनी क्लिनिक - हावेरियाना यूनिवर्सिटी; अलबिना चेबोय और एलायस किमाइओ, SEECBO (सेंगवर ऑफ़ एम्बोबुट, समुदाय आधारित संगठन); कुंडा जेसिन्टा, ज़ाम्बिया लैंड अलायंस; और, जॉनी एफ़. गिफ़ोनी का योगदान था। Cyrus R. Vance Center for International Justice (अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए साइरस आर वेंस सेंटर) ने फ़ंड पाने की तैयारी के लिए फ़्लो चार्ट में योगदान दिया। उन्होंने प्रोजेक्ट समझौते के प्रमुख घटकों से संबंधित सामग्री पर सहायता और मार्गदर्शन भी दिया था।

हम IMPACT Kenya, DAR (कानून, पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन), RECOFTC (एशिया और पैसिफिक क्षेत्रों के लिए प्रादेशिक सामुदायिक वानिकी प्रशिक्षण), Tropenbos Ghana, KAISAHAN, ProDesc, TreeAid, Namati Kenya, और Namati Sierra Leone के आभारी हैं, जिन्होंने कार्बन परियोजना समझौतों के बारे में बातचीत में समुदायों को जिनका सामना करना पड़ता है उन चुनौतियों के अपने अनुभव और उनके बारे में समझ को उदारतापूर्वक साझा किया। उनके योगदानों ने इस मार्गदर्शिका में दिए गए व्यावहारिक मार्गदर्शन के लिए ठोस आधार प्रदान किया।

मार्गदर्शिका को मज़बूत बनाने में मदद करने वाली टिप्पणियों और फ़ीडबैक के लिए हम एनरिक नुन्येज़, जूनियर, इसाबेल परेरा, लारा डोमिंगेज़, नित्या सुनील और अखिला खोलीशेट्टी के भी आभारी हैं।

कॉपी एडिटिंग पौला अल्वाराडो ने किया है और इस रिपोर्ट को एमिलिया लोपेज़ ने डिज़ाइन किया है।

इस रूप में उद्धृत करें: Namati, *"कार्बन परियोजना डेवलपर्स के साथ बातचीत कैसे करें: ज़मीनी स्तर के अधिवक्ताओं के लिए एक व्यवहारिक मार्गदर्शिका"*, 2025।

यह मार्गदर्शिका इन दानदाताओं की उदार मदद से बनाया गया था:

HAMPSHIRE FOUNDATION

CHARLES STEWART MOTT FOUNDATION

Robert Bosch Stiftung

कार्बन परियोजना डेवलपर्स के साथ बातचीत कैसे करें

ज़मीनी स्तर के अधिवक्ताओं के लिए एक व्यावहारिक मार्गदर्शिका

विषय-सूची

परिचय 6

चरण 1: बातचीत की तैयारी करना 13

I. अपने अधिकारों को समझें 15
II. प्रस्तावित परियोजना के बारे में जानकारी खोजें 21
III. एक समुदाय के रूप में संगठित होना 32
IV. बाहर से कानूनी सहायता प्राप्त करना 45

चरण 2: समझौते (एग्रीमेंट) के लिए शर्तों का प्रस्ताव करना 52

I. परियोजना समझौते (प्रोडेक्ट एग्रीमेंट) में क्या शामिल होता है? 53
II. शर्तों को प्रस्तावित करना 55

चरण 3: प्रोजेक्ट डेवलपर्स के साथ बातचीत करना 72

I. तैयारी करना और अभ्यास करना 75
II. किसी ऑफ़र का मूल्यांकन करना और जवाबी-ऑफ़र रखना 80
III. आम चुनौतियाँ और प्रभावी ढंग से बातचीत करने के लिए सुझाव 95

चरण 4: परियोजना समझौते (प्रोजेक्ट एग्रीमेंट) को लागू करना 105

I. परियोजना संचालन 106
II. फ़ंड प्राप्त करने और प्रबंधित करने की तैयारी करना 109
III. निगरानी और समझौते की शर्तों को लागू करना 113
IV. परियोजना समझौते (प्रोजेक्ट एग्रीमेंट) पर फिर से बातचीत करना 125

अनुलग्नक 129

अनुलग्नक ए: सिएरा लेओन से कार्बन साझीदारी समझौते (कार्बन पार्टनरशिप एग्रीमेंट) का नमूना 130
अनुलग्नक बी: अतिरिक्त केस स्टडीज़ 143
अनुलग्नक सी: अतिरिक्त संसाधन 150

परिचय

Grassroots Justice Network के सदस्य ऐसी दुनिया में विश्वास करते हैं जहाँ हर कोई अपने अधिकारों की रक्षा करने के लिए कानून का इस्तेमाल कर सकता है और निर्णय लेने में हिस्सा ले सकता है। इसमें कार्बन बाज़ार (कार्बन मार्केट) से प्रभावित समुदाय शामिल हैं।

हाल के वर्षों में कार्बन बाजारों के तेजी से विस्तार के साथ, दुनिया भर के कई समुदाय खुद को अपनी भूमि पर प्रस्तावित कार्बन परियोजनाओं का जवाब देते हुए पा रहे हैंपरियोजनाओं कार्बन परियोजना, संरक्षण, नवीकरणीय ऊर्जा और अन्य तरीकों के ज़रिए ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के प्रयास हैं। वे भूमि के बड़े क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं, ख़ासकर लैटिन अमेरिका, अफ़्रीका और एशिया में।

21 देशों में कार्बन परियोजनाओंपरियोजनाओं के साथ के अनुभव के आधार पर, Grassroots Justice Network ने कार्बन परियोजनाओं को निष्पक्ष बनाने के लिए छह आवश्यक सिद्धांतों को एकजुट किया है। सीधे शब्दों में कहें, तो सभी कार्बन परियोजनाओं को उन समुदायों के अधिकारों और नेतृत्व का सम्मान करना चाहिए, जिनकी भूमि पर वे हैं।

कार्बन न्याय के सिद्धांत

1. प्रदूषित कर पाने के लिए भुगतान करें नहीं

- परिहार्य उत्सर्जन को ख़तम करने **के बजाये कार्बन भुगतान का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए**।
- जीवाश्म ईंधन (फ़ॉसिल फ़्यूल) **कंपनियों को कार्बन पेमेंट स्कीम में हिस्सा लेने से रोक दिया जाना चाहिए**।

2. भूमि और पानी पर सामुदायिक अधिकारों का सम्मान करना

- **समुदायों के इस्तेमाल और मालिकाना अधिकार को स्वीकृति देना,** जिनमें प्रथागत अधिकार भी शामिल हैं, भले ही किसी समुदाय के पास भूमि पर कानूनी मालिकाना अधिकार हो या नहीं।
- खास चुनी गई समितियों की स्थापना करने के बजाय, **वैध सामुदायिक शासन संरचनाओं के साथ काम करना।**

3. स्वतंत्र, पूर्व और सूचित सहमति

- जिन समुदायों की भूमि पर सवाल है, उनकी ओर से मज़बूत और सार्थक स्वतंत्र, पूर्व, सूचित सहमति (FPIC) के बिना कोई भी कार्बन परियोजना स्थापित नहीं किया जाना चाहिए। **इसमें समुदाय का ना कहने का अधिकार भी शामिल है।**
- "सूचित" का अर्थ है परियोजना के पूरे जीवन चक्र के दौरान अन्य बातों के अलावा, इसमें शामिल सभी कार्रवाई करने वालों और साथ ही सकल राजस्व और दूसरी वित्तीय जानकारी को समुदाय के समक्ष प्रकट करना।
- **स्वतंत्र, पूर्व, सूचित सहमति का मतलब है कि सभी निवासी निर्णय लेने में हिस्सा ले सकते हैं,** जिनमें महिलाएं, भूमि का उपयोग करने वाले, युवा और अन्य समूह शामिल हैं।

4. उचित मुआवजा

- प्रकृति-आधारित प्रोजेक्ट्स जिन समुदायों की भूमि यह है, उन्हें **सकल राजस्व का कम से कम 50% मिलना चाहिए।**
- **समुदाय यह तय कर पाने चाहिए कि वह पैसा कैसे खर्च हो,** उदाहरण के लिए किस प्रकार की विकासात्मक परियोजनाओं पर।

5. निष्पक्ष भागीदारी

- **समुदाय को** प्रशिक्षण और रोज़गार के अवसरों तक पहुँच बनाने सहित प्रर्यवेक्षण कार्य की **अगुआई के लिए सक्षम बनाना।**
- **ऐसी सामुदायिक गतिविधियों को अनुमति देना जो कार्बन भंडारण को प्रभावित नहीं करती हैं,** जैसे कि गैर-लकड़ी वन उपज का संग्रह।
- समुदाय के सदस्यों को प्रतिशोध के **डर के बिना अपने अधिकारों का इस्तेमाल करने** में सक्षम होना चाहिए।
- सुनिश्चित करना कि समुदायों को परियोजना के पहले और उसके दौरान स्वतंत्र कानूनी सहायता तक पहुँच प्राप्त हो।
- समुदायों के लिए सीधे, बिना बिचौलियों के कार्बन भुगतान तक पहुँच बनाना आसान बनाना।

6. प्रवर्तन

- **इन सभी सिद्धांतों को लागू किया जाना ज़रूरी है।** सरकारों और प्रमाणन निकायों को कड़ी निगरानी और जवाबदेही सुनिश्चित करनी चाहिए।
- जब कार्बन परियोजना इन सिद्धांतों का उल्लंघन करती हैं या कोई और गड़बड़ी हो जाती है, **तब समुदायों के पास समाधान पाने के लिए सरल रास्ते हों।**

ये सिद्धांत कार्बन परियोजना के संदर्भ में समुदायों के फलने-फूलने के लिए आवश्यक न्यूनतम स्थितियों को दर्शाते हैं। अपने पूरे नेटवर्क में, हम समुदाय, राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर कार्बन बाज़ार (कार्बन मार्केट) पर मजबूत नियमों के लिए वकालत करने के लिए कार्बन न्याय के सिद्धातों का इस्तेमाल कर रहे हैं। जब समुदाय कार्बन परियोजना डेवलपर्स के साथ बातचीत करते हैं, तब ये सिद्धांत एक मज़बूत शुरुआत भी देते हैं।

कार्बन बाज़ार (कार्बन मार्केट) एक उपयुक्त जलवायु समाधान है या नहीं, इस बारे में बहस चल रही है। यह मार्गदर्शिका उस सवाल को संबोधित नहीं करता है। इसके बजाय, यह इस पर ध्यान देता है कि समुदायों को उनकी भूमि पर कार्बन परियोजना प्रस्तावित होने पर प्रतिक्रिया[1] देने के लिए कैसे तैयार किया जाए। मार्गदर्शिका का उद्देश समुदायों को परियोजना के बारे में प्रभावी निर्णय लेने में शामिल होने और उनके अधिकार सुरक्षित हों यह सुनिश्चित करने के लिए सशक्त बनाना है, तब भी अगर वे परियोजना से इन्कार करने का निर्णय लें। यह ऐसे उपकरण प्रदान करता है जिनका उपयोग समुदाय किसी परियोजना के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने, आंतरिक रूप से जानबूझकर, ताकत से बातचीत करने और समझौता होने पर शर्तों की निगरानी और उन्हें लागू करने के लिए कर सकते हैं।

- **चरण 1: बातचीत की तैयारी करना।** पहला सेक्शन शुरुआती चरणों में तथ्यों की खोज करने और सामूहिक आयोजन के बारे में मार्गदर्शन देता है, जब समुदाय यह तय करते हैं कि वे बातचीत करना चाहते हैं या नहीं।
- **चरण 2: शर्तों को प्रस्तावित करना।** दूसरा सेक्शन अपने समुदायों के लक्ष्यों के आधार पर शर्तों को सक्रिय रूप से कैसे प्रस्तावित किया जाए इस बात पर केंद्रित है। इसमें कार्बन परियोजना समझौते के तत्वों का अवलोकन और सह-प्रबंधन और उचित राजस्व साझेदारी के लिए महत्वपूर्ण सुरक्षा उपायों और सिद्धांतों पर एक विस्तृत नज़र शामिल है।
- **चरण 3: शर्तों पर बातचीत करना।** अगले सेक्शन में, हम परियोजना डेवलपरों के साथ बातचीत करने के लिए व्यावहारिक सुझाव प्रदान करते हैं, एक प्रस्ताव का मूल्यांकन करने के तरीके से लेकर शक्ति प्रयोग को संबोधित करने के लिए रणनीतियों तक।
- **चरण 4: समझौते को लागू करना।** आखिर में, हम देखेंगे कि कैसे समुदाय परियोजना में नेतृत्व की भूमिका निभाने के लिए एक मजबूत आधार बना सकते हैं। हम उन कदमों की भी रूपरेखा प्रदान कर रहे हैं, जिनसे आप परियोजना डेवलपर के साथ समझौते की शर्तों की निगरानी कर सकते हैं और उन्हें लागू कर सकते हैं।

---

1 यह मानते हुए कि मूल निवासी लोगों की अपने क्षेत्रों में अलग पहचान और शासन प्रणालियाँ होती है, पूरी मार्गदर्शिका में हम समुदाय का उपयोग मूल निवासी लोगों और स्थानीय समुदायों (IPLC) दोनों को संदर्भित करने के लिए करते हैं।

सशक्त होकर बातचीत में शामिल होना

1. सहभागिता की तैयारी करना

परियोजना के बारे में तथ्य ढूँढें और अपने लक्ष्यों को तय करने के लिए सामूहिक रूप से व्यवस्थित करें।

2. शर्तों को प्रस्तावित करना

मुख्य मांगों और ऐसे किसी भी बिंदु को पहचानें, जिन पर बातचीत न की जा सके।

3. शर्तों पर बातचीत करना

परियोजना डेवलपर के ऑफ़र का आकलन करें और जवाबी ऑफ़र दें।

4. समझौते को लागू करना

परियोजना संचालन में हिस्सा लें और उन शर्तों पर नज़र रखें जिन पर सहमति हुई थी।

यह मार्गदर्शिका समुदाय के नेताओं और फ़्रंटलाइन अधिवक्ताओं के लिए है, जो समुदायों का अपनी भूमि पर कार्बन परियोजनाओं का जवाब देने के लिए समर्थन कर रहे हैं। मार्गदर्शिका का इस्तेमाल करने से पहले, कार्बन बाज़ार (कार्बन मार्केट) और कार्बन पेमेंट के दूसरे तरीकों के बारे में कुछ मूलभूत जानकारी होना मददगार होगा। कार्बन पेमेंट कैसे काम करता है, इस बारे में ज़्यादा जानने के लिए हमने अनुलग्नक C में उपयोगी संसाधनों की एक सूची शामिल की है।

मार्गदर्शिका आपके संदर्भ के अनुसार अनुकूलित किया जा सकता है और किया जाना चाहिए। यह प्रक्रिया सभी के लिए एक समान तरीके से उपयुक्त नहीं हो सकती है। आपके लिए सही तरीका तय करने के लिए, स्थानीय ज्ञान, मूल्य और शासन प्रक्रियाओं को एकीकृत करना ज़रूरी है।

मुख्य शब्दों का सिंहावलोकन

- **कार्बन बाज़ार (कार्बन मार्केट):** ग्रीनहाउस गैस घटाव के लिए कार्बन क्रेडिट ख़रीदने और बेचने की प्रणाली। व्यक्ति, कंपनियां या देश अपने जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अपने कुछ उत्सर्जन की भरपाई करने के लिए क्रेडिट खरीद सकते हैं।
- **कार्बन क्रेडिट:** किसी कार्बन परियोजना के कारण संग्रहित किया गया या उत्सर्जित नहीं किया गया एक टन कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन क्रेडिट का सत्यापन एक स्वतंत्र निकाय द्वारा किया जाता है और कार्बन बाज़ार (कार्बन मार्केट) के ज़रिए इनका व्यापार किया जा सकता है या उन्हें बेचा जा सकता है।
- **कार्बन मानक:** एक स्वतंत्र निकाय जो प्रमाणित करता है कि परियोजनाओं ने उत्सर्जन में कमी उत्पन्न की है और सामाजिक और पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों का अनुपालन किया है।
- **कार्बन अधिकार:** किसी पारिस्थितिक तंत्र की कार्बन को अवशोषित करने और संग्रहित करने की क्षमता से फ़ायदा उठाने का अधिकार, आम तौर पर पेड़ों, घास या मिट्टी के ज़रिए।
- **परियोजना डेवलपर:** वह संगठन जो कार्बन परियोजना के डिज़ाइन और कार्यान्वयन का नेतृत्व करता है (जिसे कभी-कभी "परियोजना प्रोपोनेंट या प्रस्तावक" भी कहा जाता है)।
- **परियोजना कार्यान्वयन समझौता:** परियोजना डेवलपर (डेवलपरों) और स्थानीय समुदायों या अन्य अधिकार धारकों के बीच एक कानूनी समझौता, जो परियोजना, शासन संरचनाओं, मुख्य गतिविधियों और भूमि उपयोग, सामुदायिक अधिकारों के लिए सुरक्षा उपायों और राजस्व साझा करने की व्यवस्था में भूमिकाओं को परिभाषित करता है।

चरण 1: सहभागिता की तैयारी करना

कार्बन परियोजना समझौता (कार्बन प्रोजेक्ट एग्रीमेंट) करना किसी भी समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण कदम होता है। यह आर्थिक क्षतिपूर्ति और स्थानीय संरक्षण के प्रयासों के लिए सहायता जैसे फ़ायदे ला सकता है।

लेकिन यह जोखिमों के साथ भी आता है, जिसमें आपकी भूमि तक पहुँच या नियंत्रण की संभावित कमी और स्थानीय आजीविका में परिवर्तन शामिल हैं समुदायों को ध्यान से विचार करना चाहिए कि वे समझौता करना चाहते हैं या नहीं, और यदि ऐसा है तो किन शर्तों पर। जब आप यह करते हैं, तब सोच-समझकर फ़ैसला लेने में आपकी मदद करने के तीन चरण हैं: 1) अपने अधिकारों को समझना, 2) परियोजना के बारे में जानकारी पाना और 3) अपने समुदाय के लक्ष्यों और प्राथमिकताओं को परिभाषित करने के लिए सामूहिक रूप से सुसंगठित होना।

I. अपने अधिकारों को समझो

A. भूमि के स्वामित्व के अधिकार

कार्बन परियोजना वैश्विक स्तर पर भूमि के विशाल क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं, जिनमें से अधिकांश का प्रबंधन वर्तमान में समुदायों द्वारा किया जाता है। अगर आपके समुदाय के भूमि अधिकारों को औपचारिक रूप से मान्यता नहीं दी गई है, तो कार्बन परियोजना महत्वपूर्ण जोखिम पैदा कर सकते हैं और निष्पक्ष समझौते पर बातचीत करना मुश्किल हो सकता है। इससे पहले कि आप किसी परियोजना डेवलपर से बात करें, राष्ट्रीय भूमि कानूनों के तहत अपने अधिकारों के बारे में जानना ज़रूरी है। ज़रूरत पड़ने पर, क़ानून को समझने और अपने समुदाय के लिए सरल सारांश बनाने के लिए, कानूनी सलाह लें या सहयोगियों से मदद लें।

विचार करने योग्य प्रश्न:

- क्या आपके पास अपनी भूमि के लिए भूमि के औपचारिक कागज़ात हैं?
- अगर नहीं, तो क्या आपके रूढ़िगत अधिकारों को राष्ट्रीय कानून द्वारा मान्यता प्राप्त है?
- राष्ट्रीय कानून के तहत कार्बन के अधिकार या कार्बन पर कानूनी स्वामित्व किसके पास है?

इन सवालों के जवाब इस बात पर असर डालते हैं कि आपकी भूमि पर कार्बन परियोजना पर आपका कितना नियंत्रण है और आपके पास इसके बारे में निर्णय लेने की कितनी क्षमता है। अगर आपके अधिकारों को पूरी तरह से स्वीकृति नहीं मिली है, तो आगे बढ़ने से पहले, अपने भूमि अधिकारों और इस्तेमाल के इतिहास का दस्तावेजीकरण करने के लिए कदम उठाने पर विचार करें।

व्यवहारिक सुझाव: बातचीत शुरू करने से पहले अपने समुदाय के भूमि अधिकारोंको औपचारिक रूप से रजिस्टर करने के लिए स्थानीय कानूनी सहायता समूहों, सिविल सोसायटी संगठनों या भूमि आयोगों के साथ काम करें। यह मुश्किल और समय लेने वाला हो सकता है, तो अगर यह संभव न हो, तो अपने पारंपरिक भूमि अधिकारों का दस्तावेजीकरण करने और उन्हें बेहतर बनाने के लिए अन्य तरीकों का इस्तेमाल करें, जैसे कि सामुदायिक मानचित्रण या स्थानीय अधिकारियों का एक पत्र जिसमें भूमि के प्रबंधन या इस्तेमाल के आपके इतिहास को स्वीकार किया गया हो।

चाहे आपके भूमि अधिकारों को औपचारिक रूप से मान्यता दी गई हो या नहीं, ऐसे सुरक्षा उपाय हैं जिनका इस्तेमाल करके आप निवेश के दौरान अपने समुदाय की सुरक्षा कर सकते हैं। इनमें आम तौर पर शामिल हैं, जानकारी पाने का अधिकार, सामुदायिक भूमि पर संचालित करने के लिए परियोजना के लिए सहमति देने या अस्वीकार करने का अधिकार , और कुछ मामलों में आपकी भूमि पर बाहरी निवेश से कुछ लाभों के अधिकारभूमि।

- **राष्ट्रीय भूमि कानून** समुदायों द्वारा भूमि का इस्तेमाल और प्रबंधन करने के अधिकारों को परिभाषित करते हैं। ज़्यादातर मामलों में, उन कानूनों में बाहरी निवेशकों को भूमि अधिग्रहण के लिए जो आवश्यक कदम उठाये जाने होते है, उनके सम्बंधित प्रावधान भी शामिल करते हैं। अक्सर एक बड़ा सवाल यह होता है कि क्या आपके देश में भूमि कानून पारंपरिक भूमि अधिकारों को मान्यता देता है या नहीं।
- **संरक्षण और वन प्रबंधन संबंधी राष्ट्रीय कानून** में अक्सर जलमय भूमि, मैंग्रोव, वन्य जीव कॉरिडोर जैसे संवेदनशील पारिस्थितिक तंत्र में भूमि का प्रबंधन कैसे किया जाता है इसके लिए आवश्यकताएं, साथ ही संरक्षण में सरकारी एजेंसियों, स्थानीय समुदायों और निजी कार्रवाई करने वालों की भूमिकाओं को परिभाषित किया जाता है। कई देशों में वे अपने मूल निवासी लोगों के अपने क्षेत्रों के संचालन, सामुदायिक प्रबंधन और/या स्थानीय समुदायों के साथ सह-प्रबंधन को भी स्वीकृति देते हैं।
- **राष्ट्रीय कार्बन नीतियां और अन्य निवेश संबंधी कानून** — और उनके साथ जुड़े नियम — यह बताते हैं कि भूमि, वनस्पतियों, मिट्टी या तटीय जल में कार्बन के अधिकार किसके पास हैं। वे परियोजना डेवलपर के लिए सरकार से ऑपरेटिंग परमिट या लाइसेंस लेने के लिए ज़रूरी शर्तें और मंज़ूरी की प्रक्रिया का भी वर्णन करते हैं। अक्सर, उनमें जानकारी तक सार्वजनिक पहुँच, स्वतंत्र, पूर्व, सूचित सहमति, और यहाँ तक कि स्थानीय समुदायों के साथ लाभों को साझा करने (बेनिफिट शेयरिंग) की ज़रूरतें भी शामिल होती हैं। निवेश संबंधी अन्य कानून भी प्रासंगिक हो सकते हैं, खासकर अगर वे भूमि अधिग्रहण के नियमों को परिभाषित करते हैं।
- वैश्विक **कार्बन मानक** (कार्बन स्टैंडर्ड) जिसके तहत परियोजना रजिस्टर की हुई है या की जाएगी, वह उन ज़रूरतों को भी निर्धारित करता है जिन्हें परियोजना डेवलपर्स को पूरा करना होगा। कई मामलों में, इनमें मौजूदा स्वामित्व के अधिकारों का सम्मान करना, प्रभावित समुदायों को जानकारी देना और स्वतंत्र, पूर्व, सूचित सहमति शामिल हैं।

	वेरिफाइड कार्बन स्टैण्डर्ड (VCS) सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला कार्बन क्रेडिट प्रोग्राम है। दुनिया भर में प्रकृति-आधारित ज़्यादातर परियोजनाएं VCS के तहत रजिस्टर की जाती हैं।
Verra (VCS)	Verra जलवायु, समुदाय और जैव-विविधता मानक (CCB) की देखरेख भी करता हैं, जो प्रकृति-आधारित परियोजनाओं के लिए एक अतिरिक्त वैकल्पिक प्रमाणन है, जो जैव विविधता या स्थानीय समुदायों के लिए सकारात्मक परिणामों को बढ़ावा देता है। CCB में समुदायों और स्थानीय पारिस्थितिक तंत्र के लिए और कड़े सुरक्षा उपाय शामिल हैं।
Gold Standard	Gold Standard दूसरा सबसे बड़ा कार्बन मानक है, जिसके तहत कई परियोजनाएं रजिस्टर की गई हैं और की जा रही हैं। अन्य कार्बन मानकों की तुलना में, इसमें सामुदायिक सहभागिता के लिए ज़्यादा विस्तृत ज़रूरतें शामिल हैं और इसके साथ ही कम से कम 3 सतत विकास लक्ष्यों (SDG) पर सकारात्मक प्रभाव आवश्यक हैं।
ART-TREES	ART-TREES खास कर निर्वनीकरण या वन प्रबंधन पर क्षेत्राधिकार वाली परियोजनाओं के लिए जिनका नेतृत्व सरकार करती है और जिसमें राज्य या फिर कुछ मामलों में पूरे राष्ट्रीय क्षेत्र के जैसा एक समग्र प्रशासनिक ज़िला शामिल होता है।
Plan Vivo	Plan Vivo मानक उन परियोजनाओं के लिए डिज़ाइन किया गया था, जिनकी छोटे किसानों और स्थानीय समुदायों के साथ महत्वपूर्ण साझेदारी है। जहाँ Plan Vivo के तहत अपेक्षाकृत कम परियोजनाएं रजिस्टर की जाती हैं, यह सामुदायिक फ़ायदों के लिए ज़्यादा ऊँचे बेंचमार्क सेट करता है - इसके लिए ज़रूरी है कि क्रेडिट से होने वाली कमाई का कम से कम 60% स्थानीय समुदायों को जाए।

- **मानव अधिकारों संबंधी अंतर्राष्ट्रीय कानून और कन्वेंशन** जैसे कि मूल निवासी लोगों के अधिकारों संबंधी संयुक्त राष्ट्र की घोषणा में भी उपयोगी मानदंड और प्रतिबद्धताएं शामिल हैं — हालांकि इन्हें लागू करना अक्सर राष्ट्रीय सरकार पर निर्भर करता है। फिर भी, ऐसे मामलों में जहां सरकार समुदायों के अधिकारों का उल्लंघन कर रही है, अंतर्राष्ट्रीय कानून सुधार के लिए अतिरिक्त रास्ते प्रदान कर सकता है।

B. स्वतंत्र, पूर्व और सूचित सहमति

एक और प्रभावशाली सुरक्षा उपाय में समुदायों को उनकी भूमि या क्षेत्र को प्रभावित करने वाली परियोजनाओं के लिए स्वतंत्र, पूर्व और सूचित सहमति या FPIC का अधिकार शामिल है। मूल निवासी और जनजातीय लोगों के लिए, स्वतंत्र, पूर्व, सूचित सहमति का अधिकार अंतर्राष्ट्रीय कानून द्वारा सुरक्षित है।[2] कुछ देशों में राष्ट्रीय कानून में ऐसे प्रावधान भी हैं जो स्वतंत्र, पूर्व, सूचित सहमति की सुरक्षा करते हैं और यह मूल निवासी लोगों और अन्य स्थानीय समुदायों, दोनों के लिए निजी क्षेत्र में बड़े पैमाने पर भूमि निवेश का एक मानक बन गया है।

- ज़बरदस्ती, डराने-धमकाने या चालाकी से **मुक्त।**
- सामुदायिक भूमिभूमि पर किसी भी गतिविधि के शुरू होने से **पहले।**
- स्थान, परियोजना के क्षेत्र में सभी गतिविधियों और नियोजित भूमि उपयोग, समुदायों और स्थानीय पारिस्थितिक तंत्र को कोई भी संभावित जोखिम और प्रभाव, परियोजना की अवधि और समुदाय को प्राप्त होने वाले राजस्व और अन्य लाभों सहित निर्णय लेने के लिए आवश्यक सभी महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में **सूचित।**
- परियोजना आगे बढ़ता है या नहीं और किन शर्तों के तहत, इसके लिए स्थानीय अधिकार धारकों की **सहमति।** इसमें समुदायों का स्पष्ट रूप से ना कह पाना या ऐसी विशिष्ट शर्तें रख पाना शामिल है जिनके तहत वे सहमति प्रदान करने को इच्छुक हैं।

2 मूल निवासी लोगों का अपने प्रदेशों में किसी भी गतिविधि के लिए स्वतंत्र, पूर्व और सूचित सहमति का अधिकार कई अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के तहत संरक्षित है, जिसमें स्वदेशी लोगों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र घोषणा (UNDRIP) का अनुच्छेद 32 और ILO कन्वेन्शन 169 शामिल हैं।

- स्वतंत्र, पूर्व, सूचित सहमति की आवश्यकता तब होती है जब कोई परियोजना उस भूमि या संसाधनों को प्रभावित करती है जिन्हें समुदायों ने ऐतिहासिक रूप से प्रबंधित किया है या जिन पर वे अपनी आजीविका के लिए निर्भर हैं। इसमें खेती, चराई, जलाऊ लकड़ी इकट्ठा करने, साथ ही भूमि से जुड़ी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक प्रथाओं पर प्रतिबंध शामिल हैं।
- स्वतंत्र, पूर्व, सूचित सहमति एक बार की हाँ या ना नहीं है। यह सामुदायिक भूमि पर बाहरी निवेश के बारे में फ़ैसले लेने का अधिकार है - जिसमें यह भी शामिल है कि कौनसी गतिविधियाँ, कहाँ और किन परिस्थितियों में होगीं। स्वतंत्र, पूर्व, सूचित सहमति परियोजना के जीवनकाल में चलने वाली प्रक्रिया है।

कई कार्बन मानकों के लिए परियोजना डेवलपर को किसी परियोजना को रजिस्टर करने से पहले अधिकार धारकों और प्रभावित समुदायों से सहमति लेनी होती है। Verra और Gold Standard दोनों ने किसी परियोजना को मंज़ूरी मिलने से पहले स्वतंत्र, पूर्व, सूचित सहमति के लिए विस्तृत आवश्यकताएँ निर्धारित की हैं।[3] परियोजना डेवलपर्स को परियोजना के बाद के चरणों में किसी भी बड़े प्रस्तावित बदलाव या नए तत्वों के लिए भी सहमति लेनी होगी (उदाहरण के लिए, परियोजना क्षेत्र का विस्तार या अगर नए भूमि उपयोग प्रस्तावित हैं)।

इसकी तुलना में, अन्य मानक केवल आंशिक रूप से स्वतंत्र, पूर्व, सूचित सहमति के अधिकार की रक्षा करते हैं। अनुच्छेद 6.4 संधारणीय विकास टूल सिर्फ़ मूल निवासी लोगों और ART-TREES के लिए स्वतंत्र, पूर्व, सूचित सहमति की सुरक्षा करता है, यह मानक जिसे ख़ास तौर पर अधिकार क्षेत्र के REDD+ (निर्वनीकरण और वन घटाव से उत्सर्जनों को घटाना) परियोजनाओं के लिए डिज़ाइन किया गया है, इसके लिए भूमि अधिकारों के रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता होती है, लेकिन सिर्फ़ खास संदर्भों में स्वतंत्र, पूर्व सूचित सहमति की सुरक्षा करता है, उदाहरण के लिए, अगर स्थानीय समुदायों का कोई स्थानांतरण होता है। स्वतंत्र, पूर्व, सूचित सहमति की आवश्यकता होने पर भी, व्यवहार में उसका पूरा सम्मान किया गया है यह सुनिश्चित करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है।

3 उदाहरण के लिए, Verra के VCS मानक वर्शन 5 में पृष्ठ 48-55 देखें, जो https://verra.org/wp-content/uploads/2025/12/VCS-Standard-v5.0.pdf पर उपलब्ध है।

"स्वतंत्र, पूर्व, सूचित सहमति साझेदारी के लिए एक रूपरेखा है, जिसमें समान लाभ साझाकरण समझौतों (इक्विटेबल बेनिफिट शेयरिंग) या संरक्षण के लिए समझौता ज्ञापन (मेमोरेंडम ऑफ़ अंडरस्टैंडिंग) के विकल्प शामिल हैं।"

- जोआन कार्लिंग, इंडिजिनस पीपल्स राइट्स इंटरनेशनल

सामूहिक निर्णय लेने के लिए स्वयं के दृष्टिकोण के आधार पर समुदायों को यह परिभाषित करना चाहिए कि उनके संदर्भ में एक उपयुक्त स्वतंत्र, पूर्व, सूचित सहमति प्रक्रिया में क्या शामिल है। आपका समुदाय जो भी प्रक्रिया तैयार करता है, स्वतंत्र, पूर्व, सूचित सहमति को एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में सोचना उपयोगी होता है, जो निष्पक्ष बातचीत से शुरू होती है, जिसे समुदायों और परियोजना समर्थकों के बीच एक हस्ताक्षरित समझौते के माध्यम से औपचारिक रूप दिया जाता है, जो दोनों पक्षों द्वारा सहमति की हुई प्रतिबद्धताओं को दर्शाता है, और परियोजना समझौते की शर्तों के प्रति निरंतर जुड़ाव और सम्मान के माध्यम से इसे परियोजना के पूरे जीवन भर बनाए रखा जाना होगा। इस मार्गदर्शिका के चरण 2 से 4 में बातचीत के ज़रिए स्वतंत्र, पूर्व, सूचित सहमति को आगे बढ़ाने और होने वाले किसी भी समझौते की निगरानी और उन्हें लागू करने की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है।

II. प्रस्तावित परियोजना के बारे में जानकारी खोजें

समुदायों को परियोजना में संलग्न होना है या नहीं और बातचीत के दौरान उन्हें क्या संबोधित करने की आवश्यकता है इसको सुनिश्चित करते वक्त जानकारी के कई प्रमुख हिस्से हैं जो समुदायों को प्राप्त होने चाहिए इसमें शामिल हैं:

- किस तरह की परियोजना प्रस्तावित की जा रही है?
- परियोजना डेवलपर कौन है?
- यह परियोजना भूमि उपयोग, स्थानीय पारिस्थितिक तंत्र, और समुदायों की संसाधनों तक पहुँच और उनके इस्तेमाल को कैसे प्रभावित करेगी?
- परियोजना से कितना राजस्व मिल सकता है?

ज़्यादातर मामलों में, यह परियोजना डेवलपर की ज़िम्मेदारी होती है कि वह सार्वजनिक सलाह-मशविरा और किसी परियोजना समझौते के लिए बातचीत के हिस्से के रूप में आपके साथ इसमें से ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी साझा करे। फिर भी, समुदायों को अक्सर निर्णय लेने के लिए आवश्यक जानकारी तक पहुँच बनाने में मुश्किल होती है। आप बातचीत शुरू करें इससे पहले तथ्य खोजने में अक्सर बहुत मेहनत लगती है।

A. यह किस तरह की परियोजना है?

वानिकी, ऊर्जा दक्षता, परिवहन, औद्योगिक प्रक्रियाओं, कचरे के निपटान, और अधिक से 170 से अधिक प्रकार के कार्बन क्रेडिट उत्पन्न होते हैं। हर तरह की परियोजना अलग-अलग तरीकों से कार्बन क्रेडिट उत्पन्न करती है, (क) ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन से बच कर या (ख) वातावरण से कार्बन हटाकर।

इमेज का स्रोत: Ecosystem Marketplace

आसान तरीके से कहा जाए, तो दो तरह की परियोजनाएं भूमि के बड़े इलाक़ों को प्रभावित करती हैं — जिनमें दुनिया भर के ज़्यादातर हिस्से शामिल हैं, ऐसे क्षेत्र जिन्हें फ़िलहाल स्थानीय समुदायों द्वारा प्रबंधित किया जाता है:

1. **प्रकृति-आधारित परियोजना** जो कार्बन उत्सर्जन को कम करने या कार्बन को संग्रहित करने के लिए जंगल, आर्द्रभूमि या खेतों जैसे पारिस्थितिक तंत्रों के संरक्षण और संधारणीय प्रबंधन का इस्तेमाल करती हैं।
2. **पुनर्नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना,** जो जीवाश्म ईंधन जलाने से पैदा होने वाली बिजली का स्थान लेने के लिए हवा, सौर या हाइड्रो जैसे स्वच्छ स्रोतों से ऊर्जा उत्पन्न करके इस प्रक्रिया में ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करती हैं।

हालांकि आम तौर पर उनका सामुदायिक भूमि अधिकारों पर बड़ा प्रभाव नहीं पड़ता है, **क्लीन कुकस्टोव (स्वच्छ चूल्हा) परियोजना** एक अन्य तरह की परियोजना होती है जिसमें अक्सर समुदाय शामिल होते हैं और समुदायों के लिए ऐसे निष्पक्ष समझौतों के बारे में बातचीत करने के अवसर पेश करती हैं, जिनसे उन्हें फायदा होता है। हालांकि यह मार्गदर्शिका मुख्य रूप से ऐसी परियोजनाओं पर केंद्रित है, जो सामुदायिक भूमि अधिकारों को सीधे प्रभावित करती हैं, यहाँ दी गई रणनीतियों का इस्तेमाल उन परियोजनाओं के लिए बातचीत में भी किया जा सकता है।

प्रकृति आधारित परियोजनाओं पर करीब से नज़र

कृषि

- ये परियोजना कृषि भूमि प्रबंधन (ALM) के ज़रिए खेतों और चरागाहों में मिट्टी की सेहत को बेहतर बनाने पर केंद्रित हैं। आपने कभी-कभी इसे रीजनरेटिव एग्रीकल्चर के नाम से भी सुना होगा।

आर्द्रभूमि

- आर्द्रभूमि नवीनीकरण और संरक्षण (WRC) परियोजना दलदल वाली भूमि, कच्छ भूमि, बाढ़ के मैदानों के वनों और मैंग्रोव की सुरक्षा करती हैं। **ब्लू कार्बन परियोजना** ख़ास तौर से समुद्री और तटीय पारिस्थितिक तंत्रों, जैसे कि मैंग्रोव पर केंद्रित होती है। इन परियोजनाओं की लोकप्रियता बढ़ रही है, क्योंकि इनमें कई तरह की प्रकृति-आधारित परियोजनाओं की तुलना में अधिक समय तक भारी मात्रा में कार्बन जमा रहता है।

वानिकी और भूमि उपयोग

- वनों की कटाई और वनों के क्षरण से उत्सर्जन को कम करने (REDD+) वाली परियोजना, वनों की सफाई या असंधारणीय कटाई को कम करती है। REDD+ परियोजना संयुक्त राष्ट्र के तहत विकसित फ़्रेमवर्क पर आधारित होती हैं, लेकिन उनके जलवायु पर अपने प्रभाव को बढ़ा-चढ़ाकर बताने के लिए उनकी बहुत आलोचना की गई है।
- वनीकरण, पुनर्वनीकरण, और पुनः वनस्पतीयन (ARR) परियोजनाएं नई जगहों पर पेड़ लगाने या खराब हो चुके वन क्षेत्रों को बहाल करने पर ध्यान केंद्रित करती हैं।
- बेहतर वन प्रबंधन (IFM) परियोजनाएं मौजूदा वनों में बेहतर प्रबंधन पद्धतियां पेश करती हैं।

प्रकृति-आधारित परियोजना प्रकारों और परिवर्णी शब्दों की सूची **यहाँ** देखें।

B. परियोजना डेवलपर कौन है?

परियोजना डेवलपर निजी कंपनियां, गैर-सरकारी संगठन या सरकारी एजेंसियां हो सकते हैं। बातचीत के दौरान शक्ति गतिकी हर मामले में अलग होगी। उदाहरण के लिए, निजी कंपनियों के साथ समुदायों के पास परियोजना डिजाइन को आकार देने के महत्वपूर्ण अवसर हो सकते हैं, लेकिन आपको मुनाफे के लिए उनकी उम्मीद से निपटना होगा, और उनके निवेशक अक्सर उनके निर्णय लेने को प्रभावित करते हैं। इसकी तुलना में, जब कोई सरकारी एजेंसी परियोजना का प्रस्ताव करती है, तब हो सकता है कि परियोजना के कुछ तत्व लचीले नहीं हो और ऐसे जोखिम हो सकते हैं कि कुछ सामुदायिक अधिकार सरकार को ट्रांसफर किए जाएंगे। साथ ही, सरकारों ने अक्सर समुदायों और स्थानीय पारिस्थितिक तंत्रों की सुरक्षा के लिए कुछ सुरक्षा उपायों के लिए प्रतिबद्धताएं बनाई होती हैं। समय निकालकर पता करें कि डेवलपर कौन है और उनके हित क्या हैं।

किसी भी परियोजना डेवलपर के लिए, यह भी विचार करें कि क्या वे एक सक्षम, ईमानदार पार्टनर बनेंगे।

- **संबंधित विशेषज्ञता:** क्या उनके पास परियोजना को प्रभावी ढंग से कार्यान्वित करने के लिए ज्ञान, कौशल और अनुभव है?
- **ट्रैक रिकॉर्ड:** क्या उन्होंने दूसरी कार्बन परियोजना कार्यान्वित की हैं? यदि ऐसा है, तो क्या वे परियोजनाएं सफल रहीं? क्या अधिकारों के उल्लंघन की कोई रिपोर्ट आई है?
- **फ़ंडर्स:** परियोजना में निवेशक कौन हैं? उन्होंने कौनसी शर्तें तय की हैं और मुख्य फ़ैसलों पर उनका क्या नियंत्रण है?

कई परियोजनाओं में कई कार्रवाई करने वाले शामिल होते हैं जो साझेदारी में परियोजना को लागू कर रहे होते हैं। इससे यह समझना मुश्किल हो सकता है कि कौन शामिल है और हर कार्रवाई करने वाले की भूमिका और ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं। जितनी जल्दी हो सके, कौन शामिल है इस बारे में स्पष्ट जानकारी मांगें। आपको परियोजना के मुख्य प्रस्तावक (प्रस्तावकों) से सीधे संपर्क करना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि आपके द्वारा किए गए सभी समझौते परियोजना में शामिल सभी साझीदारों या ठेकेदारों के लिए बंधनकारी हों।

समुदाय सीधे अपनी खुद की परियोजना भी बना सकते हैं। परियोजना को सेट अप करने के लिए आमतौर पर तकनीकी सहायता की आवश्यकता होती है, ख़ासकर कार्बन स्टॉक की निगरानी के लिए। अगर यह कुछ ऐसा है, जिसे आप कर देखना चाहते हैं, तो मौजूदा परियोजनाओं और Plan Vivo के तहत पंजीकरण करने की प्रक्रिया पर एक नज़र डालें।

C. क्या यह क्षेत्राधिकार वाली परियोजना है?

क्षेत्राधिकार परियोजनाएं पूरे जिलों में कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए जंगलों और/या आर्द्रभूमि में भूमि उपयोग के प्रबंधन के लिए सरकार के नेतृत्व में, बड़े पैमाने पर कार्यक्रम होते हैं। अन्य REDD+ परियोजना के विपरीत, वे किसी खास साइट पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय लैंडस्केप पैमाने पर काम करते हैं। क्षेत्राधिकार वाली परियोजनाओं में कई निर्धारक विशेषताएँ होती हैं:

- **पैमाना:** क्षेत्राधिकार वाली परियोजनाएं किसी राज्य या प्रांत जैसी पूरी प्रशासनिक इकाई को कवर करती हैं और इसमें विशिष्ट परियोजनाओं की तुलना में बहुत बड़ा क्षेत्र शामिल होता है, अक्सर कई मिलियन हैक्टेयर तक। कुछ मामलों में, वे किसी देश के पूरे वन क्षेत्र को कवर कर सकते हैं।

- **सरकार की भूमिका:** इन परियोजनाओं का नेतृत्व आम तौर पर किसी सरकारी निकाय जैसे कि वन विभाग या ज़िला सरकार द्वारा किया जाता है। ये राष्ट्रीय वन या जलवायु नीतियों से सीधे संरेखित होती हैं। अलग-अलग REDD+ परियोजना के विपरीत, क्षेत्राधिकार वाली परियोजनाएं पूरे जिले में वनों की कटाई की निगरानी के आधार पर परिणामों का आकलन करती हैं, इस जोखिम को दूर करती हैं कि वनों की कटाई असल में कम होने के बजाय बस एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में विस्थापित हो जाती है।

क्षेत्राधिकार वाली परियोजनाओं का निधियन कार्बन क्रेडिट बिक्री या अन्य तरह के जलवायु फ़ाइनेंस जैसे दाताओं की निधि के ज़रिये किया जा सकता है, ख़ासकर विश्व बैंक जैसी द्विपक्षीय या बहुपक्षीय एजेंसियों से। अधिकाधिक रूप से, क्षेत्राधिकार वाली परियोजनाओं में कार्बन बाज़ार (कार्बन मार्केट) से होने वाले राजस्व के साथ क्लाइमेट फाइनेंस के अन्य रूपों का संयोजन होता है।

क्षेत्राधिकार वाली परियोजनाओं में अक्सर समुदायों की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त सुरक्षा उपाय शामिल होते हैं और इनमें स्थानीय समुदायों के साथ राजस्व-साझाकरण के लिए खास प्रतिबद्धताएं शामिल होती हैं। यह समुदायों को जुड़ने के लिए एक मज़बूत शुरुआत की जगह दे सकता है, लेकिन इससे समुदायों के लिए अपने समझौते पर बातचीत करने की जगह भी सीमित हो सकती है क्योंकि सुरक्षा उपायों और लाभों से जुड़ी नीतियां आम तौर पर पूरे जिले में उच्च स्तर पर तय की जाती हैं।

इसके अलावा, यह जानना ज़रूरी है कि कंपनियों या गैर-सरकारी संगठनों द्वारा चलाई जाने वाली कई व्यक्तिगत REDD+ परियोजनाएं क्षेत्राधिकार वाली परियोजनाओं के अंदर "नेस्टेड" होती हैं — यानी, वे ज़िला स्तर पर सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के साथ समन्वित होती हैं और ये उनमें योगदान करती हैं। यह समुदायों के लिए फ़ायदे और चुनौतियां दोनों ला सकता है, क्योंकि वे निर्णय लेने को आकार देने में हिस्सा लेते हैं।

अधिक जानने के लिए गुयाना में क्षेत्राधिकार वाले REDD+ की यह केस स्टडी देखें।

D. परियोजना से भूमि के इस्तेमाल, आजीविका और स्थानीय पारिस्थितिक तंत्रों पर क्या असर पड़ेगा?

परियोजना डेवलपर से पूछने के लिए मुख्य प्रश्न

परियोजना की गतिविधियाँ और स्थान

- परियोजना के तहत कौनसी गतिविधियाँ की जाएँगी (जैसे, वृक्षारोपण, संरक्षण क्षेत्र का निर्माण, जंगलों या आर्द्रभूमि का पुनःस्थापन)?
- परियोजना में जमीन के कौनसे इलाके शामिल किए जाएंगे?
- परियोजना की गतिविधियाँ कब शुरू होंगी और परियोजना कब तक चलेगी?

भूमि संबंधी अधिकार

- परियोजना शुरू होने के बाद कानूनी रूप से भूमि और प्राकृतिक संसाधनों का मालिक कौन होगा और उस पर नियंत्रण कौन करेगा?
- आप हमारे समुदाय में भूमि लीज़ पर लेना चाहते हैं या ख़रीदना चाहते हैं?
- हद का सीमांकन या भूमि उपयोग ज़ोनिंग कैसे की जाएगी? क्या समुदाय उन फ़ैसलों में शामिल होगा?
- क्या समुदाय के सदस्यों को परियोजना के दौरान भूमि, जंगल, पानी या अन्य प्राकृतिक संसाधनों तक पहुँच और उनका इस्तेमाल करने का अधिकार रहेगा?
- परियोजना गतिविधियों को अनुकूलित करने के लिए क्या तंत्र हैं, यदि वे सामुदायिक आजीविका या संसाधन आवश्यकताओं के साथ संघर्ष में हैं?

संसाधनों तक पहुँच पर पड़ने वाले प्रभाव

- परियोजना चराई की जगहों, जंगलों, पानी के स्थानों, खेतों या अन्य प्रमुख संसाधनों तक पहुँच को कैसे प्रभावित करेगी?
- क्या भूमि के इस्तेमाल के मौजूदा तरीकों पर कोई प्रतिबंध होगा?
- परियोजना प्लानिंग में भूमि के मौसमी इस्तेमाल (जैसे, सूखे मौसम में चराई) पर किस तरह विचार किया जाएगा?
- क्या विस्थापन या संसाधनों संबंधी संघर्ष के संभावित जोखिम हैं?
- अगर समुदाय के सदस्य कुछ संसाधनों तक पहुँच खो देते हैं, तो क्या आजीविका के कोई अन्य विकल्प या मुआवज़े का विकल्प मिलेगा?

E. परियोजना से कितना राजस्व मिलेगा?

राजस्व, परियोजना कितने कार्बन क्रेडिट उत्पन्न करती है और उन क्रेडिट का बिक्री मूल्य क्या है, इस बात से निर्धारित होता है। निश्चित समयावधि के लिए राजस्व का अनुमान या "पूर्वानुमान" लगाया जा सकता है, लेकिन पहले से यह जानने का कोई तरीका नहीं है कि किसी परियोजना से कितनी कमाई होगी। उदाहरण के लिए, अगर परियोजना गतिविधियों को लागू करने में चुनौतियां आती हैं, तो परियोजना को उम्मीद से कम कार्बन क्रेडिट मिलने की संभावना है। वैश्विक जलवायु समझौते और मीडिया कवरेज खरीदारों की मांग को कैसे प्रभावित करते हैं, इसके आधार पर कार्बन क्रेडिट के लिए बाज़ार मूल्य भी समय के साथ बदलते हैं।

इस सब के बावजूद, समुदायों के लिए किसी परियोजना से होने वाली संभावित आय का मोटा अनुमान लगाना उपयोगी होता है। आप कुछ आसान चरणों के आधार पर राजस्व का अनुमान लगा सकते हैं और इसका इस्तेमाल परियोजना डेवलपर द्वारा साझा की गई जानकारी को दोबारा जाँचने के लिए कर सकते हैं।

राजस्व = क्रेडिट की संख्या (tCO_2e) X प्रति क्रेडिट मूल्य ($)

चरण 1: पहचानें कि परियोजना से कितने कार्बन क्रेडिट बनेंगे

- पता करें कि परियोजना कितने क्रेडिट बनाने की योजना बना रहा है।

  आप परियोजना डेवलपर से इस जानकारी के लिए सीधे संपर्क कर सकते हैं। यह परियोजना दस्तावेज़ों जैसे कि व्यवहार्यता मूल्यांकन और परियोजना विवरण (जिसे आमतौर पर परियोजना डिज़ाइन दस्तावेज़ या PDD कहा जाता है) में भी शामिल किया गया होगा, जिसे परियोजना रजिस्टर करने के लिए सबमिट किया जाना आवश्यक है। tCO2e में "ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन घटाव" वाली तालिका खोजें और योग का उपयोग पूरी परियोजना अवधि के लिए करें।

चरण 2: क्रेडिट की संख्या को औसत कीमत से गुणा करें

- क्रेडिट बेचने से होने वाली संभावित कमाई का अनुमान लगाने के लिए हाल की कीमतों का इस्तेमाल करें। स्वैच्छिक कार्बन बाज़ार (कार्बन मार्केट) के लिए, पारिस्थितिक तंत्र मार्केटप्लेस की वार्षिक **स्वैच्छिक कार्बन बाज़ार (कार्बन मार्केट) की स्थिति** रिपोर्ट में परियोजना के हिसाब से औसत मूल्य शामिल होते हैं। अगर संभव हो, तो किसी खास परियोजना प्रकार (जैसे वनों की कटाई में कमी (REDD+), पुनः वनीकरण (ARR), या कृषि (ALM)) के लिए पिछले दो सालों की कीमतों की जाँच करें और सतर्क अनुमान पाने के लिए कम कीमत का इस्तेमाल करें।

	2022	2023	2024
वानिकी और भूमि उपयोग	$10.15	$10	$9.25
वनों की कटाई में कमी (REDD+)			$6
एग्रोफोरेस्ट्री			$14
बेहतर वन प्रबंधन (IFM)			$15
वनीकरण और पुनः वनीकरण (ARR)			$20
ब्लू कार्बन (मैंग्रोव, सीग्रास)			$25 से 30
कृषि	$11	$6.50	$7.50
घरेलू और सामुदायिक उपकरण (स्वच्छ चूल्हे)	$8.50	$7.75	$7.30
नवीकरणीय ऊर्जा	$4.15	$3.90	$2.70

स्वैच्छिक कार्बन बाज़ार (कार्बन मार्केट) के लिए ये कीमतें पारिस्थितिक तंत्र मार्केटप्लेस पर आधारित हैं 2023 और 2024 की रिपोर्ट।

- कुल संभावित आमदनी का अनुमान लगाने के लिए क्रेडिट की संख्या को औसत कीमत से गुणा करें।

हर परियोजना के लिए कीमतें अलग-अलग होंगी और बाज़ार की कीमतें अक्सर बदलती रहती हैं, इसलिए याद रखें कि **यह आंकड़ा आपको संभावित राजस्व का मोटा अनुमान ही देता है।**

आपके क्षेत्र में परियोजना के बिक्री मूल्य को प्रभावित करने वाली कुछ मुख्य बातों में शामिल हैं:

- **परियोजना का प्रकार:** जैसा कि ऊपर दी गई तालिका से पता चलता है, परियोजना के प्रकार के हिसाब से बिक्री मूल्य में काफी अंतर होता है, जिसमें ब्लू कार्बन परियोजना के क्रेडिट वर्तमान में सबसे ज़्यादा दामों पर बिक रहे हैं और नवीकरणीय ऊर्जा सबसे कम दामों पर बिक रही है।
- **अतिरिक्त "सह-फ़ायदे":** जैव-विविधता और/या समुदाय की भलाई पर सत्यापित सकारात्मक प्रभाव वाली परियोजनाएं ज़्यादा कीमत पर क्रेडिट बेच सकती हैं।
- **बिक्री पूर्व खरीदारी समझौते:** परियोजना डेवलपर कभी-कभी पूंजी जुटाने के लिए भावी क्रेडिट जल्दी बेच देते हैं। ये अग्रिम बिक्री आम तौर पर बहुत सस्ती कीमत पर होती हैं। यह एक कारण है कि परियोजना समझौते के हिस्से के तौर पर मार्केटिंग के दृष्टिकोण के बारे में बातचीत करना ज़रूरी है।

F. आपको किसी परियोजना के बारे में जानकारी कहाँ से मिल सकती है?

परियोजना डेवलपर, सरकारी विनियामक, और कार्बन मानक, प्रत्येक की ज़िम्मेदारी है कि वह प्रभावित समुदायों को, और कई मामलों में व्यापक जनता को भी कार्बन परियोजना के बारे में जानकारी प्रदान करे।

- **परियोजना डेवलपर से सीधे जानकारी का अनुरोध करें।** ज़्यादातर कार्बन मानकों के मुताबिक परियोजना डेवलपर प्रभावित समुदायों के साथ ज़रूरी जानकारी साझा करता है, और कई मामलों में राष्ट्रीय कानून भी करते हैं। आपको जो जानकारी चाहिए, उसे यथासंभव स्पष्ट शब्दों में पूछें।
- **परियोजना रजिस्ट्रियां।** परियोजना द्वारा उपयोग किए जाने वाली राष्ट्रीय सरकार के अधीन परियोजना रजिस्ट्रियों और कार्बन मानक की जाँच करें। आप आमतौर पर परियोजना दस्तावेज़ों को सीधे कार्बन मानकों की रजिस्ट्री पर ऐक्सेस कर सकते हैं। Verra (VCS स्टैंडर्ड), Gold Standard, और ART-TREES सभी अपनी सार्वजनिक रजिस्ट्रियों पर परियोजना के विवरण, निगरानी रिपोर्ट और परियोजना के सत्यापन वक्तव्य प्रकाशित करते हैं।[4] अगर आपको नहीं पता कि परियोजना किस कार्बन मानक के साथ रजिस्टर कर रही है, तो इन तीन रजिस्ट्रियों की जाँच करके शुरुआत करें।

4 Verra रजिस्ट्री https://registry.verra.org/app/search/VCS/All%20Projects पर उपलब्ध है, Gold Standard रजिस्ट्री https://registry.goldstandard.org/projects?q=&page=1 पर उपलब्ध है, और ART-TREES रजिस्ट्री https://art.apx.com/myModule/rpt/myrpt.asp?r=111 पर है (ART-TREES आपकी जिसमें रुचि हो उस परियोजनाओं के दस्तावेज़ों के नीचे "View" क्लिक करें)।

- **परियोजना डिज़ाइन दस्तावेज़:** यह परियोजना संचालन और परियोजना डेवलपर के द्वारा ज़रूरी सुरक्षा उपायों को पूरा करने के लिए उठाए गए कदमों का पूरा विवरण है। डेवलपर जब अपनी परियोजना रजिस्टर करने के लिए आवेदन करते हैं, तब कार्बन मानक उनके लिए यह दस्तावेज जमा कराना अनिवार्य बनाते हैं। इस चरण में खोजने के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज़ है। इसमें परियोजना डेवलपर और कोई भी कार्यान्वयस साझीदरों, परियोजना की गतिविधियों, स्थान और कुल क्षेत्रफल, भूमि उपयोग, भूमि अधिकारों और समुदायों पर पड़ने वाले प्रभावों और परियोजना से मिलने वाली क्रेडिट की संख्या के बारे में जानकारी शामिल होगी।
- **निगरानी और सत्यापन रिपोर्ट:** जो परियोजनाएं पहले से काम कर रही हैं, उनके लिए परियोजना डेवलपर द्वारा सबमिट की गई मॉनिटरिंग रिपोर्ट से आज तक की गई कार्रवाइयों का विवरण मिलता है। तृतीय पक्ष ऑडिटर की सत्यापन रिपोर्ट, निगरानी रिपोर्ट की सटीकता की समीक्षा करती है और कार्बन मानक द्वारा निर्धारित आवश्यकताओं के अनुसार परियोजना के अनुपालन में किसी भी कमी या समस्या की पहचान करती है।
- **जारी करने के रिकॉर्ड:** हर सत्यापन के बाद, कार्बन मानक निगरानी रिपोर्ट और ऑडिट के आधार पर क्रेडिट जारी करेगा। जारी करने के रिकॉर्ड बताते हैं कि परियोजना ने आज तक कितने क्रेडिट अर्जित किए हैं। कुछ रजिस्ट्रियों में, जारी करने के रिकॉर्ड में यह जानकारी भी शामिल होती है कि कितने क्रेडिट बेचे गए हैं।

- **सूचना का अनुरोध करने का अधिकार।** परियोजना से जुड़े मुख्य दस्तावेज़ों तक पहुँच का अनुरोध करने के लिए राष्ट्रीय कानूनों और नीतियों का इस्तेमाल करें, जिसमें परियोजना प्रस्ताव और सरकार द्वारा दिया गया कोई भी प्रचालन लाइसेंस या परमिट शामिल हैं। कुछ मामलों में, हो सकता है कि आपको परियोजना डेवलपर के कॉर्पोरेट पंजीकरण और आवश्यकता होने पर पर्यावरणीय प्रभाव का आकलन करने के लिए अतिरिक्त दस्तावेज़ों का अनुरोध करना हो।

  आप बस उपयुक्त विनियामक एजेंसी, जो अक्सर पर्यावरण मंत्रालय का कोई विभाग होती है, से संपर्क करके शुरुआत कर सकते हैं। अगर आपके देश में कार्बन ट्रेडिंग संबंधी कोई नीति है, तो वह उस संस्था की पहचान करेगी, जो कार्बन परियोजना की समीक्षा करने और उन्हें मंज़ूरी देने के लिए ज़िम्मेदार है (जिसे अक्सर "नामित राष्ट्रीय प्राधिकरण" कहा जाता है)।

अगर आपको कोई जवाब नहीं मिलता है, तो अपने देश में राष्ट्रीय कानूनों के तहत परिभाषित प्रक्रिया का इस्तेमाल करके सूचना के अधिकार का औपचारिक अनुरोध दर्ज करें। सामान्यतः यह संबंधित एजेंसी को एक पत्र का रूप लेता है जिसमें आप जो विशिष्ट जानकारी माँग रहे हैं उसका विवरण शामिल होता है (उदाहरण के लिए परियोजना विवरण दस्तावेज, एजेंसी द्वारा जारी की गई स्वीकृतियाँ या पंजीकरण दस्तावेज, EIAs, आदि)।

- **मीडिया रिपोर्ट।** आखिरकार, परियोजना और परियोजना डेवलपर के बारे में कोई भी मीडिया लेख या प्रेस विज्ञप्ति खोजना भी एक अच्छा विचार है। परियोजना डेवलपर के ट्रैक रिकॉर्ड के बारे में जानकारी पाने का यह एक अच्छा तरीका है — क्या उनका सार्वजनिक शिकायत या विवाद का इतिहास रहा है? अगर वे कहीं और कोई अन्य परियोजना चला रहे हैं, तो हो सकता है आप उन स्थानों पर समुदायों या नागरिक समाज संगठनों से संपर्क कर के परियोजना कैसे चल रही है और उनके सामने कौनसी चुनौतियाँ आई हैं उस बारे में जानकारी पा सकें।

हमेशा लिखित रूप में जानकारी का अनुरोध करें और भविष्य के संदर्भ के लिए अपने पास प्रतियाँ रखें। अगर आपको ज़रूरी जानकारी खोजने में मुश्किल हो रही है, तो सहायता के लिए सिविल सोसायटी संगठनों से संपर्क करने पर विचार करें।

III. एक समुदाय के रूप में संगठित होना

यह तय करना कि किसी निवेशक को सामुदायिक भूमि का इस्तेमाल करने की अनुमति दी जाए या नहीं, यह समुदाय के सबसे महत्वपूर्ण फ़ैसलों में से एक है। यह देखते हुए कि यह आने वाले सालों में आपकी भूमि और संसाधनों को प्रभावित करेगा, इसके लिए समुदाय के सभी लोगों के बीच सावधानी से सोच-विचार और विचार-विमर्श करने की ज़रूरत है। ये ऐसे फ़ैसले नहीं हैं, जिन्हें समुदाय के नेता विस्तृत विचार सभा के बिना ख़ुद कर सकते हैं।

सामूहिक चर्चा और विचार-विमर्श के लिए फ़ोरम आयोजित करें, जहाँ समुदाय के अलग-अलग सदस्य किसी निवेशक के साथ समझौता करने के जोखिमों और संभावित लाभों पर विचार करने के लिए इकट्ठा हो सकते हैं। इन विचार-विमर्श में वे सभी लोग शामिल होने चाहिए जो संबंधित भौगोलिक क्षेत्र में स्थायी रूप से रहते हैं और काम करते हैं और जिनके पास ऐतिहासिक ऐक्सेस अधिकार हैं — जिनमें महिलाएं, पुरुष, युवा, बुजुर्ग, अलग-अलग आजीविका समूह और जातीय या धार्मिक अल्पसंख्यक समूहों के सदस्य शामिल हैं।

प्रभावी संगठन के लिए मुख्य तत्व

समुदाय का एकजुट दृष्टिकोण

जब आप पूरी बातचीत के दौरान संयुक्त मोर्चा पेश करते हैं, तो बेहतर तरीके से आप अपने लक्ष्य हासिल कर पाते हैं। उन साझा लक्ष्यों पर सहमत होने के लिए साथ आएं, जिन्हें आप सामूहिक रूप से पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

समावेशी प्रतिनिधित्व

यह पक्का करने के लिए खास कदम उठाएं कि महिलाओं, युवाओं, मूल निवासी लोगों और किसी भी जातीय या धार्मिक अल्पसंख्यक समूह को फ़ैसला लेने में पूरी तरह से शामिल किया जाए। इससे सभी दृष्टिकोणों पर विचार किया जाए और एकता बनाए रखने में मदद होगी।

बातचीत के लिए स्पष्ट उद्देश्य

बातचीत के लिए अपने लक्ष्यों को परिभाषित करें — आपके समुदाय की मुख्य माँगें और जिस पर आप समझौता नहीं करेंगे वे मुद्दे कौनसे हैं? अगर आप इन्हें स्पष्ट रूप से व्यक्त करते हैं, तो आप परियोजना डेवलपर को सक्रिय प्रस्ताव दे सकते हैं और किसी भी ऑफ़र का आकलन करने के लिए इन बिंदुओं का इस्तेमाल कर सकते हैं।

सक्षम वार्ताकार

अलग-अलग दृष्टिकोणों का प्रतिनिधित्व करने वाले विश्वसनीय समुदाय सदस्यों की एक वार्ता टीम बनाएं जो परियोजना डेवलपर के साथ बातचीत का नेतृत्व करेगी। यह टीम जानकारी साझा करने और व्यापक समुदाय के साथ सामूहिक रूप से निर्णय लेने के लिए ज़िम्मेदार भी हो सकती है।

भविष्य के लिए अपनी प्राथमिकताओं और परिकल्पना को परिभाषित करें

भूमि सामुदायिक परिकल्पना यह तय करने में मदद कर सकती है कि आप अपनी भूमि और संसाधनों का इस्तेमाल कैसे करना चाहते हैं। फिर आप बाहरी कार्रवाई करने वालों के साथ, उनकी प्रस्तावित योजनाएँ आपकी परिकल्पना का समर्थन करती हैं या नहीं इसके आधार पर कोई भी संबंध बनाने के बारे में निर्णय ले सकते हैं।

परिकल्पना अभ्यास

समुदाय के सदस्यों को अपनी आँखें बंद करके ये सोचने के लिए आमंत्रित करें कि वे 30 या 50 वर्षों में अपने पोते-पोतियों के लिए अपना समुदाय कैसा चाहते हैं। चर्चा के लिए प्रेरित करने वाले कुछ सवालों में शामिल हो सकते हैं:

- भूमि प्रदेश कैसा दिख रहा है? पानी, मिट्टी और हवा की गुणवत्ता कैसी है? कौनसे प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध हैं?
- लोग अपनी आजीविका कैसे चला रहे हैं?
- समुदाय में किस तरह की अवसंरचना या सार्वजनिक सेवाएँ मौजूद हैं?
- समुदाय में लोग कैसे साथ रह कर और साथ मिलकर काम करते हैं?
- क्या लोग प्रथागत संस्कृतियों और परम्पराओं का अनुसरण करते हैं?

हर किसी को सोचने के लिए कुछ समय दें और फिर लोगों से अपनी कल्पना साझा करने के लिए कहें। लोग जो साझा करें उसे कागज़ के ब्रडे टुकड़ों पर लिख लें। साथ मिल कर हर व्यक्ति ने भविष्य के लिए साझा किए सपनों में मौजूद सामान्य विषय वस्तु की चर्चा करें। उन खास साझा प्राथमिकताओं को पहचानना शुरू करें, जो भविष्य के लिए समुदाय के लक्ष्यों को पूरा करती हैं।

यह करते समय, याद रखें कि समुदाय में विविधता है। सुनिश्चित करें कि हर सामाजिक समूह — जिसमें महिलाएं, युवा, मौसमी भूमि उपयोगकर्ता और कोई भी अन्य अल्पसंख्यक समूह शामिल हैं — को अपने दृष्टिकोण साझा करने का मौका मिले। अलग-अलग दृष्टिकोणों के बारे में खुलकर बात करें और मतभेदों को दूर करके काम करने के लिए ,समय ले ताकि वह प्राथमिकतायें तैयार की जा सके जो सभी समूहों के हितों को दर्शाती है।

एक लंबी दृष्टि अभ्यास के लिए जो समुदाय के इतिहास से शुरू होता है और समय के साथ सामुदायिक भूमि कैसे बदल गई है, देखें इस मार्गदर्शिका में पृष्ठ 14।

एक बार आपके पास सामुहिक परिकल्पना हो, तो इसे लागु करने के लिए आप जो करेंगे उन महत्वपूर्ण कार्रवाइयों को परिभाषित करें। एक सामुदायिक कार्य योजना — जिसमें भूमि उपयोग की योजना और संसाधनों को सामुहिक रूप से प्रबंधित करने के लिए सामुदायिक नियम या उपनियम शामिल हैं — निवेशकों और सरकारी अधिकारियों को यह स्पष्ट कर सकती है कि समुदाय का अपने भविष्य के लिए अपना दृष्टिकोण है और किसी भी बाहरी निवेश को समुदाय की प्राथमिकताओं और मौजूदा योजनाओं का समर्थन करना चाहिए।

तय करें कि आपको बातचीत में शामिल होना है या नहीं

समुदाय के सदस्य कंपनी और उसके प्रस्तावित निवेश के बारे में सभी ज़रूरी जानकारी की समीक्षा कर लें, तो उन्हें परियोजना डेवलपर के साथ समझौते के लिए बातचीत करनी है या नहीं, यह तय करने के लिए सामुदायिक विचार-विमर्श करना होगा। यह निर्णय लेते समय, निम्नलिखित पर वापस जाएँ और सोचें:

- भविष्य के लिए समुदाय की परिकल्पना
- भूमि के उपयोग के लिए मौजूदा सामुदायिक नियम और/या भूमि उपयोग योजनाएं
- राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय क़ानून के तहत आपके अधिकार
- प्रस्तावित निवेश के बारे में जानकारी, जिसमें संभावित सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव शामिल हैं

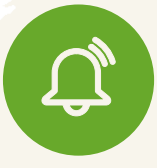

अगर समुदाय यह तय करता है कि उसे अपनी भूमि पर कार्बन परियोजना नहीं चाहिए, तो आपको परियोजना डेवलपर के साथ अनुबंध करने से इन्कार करने का हक़ हो सकता है। समुदाय परियोजना के लिए अपनी सहमति रोककर ऐसा कर सकता है। सहमति से इनकार किए जाने का दस्तावेजीकरण किया जाना चाहिए और परियोजना डेवलपर को लिखित रूप में सूचित किया जाना चाहिए। अगर परियोजना डेवलपर या सरकार समुदाय के फ़ैसले को स्वीकार करने से इनकार करते हैं, तो सामुदायिक पैरालीगल और वकील परियोजना का विरोध जारी रखने के लिए आपकी सहायता कर सकते हैं।

ऐसे मामलों में, संभावित रणनीतियों में ये शामिल हो सकते हैं:

- राष्ट्रीय सरकार और कार्बन मानक द्वारा परियोजना **स्वीकृतियाँ प्रदान करने की प्रक्रिया में हिस्सा लेना** इन प्रक्रियाओं में अक्सर प्रभावित अधिकार धारकों और अन्य लोगों के लिए चिंता जताने और परियोजना के बारे में सुझाव देने के अवसर शामिल होते हैं। कार्बन परियोजना के लिए, प्रमाणन निकाय को परियोजना रजिस्ट्रेशन से पहले और परियोजना के संचालन के दौरान नियमित अंतराल पर स्वतंत्र ऑडिट की ज़रूरत होती है। समुदाय के विरोध को व्यक्त करने और स्वतंत्र, पूर्व, सूचित सहमति के उल्लंघनों की शिकायत करने के लिए ये बहुमूल्य अवसर हैं।
- सामुदायिक अधिकारों के उल्लंघन **की शिकायत करने के लिए शिकायत तंत्र का इस्तेमाल करना।** इनमें परियोजना का नेतृत्व करने वाली कंपनी के आंतरिक तंत्र और साथ ही कार्बन मानक द्वारा स्थापित तंत्र शामिल हैं। कार्बन मानक को प्रस्तुत की गयी शिकायतों से अक्सर इस बात की समीक्षा होती है कि परियोजना डेवलपर ने सामुदायिक भूमि अधिकारों पर पर्याप्त विचार किया है और स्वतंत्र, पूर्व और सूचित सहमति हासिल की है या नहीं।
- परियोजना डेवलपर और/या सरकारी एजेंसियों के खिलाफ **कानूनी कार्रवाई** ,सामुदायिक भूमि अधिकारों को मजबूत करने या औपचारिक बनाने के लिए, समुदाय के स्वतंत्र, पूर्व और सूचित सहमति के अधिकार को पहचानना; और/या परियोजना को मंजूरी देने या संचालित करने की अनुमति देने के लिए सरकारी नियामकों के निर्णयों को चुनौती देती है।
- समुदाय की चिंताओं और परियोजना के प्रति विरोध के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए **वकालत अभियान** परियोजना डेवलपर और सरकार पर जवाब देने के लिए दबाव पैदा कर सकते हैं।
- **सीधी कार्रवाई** जैसे मार्च, विरोध प्रदर्शन, पिकेट लाइन, या अन्य कार्रवाइयाँ जिन्हें समुदाय की शिकायतों को सार्वजनिक करने के लिए और, कुछ परिस्थितियों में, परियोजना संचालन को शारीरिक रूप से रोकने या उनमें देरी करने के लिए की जाती है।

अगर समुदाय परियोजना डेवलपर के साथ बातचीत करने का फ़ैसला करता है, तो बातचीत के लिए अपने उद्देश्यों (या अपनी मांगों) को परिभाषित करके और बातचीत करने वाली ऐसी टीम का चयन करके तैयारी जारी रखें, जो समुदाय के भीतर सामूहिक निर्णय लेने की सुविधा प्रदान कर सके और आपकी ओर से परियोजना डेवलपर के साथ बातचीत कर सके।

बातचीत में शामिल होने का मतलब यह **नहीं है** कि समुदाय ने निवेशक को सामुदायिक भूमि का इस्तेमाल करने की अनुमति दी है और न ही यह वादा किया है कि कोई समझौता किया जाएगा। इसके बजाय, यह परियोजना डेवलपर के साथ औपचारिक रूप से जुड़ने की प्रक्रिया शुरू करता है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि आप परियोजना के आगे बढ़ने की शर्तों पर पारस्परिक रूप से सहमत हो सकते हैं या नहीं। यह समुदाय के लिए परियोजना के लिए योजना तैयार करने और सामुदायिक भूमि के इस्तेमाल के बदले विशेष लाभों की मांग करने का एक अवसर है। अगर आप परियोजना डेवलपर के साथ शर्तों पर सहमत हो सकते हैं, तो इन्हें एक अनुबंध में औपचारिक रूप दिया जाएगा, जिस पर दोनों पक्ष हस्ताक्षर करेंगे। अगर आप शर्तों पर सहमत नहीं हो पाते हैं, तो समुदाय ना कह सकता है और परियोजना के साथ आगे बढ़ने से मना कर सकता है।

जब बातचीत निष्पक्षता से की जाती है, तो एक कार्बन परियोजना भविष्य के लिए समुदाय की परिकल्पना को आगे बढ़ाने के अवसर पेश कर सकती है। तथापि, बातचीत में सत्ता और जानकारी तक पहुँच में बड़ा असंतुलन शामिल होता है। बातचीत न्यायोचित हो यह सुनिश्चित करने के लिए समुदाय को अनुभवी कानूनी और तकनीकी सहायता की ज़रूरत हो सकती है। आखिरी सेक्शन में हम बातचीत की तैयारी में सामुदायिक पैरालीगल और वकील जो सहायता दे सकते हैं, उस पर नज़र डालेंगे।

A. बातचीत करने वाली टीम बनाएं

सामूहिक हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए ज़िम्मेदार बातचीत करने वाली टीम का चयन करने से आपको पूरी बातचीत के दौरान और व्यवस्थित और रणनीतिक तरीके से जुड़ने में मदद मिल सकती है। बातचीत करने वाली टीम के ज़रिए काम करने के कई फ़ायदे हैं:

- **एक आवाज़ से बोलना।** बातचीत करने वाली टीम साझा प्राथमिकताओं के बारे में पूरे समुदाय में सहमति को बढ़ावा दे सकती है। फिर वे परियोजना डेवलपर्स को एक स्पष्ट सामूहिक दृष्टिकोण पेश कर सकते हैं।
- **जटिल समस्याओं को समझना।** कार्बन परियोजना में कई जटिल कानूनी, तकनीकी और वित्तीय समस्याएं शामिल होती हैं। बातचीत करने वाली टीम तथ्य खोजने का फायदा उठा कर सलाहकारों के साथ मिलकर इन समस्याओं को समझकर समुदाय को समझा सकती है।
- **सौदेबाजी की शक्ति बनाना।** बातचीत करने वाली टीम पूरे समुदाय (या समुदायों) में सामूहिक कार्रवाई कर सकती है और उन बेहतर शर्तों पर ज़ोर दे सकती है जो पूरे समुदाय के हितों का प्रतिनिधित्व करती हैं।
- **जारी संचार और जानकारी साझाकरण को पोषित करना।** बातचीत करने वाली टीम को समुदाय को नियमित रूप से अपडेट करने, फ़ीडबैक इकट्ठा करने और फ़ैसलों के लिए सामूहिक सहायता की पुष्टि करने का काम सौंपा जा सकता है।

बातचीत करने वाली टीम को सामूहिक रूप से चुना जाना चाहिए, ताकि यह पक्का हो सके कि समुदाय की ओर से बातचीत करने के लिए उन्हें स्पष्ट आदेश मिला है। बातचीत करने वाली टीम तैयार करने के लिए यहां कुछ चरण दिए गए हैं:

1. **टीम की आवश्यकता पर सहमति स्थापित करें।** बातचीत करने वाली टीम क्यों ज़रूरी है, इस पर चर्चा करने के लिए एक खुली सामुदायिक मीटिंग आयोजित करें। टीम की भूमिका पर सहमति करें - पहरेदारों के रूप में नहीं, बल्कि प्रतिनिधि और समुदाय और बाहरी कार्रवाई करने वालों के बीच में एक पुल के रूप में। यह बातचीत में सामुदायिक लक्ष्यों को फिर से बताने और उन चिंताओं की पहचान करने का भी समय हो सकता है, जिनका समाधान बातचीत के दौरान सावधानी से किया जाना चाहिए।
2. **टीम को मिले अधिकारों और ज़िम्मेदारियों को स्पष्ट करें।** टीम की खास ज़िम्मेदारियों को परिभाषित करें, उदाहरण के लिए, सामूहिक प्राथमिकताओं की पहचान करने के लिए सामुदायिक विचार-विमर्श की सुविधा देना, उन चर्चाओं के आधार पर प्रस्तावित शर्तों का ड्राफ़्ट तैयार करना, परियोजना डेवलपर के साथ मीटिंग के दौरान समुदाय का प्रतिनिधित्व करना और व्यापक समुदाय को वापस रिपोर्ट करना। उनकी भूमिका सामूहिक निर्णय लेने की प्रक्रिया का नेतृत्व करना है, न कि एकतरफा फ़ैसले लेने की।
3. **अच्छे वार्ताकारों के लिए मापदंड तय करें।** किसी वार्ताकार के लिए आपका प्रभावी ढंग से प्रतिनिधित्व करने के लिए कौनसे मापदंड ज़रूरी होते हैं? सामुदायिक मीटिंग में भाग लेने वालों से महत्वपूर्ण खूबियों या विशेषताओं के बारे में बात करने के लिए कहें। उनका इस्तेमाल बातचीत करने वाली टीम को चुनने में मदद करने के लिए करें।

   एक उदाहरण के तौर पर, बोनथे, सिएरा लियोन के समुदायों ने नेतृत्व के महत्वपूर्ण पहलुओं जैसे कि ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और समुदाय के सभी समूहों के द्वारा भरोसा किया जाना पर ध्यान केंद्रित किया था। आप प्रसांगिक विषयों (जैसे भूमि का संचालन और उपयोग) की जानकारी, बाहरी कार्रवाई करने वालों से मीटिंग में आवाज़ उठाने में सहजता और टीम के कम से कम कुछ सदस्यों के लिए साक्षरता के बारे में भी सोचना चाह सकते हैं।

   महिलाओं और ऐसे अन्य समूहों को शामिल करना और उनका प्रतिनिधित्व करना सुनिश्चित करें, जो निर्णय लेने की प्रक्रिया से छूट सकते हैं। बातचीत करने वाली टीम में महिलाओं के लिए निर्धारित संख्या या अनुपात के लिए सहमति करना मददगार हो सकता है। सिएरा लियोन में, समुदायों ने आवश्यक बनाया था कि कम से कम 30% सदस्य महिलाएँ हों।

4. **टीम चुनने के लिए पारदर्शी प्रक्रिया का इस्तेमाल करें।** ऐसा तरीका इस्तेमाल करें जो आपके समुदाय के लिए कारगर हो - जैसे चुनाव, आम सहमति से चयन, या नामांकन के बाद समुदाय की स्वीकृति। टीम चुनते वक़्त यह सुनिश्चित करें कि प्रक्रिया खुले तौर पर और पारदर्शी रूप से की गयी हो और बातचीत करने वाली टीम के विभिन्न सदस्यों के बीच कौशल के संतुलन का लक्ष्य रहे।
5. **परिभाषित करें कि बातचीत करने वाली टीम जानकारी कैसे साझा करेगी और व्यापक इनपुट कैसे प्राप्त करेगी।** साझा बातचीत करने वाली टीम समुदाय को जवाबदेह रहे यह सुनिश्चित करने के लिए आपको बातचीत करने वाली टीम परियोजना डेवलपर के प्रस्तावों को कैसे वापस रिपोर्ट करेगी और प्रमुख चरणों में निर्णय लेने की प्रक्रिया में किस तरह से विस्तृत समुदाय को शामिल करेगी यह भी परिभाषित करना चाहिए। साथ मिलकर इस बारे में चर्चा करें:

    - बातचीत करने वाली टीम अपने दम पर कौनसे फ़ैसले ले सकती है? सामूहिक फ़ैसला लेने के लिए किन मुद्दों को पूरे समुदाय के पास वापस लाने की ज़रूरत है?
    - बातचीत करने वाली टीम कितनी बार और किन फ़ोरम में, प्रगति के बारे में समुदाय के सदस्यों को अपडेट करेगी और उनकी राय लेगी?

बातचीत करने वाली टीम के सदस्यों को प्रभावी होने के लिए किन कौशलों की ज़रूरत होती है?

- धैर्य और ज़रूरत पड़ने पर प्रक्रिया को धीमा करने की क्षमता
- दूसरों के विचार सुनना
- समुदाय के लक्ष्यों को आगे बढ़ा सके ऐसे विकल्पों और वैकल्पिक व्यवस्थाएं खोजने का लचीलापन
- व्यापक समुदाय को प्रस्ताव समझाने की क्षमता
- अपनी बात कहने और समुदाय के हितों का प्रतिनिधित्व करने का भरोसा
- दूसरों के साथ तालमेल बिठाने और एक टीम के तौर पर काम करने की क्षमता
- तनाव का सामना करने में सहजता और आवश्यकता पड़ने पर संघर्ष को शांत करने की क्षमता
- एक संभवतः लंबी प्रक्रिया के दौरान टीम और समुदाय में वेग बनाए रखने की क्षमता

B. सामूहिक रूप से बातचीत करने के लिए प्रतिबद्ध होना

ज़्यादातर कार्बन परियोजना एकाधिक समुदायों को प्रभावित करते हैं। इससे संगठन अधिक चुनौतिपूर्ण हो सकता है, तथापि यह समुदायों को सामूहिक शक्ति बनाने का अवसर भी प्रदान करता है। अगर समुदाय अलग-अलग होने के बजाय एकजुट तरीके से बातचीत करते हैं, तो वे ज़्यादा मज़बूत स्थिति में होते हैं।

जब एक ही परियोजना से कई अलग-अलग समुदाय प्रभावित होते हैं, तो सबसे अच्छा होता है कि एक ही बातचीत करने वाली टीम हो, जिसमें हर समुदाय के प्रतिनिधि शामिल हों। अगर परियोजना में एक बड़े क्षेत्र में अनेक समुदाय शामिल हैं, तो समुदायों को समूह बनाकर संयोजन को सुगम बनाना और विचार-विमर्श को बातचीत की गति पर चलने देना भी उपयोगी हो सकता है। पड़ोसी समुदायों का हर समूह, साथ मिल कर हर समूह की प्राथमिकताओं पर सहमत हो सकता है। इसके बाद बातचीत करने वाली टीम की भूमिका एक एकीकृत दृष्टिकोण विकसित करने की है, जिसे सभी समुदाय साथ मिलकर आगे बढ़ा सकते हैं।

बातचीत के दौरान संवाद जारी रखने के लिए, जानकारी साझा करने और समन्वय करने के लिए कई तरीकों का इस्तेमाल करने पर विचार करें। इसमें ये शामिल हो सकते हैं:

- WhatsApp या Signal ग्रुप चैट के ज़रिए नियमित रूप से संचार करना
- अलग-अलग कामों के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों की पहचान करना
- जब निर्णय लिए जाने हों तब महत्वपूर्ण समयों पर आमने-सामने मीटिंग का उपयोग करना

आप हर समुदाय के मौजूदा नेताओं या संस्थानों को भी ज़िम्मेदारी सौंप सकते हैं, कि वे बातचीत करने वाली टीम के साथ समन्वय करें और उनकी मदद करें। उदाहरण के लिए, हो सकता है कि वे अपने समुदाय में विचार-विमर्श आयोजित करें और बातचीत करने वाली टीम को प्राथमिकताएं या सुझाव पहुँचाएं। इसी तरह, वे बातचीत करने वाली टीम की जानकारी वापस अपने समुदाय के साथ साझा करने में मदद कर सकते हैं।

सामूहिक सौदेबाजी की ताकत

नॉर्दर्न केन्या रेंजलैंड्स कार्बन परियोजना (NKRCP), दुनिया की सबसे बड़ी सॉइल कार्बन परियोजना, एक 30 साल की परियोजना है जो 2013 में शुरू हुई थी। परियोजना के पहले दशक में स्थानीय समुदायों को कई फ़ायदे मिले, जिसमें चराई की भूमि में सुधार करना और समुदायों के लिए 14 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का राजस्व प्राप्त करना शामिल था, परियोजना में शामिल समुदायों के मन में भी सवाल और चिंताएं थीं कि परियोजना रोज़ाना कैसे काम कर रही है।

2023 में, सामुदायिक भूमि प्रबंधन समितियां (CLMC), जो उस सामुदायिक भूमि, जिस पर परियोजना हो रही है, को नियंत्रित करती हैं, परियोजना के प्रस्तावक, नॉर्दर्न रेंजलैंड्स ट्रस्ट (NRT) से परियोजना के बारे में और जानकारी मांगने के लिए एक साथ आईं। 15 CLMC और सामुदायिक संरक्षण, जो परियोजना के तहत संरक्षण और चराई क्षेत्रों का प्रबंधन करते हैं, ने साथ में परियोजना के चल रहे कार्यान्वयन में उन मांगों का एक सेट विकसित किया, जिन पर ध्यान दिया जाना चाहिए। उन्होंने NRT को एक पत्र ड्राफ़्ट किया और प्रत्येक सामुदायिक समिति से हस्ताक्षर लिए। अपने पत्र में, उन्होंने उन चुनिंदा CLMC के साथ जुड़ाव की मांग की, जिनके पास सामुदायिक भूमि के बारे में निर्णय लेने का कानूनी अधिकार है; मौजूदा संविदा तक पहुँच और कार्बन क्रेडिट सेल्स से होने वाले राजस्व के बारे में जानकारी; और परियोजना समझौते पर फिर से बातचीत की मांग की।

तीन हफ़्ते बाद, नेताओं के फ़ॉलो-अप पत्र के जवाब में, प्रस्तावक ने परियोजना कार्यान्वयन समझौता (PIA) साझा किया, जिस पर 2021 में हस्ताक्षर किए गए थे। किसी भी सामुदायिक नेता ने समझौता पहली ही बार देखा था। NRT ने बताया कि मूल समझौता आने वाले साल में समाप्त होगा और उन्होंने समुदायों को एक नए समझौते पर बातचीत करने के लिए आमंत्रित किया था। इस आमंत्रण ने परियोजना क्षेत्र के अन्य समुदायों को बातचीत करने वाली टीम में शामिल होने के लिए प्रेरित किया, जिससे भाग लेने वाले समुदायों की कुल संख्या 28 हो गई।

बातचीत करने वाली टीम ने कई मीटिंग्स बुलाई, जिसमें नए PIA की मांगों के एक साझा मंच पर सहमति बनाने के लिए परियोजना क्षेत्र के सभी CLMC और कंज़र्वेंसी बोर्ड को एक साथ लाया गया। उनकी मुख्य मांगों में परियोजना के लिए पूर्ण पारदर्शिता और अनुबंधों और वित्तीय रिकॉर्ड तक पहुंच,

हस्ताक्षरकर्ताओं के रूप में समुदायों के साथ एक समर्पित परियोजना बैंक खाता जिसमें कार्बन क्रेडिट बिक्री से सभी राजस्व जमा किए जाएं, और एक नई राजस्व-साझाकरण व्यवस्था जिसने समुदायों को भूस्वामियों और परियोजना के कार्यान्वयनकर्ताओं के रूप में उनकी भूमिका को देखते हुए अधिकांश राजस्व दिया जाये, ये सब मांगे शामिल थी। उन्होंने एक नई शासन संरचना भी प्रस्तावित की थी जिसमें परियोजना में शामिल सभी CLMC और कंज़र्वेंसियों के प्रतिनिधि शामिल होंगे, साथ ही यह भी आवश्यक बनाया गया था कि मार्केटर्स के साथ किसी भी तीसरे पक्ष के ठेके हस्ताक्षरित किए जाने से पहले समुदायों द्वारा मंज़ूरी दी जाए।

इससे भाग लेने वाले सभी समुदायों के निर्वाचित नेताओं की सहभागिता के साथ फिर से बातचीत की प्रक्रिया शुरू हुई। इसने परियोजना के लिए स्वतंत्र, पूर्व, सूचित सहमति का नवीनीकरण करने की प्रक्रिया भी शुरू की, जिसमें नए संविदा की शर्तों को मंज़ूरी दी जाए या नहीं यह तय करने में समुदाय सदस्यों की व्यापक भागीदारी थी।

कार्बन परियोजना से जुड़ने की तैयारी करते समय चेकलिस्ट

☐ **क्या हमारे भूमि अधिकार औपचारिक रूप से मान्य किये गए है?**

- **[हाँ]** परियोजना डेवलपर के साथ जुड़ने के लिए योजना बनाने के लिए आगे बढ़ें
- **[नहीं]** पहले चरण के तौर पर अपने भूमि अधिकारों के दस्तावेजीकरण के लिए सहायता प्राप्त करें

☐ **क्या हमारे पास परियोजना के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी, जिसमें परियोजना का प्रस्तावक कौन है, प्रस्तावित गतिविधियाँ, स्थानीय पारिस्थितिक तंत्र और सामुदायिक अधिकारों पर संभावित प्रभाव आदि शामिल हैं,**

- **[हाँ]**
- **[नहीं]** आपको अब भी जिस जानकारी की ज़रूरत हो उसकी सूची बनाएं और इसे पाने की योजना बनाएं।

☐ **क्या हमारे पास स्वतंत्र, पूर्व, सूचित सहमति प्रोटोकॉल है?**

- **[हाँ]** बातचीत में मार्गदर्शन करने के लिए प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करें, जिसमें परियोजना डेवलपर से बात करना भी शामिल है कि समुदाय कैसे फ़ैसले लेता है
- **[नहीं]** FPIC प्रोटोकॉल को विकसित करें या जो सामूहिक विचार-विमर्श और निर्णय लेने के लिए मौजूदा प्रक्रियाएं है उन्हें अपनाये। हम अगले सेक्शन में और सुझाव और उदाहरण दे रहे हैं।

IV. बाहर से कानूनी सहायता प्राप्त करना

समुदाय अपने दम पर सफलतापूर्वक बातचीत करने के लिए सामूहिक रूप से संगठित हो सकते हैं, लेकिन कानूनी अनुबंध के तकनीकी पहलू और समुदायों और परियोजना डेवलपर के बीच शक्ति के असंतुलन को देखते हुए, इस प्रक्रिया के कुछ चरणों के लिए सहायता प्राप्त करना अक्सर मददगार होता है। तथ्यों का पता लगाने के दौरान, ऑफ़र का मूल्यांकन करते समय, और समझौते या समझौते के मसौदे की अंतिम समीक्षा के लिए, यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह लागू करने योग्य है और मौजूदा कानूनों के अनुरूप है, कानूनी परामर्शदाता या मौजूदा सहयोगियों के साथ काम करना ख़ास तौर पर महत्वपूर्ण हो सकता है।

अगर आप बातचीत के दौरान किसी वकील या दूसरे साझीदारों के साथ काम करते हैं, तो पहले से पहचान लें कि आपको क्या मदद चाहिए और यह तय करें कि आप साथ काम कैसे करेंगे। यहां कुछ तरीके दिए गए हैं जिनसे समुदाय के नेता बाहरी वकीलों के साथ काम कर सकते हैं:

- सामुदायिक वार्ताकार टीम, बातचीत के दौरान समुदायों के लक्ष्यों और दृष्टिकोण की व्याख्या करती है। व्यापक समुदाय के साथ जानकारी साझा करने और समझौते की शर्तों पर अंतिम निर्णय लेने के लिए सामुदायिक विचार-विमर्श को सुविधाजनक बनाने में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है।
- सामुदायिक पैरालीगल कानूनी प्रक्रिया के बारे में मार्गदर्शन दे सकते हैं और सत्ता के स्थान से सौदेबाज़ी करने के लिए सामूहिक रूप से संगठन करने में सहायता प्रदान कर सकते हैं। वे अक्सर समुदायों की जानकारी इकट्ठा करने और यह निर्धारित करने में मदद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं कि वे आगे कैसे बढ़ना चाहते हैं।
- एक वकील अंतिम समझौते का मसौदा बनाने में मदद कर सकता है या फिर यह सुनिश्चित करने के लिए समीक्षा कर सकता है कि यह स्पष्ट, कानूनी रूप से बाध्यकारी और प्रवर्तनीय है। अगर परियोजना डेवलपर समझौते की शर्तों का सम्मान नहीं करता है या समुदायों या स्थानीय पारिस्थितिक तंत्र को नुकसान पहुँचाता है, तो वे इसका हल करने के विकल्पों की पहचान भी कर सकते हैं।

नीचे दी गई तालिका में समुदाय से बातचीत करने वाली टीम की भूमिका और पैरालीगल या वकील द्वारा दी जाने वाली सहायता के क्षेत्रों के बारे में और विस्तार से बताया गया है।

	समुदाय की बातचीत करने वाली टीम	पैरालीगल्स	वकील
जागरूकता बढ़ाना पक्का करना कि समुदाय अपने अधिकारों को समझता हो और उसे प्रस्तावित परियोजना के बारे में जानकारी हो	• सूचना सत्रों में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए समुदाय के सदस्यों को संगठित करना। • महिलाओं, युवाओं और अल्प संख्यक समूहों सहित समुदाय के सभी सदस्यों के निर्णय लेने की प्रक्रिया में हिस्सा ले पाने के लिए स्थान बनाना। अगर संभव हो तो इन समूहों के साथ अलग-अलग मीटिंग करना। • समुदाय में अलग-अलग समूहों की प्राथमिकताओं को पहचानना और सामान्य मांगों पर समझौते को बढ़ावा देना।	• कार्बन बाज़ार (कार्बन मार्केट), भूमि अधिकारों और स्वतंत्र, पूर्व, सूचित सहमति (FPIC) पर जागरूकता सेशन आयोजित करना। • जटिल संकल्पनाओं को स्थानीय भाषा और सुलभ फ़ॉर्मेट में अनुवादित करना। • ज़रूरत पड़ने पर महिलाओं, युवाओं और अल्पसंख्यक समूहों को शामिल करने के लिए विचार-विमर्श करने और/या रणनीति सुझाने में मदद करना।	• समुदाय के नेताओं को लागू कानूनों, विनियमों और संभावित जोखिमों के बारे में शुरुआती कानूनी जानकारी देना। • प्रारंभिक ऑफ़र या समझौता ज्ञापनों (MoU) में समस्या सूचकों को पहचानना।
बातचीत के लिए तैयारी करना बातचीत शुरू होने से पहले सामूहिक प्राथमिकताओं और मुख्य मांगों को पहचानना	• बातचीत के लिए समुदाय की प्राथमिकताओं को एक एकीकृत स्थिति में समेकित करना। • समुदाय की ओर से बोलने के लिए प्रतिनिधि चुनना और बातचीत से पहले अभ्यास करना।	• समुदाय को उनकी प्राथमिकताओं, मांगों और उन सभी समस्याओं का दस्तावेजीकरण करने में मदद करना, जिनका वे समाधान करना चाहते हैं। • प्रस्तावित परियोजना और परियोजना डेवलपर द्वारा पूरी की जाने वाली ज़रूरतों के बारे में जानकारी इकट्ठा करना। • बातचीत करने वाली टीम को बातचीत में शामिल होने के तरीके के बारे में प्रशिक्षित करना और अभ्यास में उनकी मदद करना।	• समुदायों द्वारा तैयार किए गए प्रस्तावित शब्दों की समीक्षा करना। • राजस्व साझाकरण मॉडल, अनुबंध की अवधि और निकास की शर्त के बारे में सलाह देना। • बातचीत की रणनीति बनाने में मदद करना (उदाहरण के लिए, जिन पर समझौता संभव नहीं ऐसी बातों का स्पष्टीकरण या समुदाय के अपनी सहमति देने के लिए आवश्यक न्यूनतम शर्तों की स्पष्ट परिभाषा)।
डेवलपरों के साथ बातचीत सुनिश्चित करना कि समुदायों को उचित शर्तें मिलें, जो उनकी मूल मांगों को पूरा करती हैं।	• सहमत प्राथमिकताओं और मांगों को पेश करते हुए, समुदाय की ओर से बोलना। • ऑफ़र का मूल्यांकन करना और समुदायों की मुख्य मांगों के आधार पर जवाबी ऑफ़र का प्रस्ताव देना। • प्रगति के बारे में समुदाय को नियमित रूप से रिपोर्ट करना।	• बातचीत के दौरान समुदाय के प्रतिनिधियों की मदद करना (बैठक का कार्यवृत्त, शर्तों को स्पष्ट करना, समावेशन सुनिश्चित करना)। • व्यापक समुदाय के साथ बातचीत के प्रमुख मुद्दों को वास्तविक समय में समझाने में मदद करना।	• समुदाय के अधिकारों की सुरक्षा करने वाले शब्दों को प्रस्तावित करने के लिए समुदायों की सहायता करना। • यह मूल्यांकन करने में समुदायों की मदद करना कि ऑफ़र उनके लक्ष्यों और प्राथमिकताओं को कितनी अच्छी तरह पूरा करते हैं।

	समुदाय की बातचीत करने वाली टीम	पैरालीगल्स	वकील
समझौते को अंतिम रूप देना पक्का करना कि संविदा स्पष्ट हो, कानूनी रूप से सही हो और लागू किया जा सके।	• समुदाय के बीच सामूहिक फ़ैसला लेने के लिए समझौते के ड्राफ़्ट पर अंतिम विचार-विमर्श की सुविधा देना। • सामूहिक निर्णय लेने के लिए व्यापक सहभागिता सुनिश्चित करना और प्रक्रिया का दस्तावेजीकरण करना। • यह पक्का करने के लिए कि यह पारदर्शी और वैध है, समझौते पर हस्ताक्षर करने की सुरक्षा करना।	• अंतिम समझौते का एक सरल समुदाय-अनुकूल संस्करण में अनुवाद करने में मदद करना। • सामुदायिक बैठकों के दौरान समझौते के मसौदे में दिए गए प्रमुख दायित्वों और अधिकारों के बारे में बताना।	• यह पक्का करने के लिए कि मुख्य प्रावधान स्पष्ट और लागू किए जा सकें ऐसे हैं, राष्ट्रीय कानूनों के अनुरूप हैं, और सभी ज़रूरी मुद्दों (जैसे विवाद समाधान, समापन शर्त, आदि) को संबोधित करते हैं, समझौते की अंतिम समीक्षा करना। • पक्का करना कि समझौते पर सही तरीके से हस्ताक्षर किए गए हों, उनके लिए गवाह हो और उन्हें संबंधित अधिकारियों के साथ रजिस्टर किया गया हो।
समझौते की निगरानी करना और उसे लागू करना ट्रैक करना कि क्या प्रतिबद्धताओं का सम्मान किया जा रहा है और लाभ दिए जा रहे हैं या नहीं।	• समुदाय के सदस्यों को अपडेट करने के लिए नियमित सार्वजनिक फ़ोरम रखना। • राजस्व के पारदर्शी और समान वितरण की निगरानी करना। • जब प्रतिबद्धताएं पूरी नहीं होती हैं, तो समस्याओं को पैरालीगल और वकीलों तक पहुँचाना।	• संविदा में प्रतिबद्धताओं के अनुपालन की निगरानी करना (जमीन और प्राकृतिक संसाधनों तक पहुँच, राजस्व साझा करना, और अन्य सुरक्षा उपाय)। • अनुपालन, शिकायतों और विवादों के उल्लंघनों का रिकॉर्ड बनाए रखना और इसका समाधान खोजने के लिए समुदायों की सहायता करना।	• संविदा की शर्तों के अनुपालन के लिए समय-समय पर ऑडिट का समर्थन करना। • अगर प्रतिबद्धताओं का सम्मान नहीं किया जाता है या विवाद होते हैं, तो समाधान के लिए कानूनी रास्ते पर समुदायों का मार्गदर्शन करना। • अगर परिस्थितियाँ (कानून, जलवायु, बाज़ार की स्थितियाँ) बदलती हैं, तो फिर से बातचीत करने की सलाह देना।
फिर से बातचीत परिणामों की समीक्षा करना और मूल्यांकन करना कि किसी अनुबंध का नवीनीकरण करना है या फिर से बातचीत करनी है।	• लाभ उम्मीदों से मेल खाते हैं या नहीं, इसका मूल्यांकन करने में समुदाय की अगुवाई करना। • भविष्य में होने वाली वार्ताओं के लिए सबक पहचानना और यह ज्ञान आने वाले लीडर्स को देना।	• सीखे गए सबक और अगले चरणों पर सामुदायिक चिंतन को सुगम बनाना। • भविष्य में फिर से होने वाली बातचीत के लिए प्रासंगिक सबूत दस्तावेज़ीकृत करना।	• दायित्वों को पूरा किया गया या नहीं और किन चीज़ों में बदलाव की ज़रूरत हो सकती है, इस पर कानूनी राय देना • भविष्य में होने वाली वार्ताओं के लिए नए सामुदायिक प्रोटोकॉल ड्राफ़्ट करने में सहायता करना।

कोलम्बिया में पिरा पराना REDD+ संघर्ष में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देना

पाउलो इलिच बाका, सेंटर फ़ॉर द स्टडी ऑफ़ लॉ, जस्टिस एंड सोसाइटी - डेजस्टिसिया और जूलियन ट्रुजिलो गुरेरो, जेवरियाना यूनिवर्सिटी में लॉ एंड टेरिटरी पर कानूनी क्लिनिक

यह मामला कोलम्बियाई Amazon के वौपेस डिपार्टमेंट में स्थित पिरा पराना के मूल निवासी क्षेत्र पर केंद्रित है। इस क्षेत्र में छह पूर्वी Tukanoan मूल निवासी लोग रहते हैं और यह पारंपरिक अधिकारियों और सामुदायिक कप्तानों से बनी एक एकीकृत मूल निवासी परिषद के माध्यम से संचालित होता है। 2019 में, परिषद ने क्षेत्रीय शासन का समर्थन करने के लिए REDD+ परियोजनाओं की संभावनाओं का पता लगाने का स्वायत्त निर्णय लिया — जिसमें पूर्ण मूल निवासी नियंत्रण पर ज़ोर दिया गया, कोई बिचौलिया नहीं, और उनके स्व-निर्धारित विकास मॉडल के साथ संरेखण पर ज़ोर दिया गया। तथापि, एक समानांतर और अनधिकृत REDD+ परियोजना Corporation for the Sustainable Management of Forests (Masbosques) और Soluciones Proambiente S.A.S. द्वारा मूल निवासी लोगों की परिषद की सहमति के बिना विकसित किया गया था। रद्द की गई पावर ऑफ़ एटर्नी का इस्तेमाल करते हुए, कंपनियों ने 2021 में परियोजना रजिस्टर की थी, इसे Ruby Canyon Environmental द्वारा सत्यापित किया गया था, और 2018 के क्रेडिट के लिए Cercarbono से पूर्वप्रभावी प्रमाणन हासिल किया था, और अंततः उन्हें Delta Airlines को बेच दिया गया था।

जानकारी तक पहुँच और ख़ुद का निर्णय

इस मामले में न्याय का मुद्दा मूल निवासी लोगों के आत्मनिर्णय के अधिकारों के गंभीर उल्लंघन और स्वतंत्र, पूर्व और सूचित सहमति के साथ ही जानबूझकर पारदर्शिता और महत्वपूर्ण जानकारी तक पहुँच की कमी के इर्द-गिर्द घूमता है। इस परियोजना को पिरा पराना इंडीजीनियंस काउंसिल — क्षेत्र के सर्वोच्च शासी प्राधिकारण — को सूचित किए बिना या उसे शामिल किए बिना तैयार किया गया, मान्य किया गया और उसे बाज़ार में लाया गया। समुदाय इस बात से अनजान था कि एक REDD+ परियोजना रजिस्टर की गई थी, और 2022 तक Masbosques के नाम से क्रेडिट बेचे गए थे। अनुबंध, कार्यप्रणाली, और सत्यापन रिपोर्ट सहित दस्तावेज़ों को कभी भी परिषद के साथ साझा नहीं किया गया, जिससे मूल निवासी अधिकारों पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों मानकों का उल्लंघन हुआ।

इसके अलावा, जानकारी तक पहुँच की कमी मूल निवासी शासन को कमज़ोर करने की व्यवस्था के तौर पर काम करती थी। बाद में कंपनियों ने सामुदायिक प्रोटोकॉल को दरकिनार करके और अंदरूनी विभाजन को बढ़ावा देते हुए परिषद के बजाय व्यक्तिगत लीडर्स को चुनिंदा भुगतानों के जरिए परियोजना फंड का "प्रबंध" करने का प्रयास किया। जानकारी को साझा नहीं किया जा रहा था या फिर औपचारिक शासन चैनलों के बाहर वितरित किया जा रहा था और अक्सर ऐसी तकनीकी भाषा में बताया जाता था, जिसे समझना मुश्किल था। पारदर्शिता की इस कमी ने समुदाय को परियोजना के शुरुआती चरण में सार्थक रूप से समझने या उसका विरोध करने से रोक दिया।

समुदाय ने समस्या को हल करने के लिए क्या किया?

2022 में इस अनधिकृत परियोजना के बारे में पता चलने पर, पिरा पराना की मूल निवासी परिषद ने तुरंत राजनीतिक और कानूनी कार्रवाई की। उन्होंने परियोजना को अस्वीकार करते हुए औपचारिक संचार जारी किया और मांग की कि Masbosques और उसके साझीदार परिषद के क्षेत्र में REDD+ से संबंधित सभी गतिविधियाँ बंद कर दें और वे जारी किए गए कार्बन क्रेडिट का व्यापार करने से बचें। यह संचार परियोजना डेवलपर के तौर पर Masbosques और Soluciones Proambiente SAS को और साथ ही, स्वतंत्र ऑडिटर के तौर पर Ruby Canyon Environmental को और कार्बन मानक के तौर पर Cercarbono को भेजा गया था। इसके जवाब में, Masbosques ने कहा कि परियोजना में सभी कानूनी ज़रूरतों का अनुपालन किया गया था, जिसमें मूल निवासी लोगों की ओर से मांगी जाने वाली स्वतंत्र, पूर्व और सूचित सहमति भी शामिल है। कंपनी के अनुसार निजी अधिदेश संविदा पर हस्ताक्षर करने से इस अधिकार का उपयोग कर लिया गया था और मूल निवासी सरकार के साथ विस्तृत संबंधी की कोई आवश्यकता नहीं थी। दूसरे निकायों ने संचार पर प्रतिक्रिया नहीं दी। परियोजना जारी रहा और मूल निवासी लोगों की मांगों को नज़रअंदाज़ करते हुए इसके क्रेडिट बेचे गए।

उल्लंघनों की गंभीरता को स्वीकार करते हुए, परिषद ने कोलम्बियाई न्यायपालिका के समक्ष स्वायत्तता, आत्मनिर्णय, क्षेत्र, सांस्कृतिक अस्तित्व और जानकारी तक पहुँच के अधिकारों का बचाव करने के लिए एक tutela (संवैधानिक सुरक्षा कार्रवाई) दायर की।

उन्होंने फिर से आम सहमति बनाने और परियोजना से होने वाले नुकसानों का दस्तावेजीकरण करने के लिए आंतरिक सभाएं भी बुलाई थीं, जिसमें chagras (पारंपरिक कृषि प्रणालियों) पर प्रतिबंध लगाना भी शामिल था, जिन्हें कंपनियों ने कार्बन क्रेडिट को सही ठहराने के लिए वनों की कटाई के चालक के रूप में वर्गीकृत किया था। परिषद ने कानूनी और मानवाधिकार संगठनों के साथ मिलकर एक ऐसा केस बनाया, जिसमें पारदर्शिता की कमी, इस्तेमाल की गई पावर ऑफ़ एटर्नी की अमान्यता और मूल निवासी निर्णय लेने की प्रणालियों को दरकिनार करने के संरचनात्मक प्रभावों पर ज़ोर दिया गया था।

नतीजा क्या था?

समुदाय की रणनीति के कारण कोलंबिया के संवैधानिक न्यायालय ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया, जिसमें मूल निवासी परिषद के अधिकारों को बरकरार रखा गया और वैध सहमति के अभाव के चलते परियोजना को अमान्य घोषित कर दिया गया। कोर्ट ने माना कि REDD+ परियोजना को मूल निवासी लोगों द्वारा अपनी स्वयं की शासन प्रणाली के ज़रिए मंज़ूरी दी जानी चाहिए और इस तरह की सहमति के बिना कार्बन से संबंधित कोई भी हस्तक्षेप असंवैधानिक है।[5]

महत्वपूर्ण बात यह है कि आदेश ने पुष्टि की कि मूल निवासी परिषदें कोलम्बियाई कानून के तहत सार्वजनिक प्राधिकरण हैं और केवल वे ही अपने क्षेत्रों में फ़ॉरेस्ट कार्बन परियोजनाओं की व्यवहार्यता के बारे में निर्णय ले सकती हैं। अदालत ने उजागर किया कि कोलंबिया के कार्बन बाज़ार (कार्बन मार्केट) में मौजूदा विनियामक खालीपन कैसे मूल निवासी अधिकारों के उल्लंघन को संभव बनाता है और सरकार को मजबूत नियम, निगरानी तंत्र विकसित करने और मूल निवासी समुदायों के लिए जानकारी तक सार्थक, अग्रिम पहुँच सुनिश्चित करने का आदेश दिया है।

हालांकि Masbosques परियोजना के व्यवसायिक क्रेडिट पहले ही बिक चुके थे, आदेश ने समुदाय के अधिकार को सार्वजनिक मान्यता दी जाने के लिए बाध्य कर दिया और निजी कार्रवाई करने वालों को एक स्पष्ट संदेश भेजा: क्लाइमेट फाइनेंस गैर-कानूनी और नैतिक रूप से संदिग्ध तरीके से काम नहीं कर सकता। इसने जलवायु शमन के लिए पारदर्शी, स्वायत्त और सांस्कृतिक रूप से आधारित दृष्टिकोण अपनाने के व्यापक मूल निवासी आंदोलन के आह्वान को भी मज़बूत बनाया।

5 कोलम्बियाई संवैधानिक न्यायालय। T-248/24, 25 जून, 2024। बोगोटा। https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2024/t-248-24.htm

इस मामले से यह बहुत स्पष्ट हो गया है कि कोलम्बिया में कार्बन क्रेडिट मार्केट की मौजूदा स्थितियाँ मूल निवासियों के अधिकारों की सुरक्षा और सम्मान के लिए पर्याप्त नहीं हैं। सरकार द्वारा निर्मित वर्तमान विनियम तकनीकी मुद्दों पर केन्द्रित हैं और उन संवैधानिक मानदंडों को अनदेखा करते हैं जो पर्यावरणीय संरक्षण पर मूल निवासियों के दृष्टिकोण को शामिल करते हैं और साथ ही अपने क्षेत्र में शासन संबंधी उनके स्वायत्त निर्णयों को अनदेखा करता है। इसी तरह, इस आदेश ने दिखाया कि कंपनियों का व्यवहार मानव अधिकारों के लिए किए गए सम्यक् तत्परता मानकों के अनुरूप नहीं है। अपने निष्कर्षों में अदालत ने पाया कि वास्तव में परियोजना के मालिक के रूप में कंपनी ने सारे निर्णय लिए थे और मूल निवासी सरकार को एक तरफ कर दिया था।

वस्तुतः, कोर्ट ने तय किया कि प्रतिवादी कंपनियों ने स्वतंत्र, पूर्व और सूचित सहमति के अधिकार का उल्लंघन किया है, साथ ही स्व-शासन के अधिकार और पिरा पराना की सांस्कृतिक व्यवस्था का भी उल्लंघन किया है। परिणामस्वरूप, न्यायालय ने क्षेत्र की मूल निवासी परिषद को इस बारे में स्वायत्त निर्णय लेने के लिए आमंत्रित किया कि परियोजना को जारी रखा जाए या नहीं और यदि ऐसा है, तो किन शर्तों के तहत। साथ ही, कोर्ट ने कोलम्बियाई सरकार को आदेश दिया कि वह REDD+ के लिए पर्याप्त नियमन जारी करे, जो मूल निवासियों के अधिकारों की रक्षा करते हैं, जिसमें स्व-शासन, स्वतंत्र, पूर्व और सूचित सहमति, और सामाजिक और पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों का विकास शामिल है।

कोर्ट के फैसले के बाद, मूल निवासी परिषद ने अपने शासी निकाय में बैठक की और परियोजना को जारी रखने से इनकार करने का फैसला किया। इसमें तर्क दिया गया था कि परियोजना कभी भी कानूनी रूप से स्थापित नहीं की गई थी क्योंकि इसे क्षेत्रीय अधिकारियों की सहमति के बिना पूरा किया गया था। परिषद ने बिचौलिये डेवलपर्स के बिना REDD+ परियोजना विकसित करने में भी दिलचस्पी दिखाई। यह परियोजना क्षेत्राधिकार पर आधारित होगी क्योंकि इसमें वे सभी मूल निवासी क्षेत्र शामिल होंगे जिन्हें स्व-शासित इकाइयों के रूप में सार्वजनिक मान्यता प्राप्त है। कोलंबिया में यह अपनी तरह का पहला परियोजना होगी।

इसके हिस्से के तौर पर, पर्यावरण मंत्रालय ने नए नियम जारी करने के लिए काम के सत्र आयोजित किए थे, लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं निकला।

चरण 2: समझौते की शर्तों को प्रस्तावित करना

I. परियोजना के समझौते में क्या शामिल होता है?

कार्बन परियोजना समझौता एक कानूनी संविदा होते हैं, जो भूमिकाओं और जिम्मेदारियों, सामुदायिक अधिकारों के लिए सुरक्षा, राजस्व साझा करने की व्यवस्था और सभी पक्षों द्वारा सहमत अन्य प्रतिबद्धताओं को परिभाषित करते हैं। समुदायों को यह सुनिश्चित करने के लिए अनुबंध की शर्तों की सावधानीपूर्वक जांच करनी चाहिए कि वे सामुदायिक प्राथमिकताओं को दर्शाते हैं, और आपको अनुबंध में किसी भी मुद्दे को संबोधित करना चाहिए जिसे आप आवश्यक या गैर-परक्राम्य के रूप में देखते हैं।

इस सेक्शन में, हम किसी परियोजना समझौते के प्रमुख तत्वों के बारे में संक्षेप में बताते हैं। फिर हम देखेंगे कि समुदाय किस तरह से किसी समझौते की शर्तों को सक्रियता से प्रस्तावित कर सकते हैं। आखिर में, हम चर्चा करेंगे कि समुदाय किसी परियोजना समझौते के लिए स्वतंत्र, पूर्व और सूचित सहमति के लिए प्रक्रिया को कैसे परिभाषित कर सकते हैं।

कार्बन परियोजना समझौते के मुख्य घटक:

- **पार्टियां:** यह सेक्शन बताता है कि कार्बन परियोजना में कौन शामिल है और उनकी भूमिकाएँ क्या हैं। यह स्पष्ट करता है कि परियोजना समझौते के तहत कानूनी रूप से बाध्यकारी प्रतिबद्धताएं कौन कर रहा है। यह सेक्शन यह पक्का करने के लिए ज़रूरी है कि परियोजना में खास अधिकारों वाले समुदायों को औपचारिक रूप से एक कानूनी पार्टी के तौर पर पहचाना जाए।
- **परियोजना का विवरण:** समझौते में एक या अधिक सेक्शन शामिल होंगे, जिनमें कार्बन परियोजना के उद्देश्यों और प्रमुख गतिविधियों के बारे में बताया जाएगा, जिसमें परियोजना का स्थान, कुल क्षेत्रफल और सामुदायिक भूमि पर प्रभाव शामिल है। आमतौर पर, यह सेक्शन इस्तेमाल किए जाने वाले कार्बन सर्टिफिकेशन स्टैंडर्ड (जैसे Verra या Gold Standard) की पहचान करेगा।
- **भूमि को पहुँच और इस्तेमाल के अधिकार:** संविदा में भूमि पर अधिकारों के किसी भी स्थानांतरण एवं परियोजना डेवलपर और समुदाय के अधिकार धारकों को प्राप्त पहुँच और उपयोग

के अधिकारों की भी पहचान की जाएगी। यह सेक्शन समुदायों के उनकी भूमि का परियोजना के दौरान कैसे उपयोग किया जा सकता है और कैसे नहीं यह समझने और परिभाषित करने एवं वे बनाए रखना चाहते हों ऐसे किन्हीं भी प्रबंधन, पहुँच या उपयोग के अधिकारों के लिए महत्वपूर्ण है।

- **परियोजना संचालन:** यह उन प्रावधानों को संदर्भित करता है जो निर्णय लेने में भूमिकाओं और परियोजना कार्यान्वयन या निगरानी में शामिल किसी भी प्रबंधन निकाय को परिभाषित करते हैं। इसमें स्पष्ट रूप से परिभाषित होना चाहिए कि समुदाय कैसे शामिल होंगे और पूरे परियोजना के कार्यान्वयन के दौरान मुख्य परिणामों के लिए उत्तरदायिता और समुदाय के अधिकारों के लिए सुरक्षोपाय कौन से हैं।
- **राजस्व साझा करना:** संविदा में इस बारे में पूरी जानकारी शामिल होनी चाहिए कि परियोजना से होने वाले राजस्व को इसमें शामिल पक्षों के बीच कैसे साझा किया जाएगा। इसमें स्थानीय समुदायों को जाने वाले राजस्व के हिस्से को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना शामिल होना चाहिए और इसका भुगतान कैसे किया जाएगा। राजस्व साझा करने में मौद्रिक भुगतान और अन्य गैर-आर्थिक लाभ, जैसे स्थानीय निवासियों के लिए नौकरी या स्थानीय आजीविका में निवेश, दोनों शामिल हो सकते हैं।
- **जानकारी तक पहुँच:** संविदा में ऐसी किसी भी जानकारी का विवरण शामिल होना चाहिए, जिसे डेवलपर को समुदाय के साथ साझा करना चाहिए और कितनी बार। ये प्रावधान एक समुदाय के लिए कार्यान्वयन को ट्रैक करने और यह सत्यापित करने में सक्षम होने के लिए महत्वपूर्ण हैं कि सभी प्रतिबद्धताओं को पूरा किया जा रहा है। समुदायों को सुनिश्चित करना चाहिए कि परियोजना गतिविधियों, स्थानीय समुदायों या पारीस्थितिक तंत्र को जोखिमों और परियोजना फाइनेंस के बारे में जानकारी तक पहुँच के लिए स्पष्ट प्रतिबद्धताएं हैं।
- **शिकायत निवारण:** संविदा विवादों के समाधान की प्रक्रियाओं को परिभाषित करेगी और समुदायों द्वारा की गई किसी भी शिकायत को संबोधित करेगी। इसमें अक्सर संविदा के पक्षों के बीच विवादों को सीधे हल करने के लिए परियोजना-आधारित शिकायत तंत्र शामिल होता है, ताकि ज़रूरत पड़ने पर स्थानीय या राष्ट्रीय स्तर पर मध्यस्थता या बाहरी निकायों को रेफ़र किया जा सके। यह पक्का करना ज़रूरी है कि विवाद समाधान और शिकायत निवारण की प्रक्रियाएँ वैध हों और समुदाय के सदस्य उन तक आसानी से पहुँच बना सकें।
- **अवधि:** संविदा अनुबंध जिसके लिए वैध है उस समयसीमा को परिभाषित करेगी। ज़्यादातर मामलों में, कार्बन परियोजना का जीवनकाल लंबा होता है, अक्सर 30 से 50 साल या उससे अधिक समय तक। संविदा में परियोजना के जीवनकाल के दौरान कुछ अल्पकालीन प्रतिबद्धताएं शामिल हो सकती हैं, लेकिन इनकी अवधि कम होनी चाहिए और समय-समय पर रिन्यू किए जाने की संभावना होनी चाहिए।

- **समापन की शर्तें:** समापन की शर्तें उन शर्तों को परिभाषित करती हैं जिनके तहत डेवलपर या समुदाय बताई गई अंतिम तारीख से पहले संविदा से नाम वापस ले सकते हैं या उसे रद्द कर सकते हैं। ज़्यादातर मामलों में, यह तभी संभव होता है, जब अनुबंध की शर्तों का अनुपालन न किया गया हो या बाहरी संदर्भ में कोई बड़ा बदलाव आया हो। वे यह भी बताते हैं कि भूमि पर अधिकार, परियोजना क्षेत्र में पहुँच, और बाकी बचे हुए राजस्व के लिए समय से समापन का क्या मतलब है। ये शर्तें कार्बन परियोजना के लिए खास तौर से महत्वपूर्ण होती हैं क्योंकि संविदा अक्सर 30 साल या उससे अधिक समय तक चलती हैं। समुदाय को यह पक्का करना चाहिए कि समापन की शर्तें स्पष्ट हों और परियोजना से उनके भूमि के अधिकारों और राजस्व के अधिकारों को पर्याप्त रूप से सुरक्षित रखें।

II. शर्तों को प्रस्तावित करना

अक्सर समुदाय, किसी प्रस्तावित परियोजना के लिए प्रस्ताव देने के लिए परियोजना डेवलपर की प्रतीक्षा करते हैं। हालाँकि, अगर समुदाय पहले कुछ शर्तों का प्रस्ताव रखते हैं, तो उनके पास बातचीत में ज़्यादा ताकत होती है। एक सामान्य नियम के तौर पर, जो भी पहला ऑफ़र देता है, उसे फ़ायदा मिलता है क्योंकि शुरुआती प्रस्ताव एक संदर्भ बिंदु या "एंकर" के रूप में काम करता है, जिससे पता चलता है कि दोनों पक्ष बातचीत को किस तरह से देखते हैं। जब समुदाय सक्रियता से कोई प्रस्ताव देते हैं, तो उन्हें परियोजना डेवलपर या संभावित पार्टनर को बताने का अवसर मिलता है कि उनके लक्ष्य और प्राथमिकताएं क्या हैं।

ऐसे व्यवहार्य प्रस्ताव के साथ शुरुआत करना ज़रूरी है जो दूसरे पक्ष के लिए भी कारगर हो। अपनी मुख्य प्राथमिकताओं पर ध्यान दें और ऐसी शर्तें प्रस्तावित करें जो चुनौतीपूर्ण हों लेकिन बचाव के योग्य हों। व्यवहार्य ऑफ़र के साथ शुरुआत करके और सिर्फ़ मामूली और विरल रियायतें देकर, आप अपने बातचीत करने वाले पार्टनर को दिखा सकते हैं कि आप मुख्य मांगों के बारे में स्पष्ट और अडिग हैं।

अगर कोई परियोजना डेवलपर पहले किसी ऑफ़र के साथ आपके समुदाय से संपर्क करता है, तो भी आप अपने समुदायों की मुख्य प्राथमिकताओं को स्पष्ट रूप से बताकर और जो भी आपको समझौता न करने योग्य लगता है, उन्हें स्पष्ट रूप से बताकर बातचीत पर नियंत्रण कर सकते हैं। सावधान रहें और उनके शुरुआती ऑफर के बजाए अपने एंकर के रूप में परिभाषित लक्ष्यों का उपयोग करें।

A. मांगों के एक समूह को पहचानें

अगर आपका समुदाय यह तय करता है कि आप प्रस्तावित परियोजना के लिए तैयार हैं, तो बातचीत शुरू करने से पहले यह समझना ज़रूरी है कि आपके "नॉन-नेगोशिएबल्स" यानी कि ऐसी चीज़ें जिन पर आप समझौता नहीं करेंगे, क्या हैं। उन मुख्य मांगों के समूह को पहचानें जिन्हें किसी भी अंतिम समझौते में शामिल किया जाना चाहिए। इन मुख्य मांगों से बातचीत करने वाली टीम को ऑफ़र का आकलन करने की स्पष्ट आधार रेखा मिल जाएगी। इन मांगों के बारे में पहले से स्पष्ट रहने से यह सुनिश्चित करने में भी मदद मिल सकती है कि बातचीत के दौरान मुख्य प्राथमिकताओं का दबाव में कारोबार न किया जाए।

बातचीत के लिए अपने लक्ष्यों को सामूहिक रूप से तय करते समय इन सवालों पर विचार करें:

- आप कौन से सबसे महत्वपूर्ण अधिकारों को सुरक्षित रखना चाहते हैं?
- आप परियोजना के बारे में निर्णय लेने में किस तरह शामिल होना चाहते हैं? क्या कोई ऐसा क्षेत्र है जहाँ आपका समुदाय निर्णय लेने पर पूरा नियंत्रण रखना चाहता है?
- भविष्य के लिए अपने समुदायों की परिकल्पना को आगे बढ़ाने के लिए आपको परियोजना से क्या-क्या लाभ चाहिए?

अक्सर, राजस्व साझाकरण, वार्ताओं का मुख्य केंद्र होता है। हालांकि यह महत्वपूर्ण है, यह पक्का कर लें कि आप भूमि के इस्तेमाल, जानकारी, पारदर्शिता और परियोजना के बारे में फ़ैसले लेने से जुड़ी दूसरी प्रमुख मांगों को भी पहचान लें। ऐसे अन्य मुद्दे भी हो सकती हैं जो आपके समुदाय के लिए ज़रूरी हों, उदाहरण के लिए, उन स्थलों को सुरक्षित रखना जिनका सांस्कृतिक या आध्यात्मिक महत्व है।

बातचीत के लिए लक्ष्य पहचान लेने के बाद, यह तय कर लें कि कौनसे वास्तव में ऐसे हैं जिन पर समझौता नहीं हो सकता। ये आपकी सबसे ज़रूरी मांगें हैं — जिनके बिना समुदाय किसी भी सौदे से हट जाना पसंद करेगा। उन मूल मांगों के अलावा, जिन पर बातचीत नहीं की जा सकती है; समुदाय विकल्पों या समझौतों पर विचार कर सकता है।

नॉर्दर्न केन्या रेंजलैंड्स कार्बन परियोजना के साथ बातचीत के दौरान समुदाय की मांगें

सामुदायिक भूमि प्रबंधन समितियों और कंज़र्वेंसी बोर्ड द्वारा तैयार कियागया

पारदर्शिता: समुदाय को परियोजना से जुड़ी सभी जानकारी पूरी तरह से दिखाने की ज़रूरत है, ताकि सूचित फ़ैसले लिए जा सकें। इसमें 1) परियोजना संचालन लागत की वित्तीय जानकारी; कार्बन क्रेडिट बिक्री से होने वाली आय; और परियोजना की कोई भी संपत्ति; और 2) कार्बन क्रेडिट के मार्केटर्स सहित किसी भी तीसरे पक्ष के साथ संविदा का खुलासा करना शामिल है। भविष्य में, किसी भी अतिरिक्त संविदा को हस्ताक्षर किए जाने से पहले भाग लेने वाले समुदायों द्वारा मंज़ूरी दी जानी होगी।

लाभ साझा करना: समुदायों को कार्बन से होने वाली कमाई का सबसे बड़ा हिस्सा मिलना चाहिए, जो भूमि मालिकों और प्राथमिक परियोजना कार्यान्वयनकर्ताओं के रूप में उनकी भूमिका को दर्शाता है। समुदायों ने शुरू में प्रस्ताव दिया था कि कार्बन की बिक्री से होने वाले कुल राजस्व का 60% समुदायों को जाए और शेष 40% NRT और परियोजना संचालन लागत को जाए। हालाँकि राजस्व को बाँटने के विशिष्ट नियम बातचीत का हिस्सा थे, समुदायों को सब से बड़ा हिस्सा मिले इस सिद्धांत पर समझौते की कोई संभावना नहीं थी।

किसी भी पार्टी (समुदाय, NRT, मार्केटर्स, आदि) को वितरण करने से पहले सभी कार्बन राजस्व एक समर्पित परियोजना खाते में जमा किए जाने चाहिए। समुदाय की ओर से एक सामुदायिक प्रतिनिधि उस खाते पर हस्ताक्षरकर्ता होंगे और किसी भी लेन-देन के लिए उस प्रतिनिधि का हस्ताक्षर भी आवश्यक होगा।

शासन और निगरानी: समुदाय, परियोजना के कार्यान्वयन और वित्तीय प्रबंधन की निगरानी के लिए, एक विशेष निरीक्षण समिति की स्थापना करेगा, जिसे समुदाय के सदस्य चुनेंगे। यह समिति रिपोर्ट की समीक्षा करने, राजस्व प्रवाह की निगरानी करने और प्रतिबद्धताओं को बरकरार रखने में केंद्रीय भूमिका निभाएगी।

निर्णय लेने की शक्ति: किसी भी नई कार्बन संविदा पर बातचीत करने और उस पर हस्ताक्षर करने में CLMC और कंज़र्वेंसी लीडरशिप दोनों ही सक्रिय रूप से शामिल होंगे। कोई भी समझौता उनकी औपचारिक भागीदारी और अनुमोदन के बिना मान्य नहीं होगा।

स्वतंत्र कानूनी सहायता: संविदा और बातचीत की प्रक्रिया के सभी पहलुओं पर सलाह देने के लिए समुदायों के पास अपना स्वतंत्र वकील होगा। कानूनी लागत सामुदायिक संसाधनों के ज़रिये कवर की जाएगी, जिसमें पिछले कार्बन परियोजना से प्राप्त राजस्व भी शामिल है।

B. ध्यान में रखने योग्य महत्वपूर्ण मुद्दे

यह सेक्शन समझौते के लिए शर्तों का प्रस्ताव करते समय समुदायों के लिए महत्वपूर्ण विचार प्रदान करता है। यह आपके दीर्घकालिक हितों को सुरक्षित रखने के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर प्रकाश डालता है।

पहुँच और इस्तेमाल के अधिकार: कार्बन क्रेडिट परियोजना भूमि के इस्तेमाल को काफ़ी हद तक प्रभावित करते हैं और प्रकृति-आधारित परियोजना में आम तौर पर भूमि और संसाधनों के इस्तेमाल के तरीके पर प्रतिबंध भी शामिल होते हैं।

- **स्थान को परिभाषित करें** जिसे आप परियोजना क्षेत्र में शामिल करने को तैयार हैं और नहीं हैं। खास तौर पर, ऐसे किसी भी क्षेत्र की पहचान ज़रूर करें, जिसे बाहर रखा जाना चाहिए। इसमें खास सांस्कृतिक महत्व वाले क्षेत्र या जो मौजूदा रिहायशी इलाकों के नजदीक हैं, शामिल हो सकते हैं। हो सकता है कि आप आजीविका गतिविधियों, जैसे कि खेती, पशु चराना, मछली पकड़ना या घरेलु ज़रूरतों के लिए लकड़ी काटना, के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले क्षेत्रों को सुरक्षित रखना चाहें।
- **उन पहुँच, उपयोग और प्रबंधन अधिकारों को पहचानें, जिन्हें समुदाय परियोजना एरिया में बनाए रखना चाहता है।** उदाहरण के लिए इसमें लकड़ी के अलावा अन्य वन्य उत्पाद इकट्ठा करने का अधिकार, पानी के स्रोतों या मछली पकड़ने के क्षेत्रों के उपयोग का अधिकार या फुटपाथ और पगडंडियों के उपयोग के अधिकार शामिल हो सकते हैं।
- **यह तय करें कि परियोजना की किसी गतिविधि से आस-पास के इलाके प्रभावित हो सकते हैं या नहीं।** उदाहरण के लिए, दक्षिण भारत में मैंग्रोव रीस्टोरेशन परियोजना में भाग लेने वाले समुदायों ने कुछ क्षेत्रों को मैंग्रोव रोपण से बाहर करने का फैसला किया क्योंकि इससे उनके मछली पकड़ने के मैदानों में पानी का बहाव बदल जाएगा।

परियोजना संचालन: सामुदायिक भूमि पर कार्बन परियोजनाओं को परियोजना डिज़ाइन और कार्यान्वयन में समुदायों को साझीदार के रूप में शामिल करना चाहिए। यह समुदायों के साथ सिर्फ़ "लाभार्थी" की तरह बर्ताव करने से बहुत अलग है। फिर भी, समुदाय को परियोजना के अलग अलग पहलू में निर्णय लेने की शक्ति के स्तर पर बातचीत के वक़्त सिमित ध्यान दिया जाता है। एक समुदाय के तौर पर, इस पर विचार करें:

- निर्णय लेने के किन क्षेत्रों में शामिल होना ज़रूरी है? इसमें परियोजना डिज़ाइन और प्रमुख गतिविधियों की योजना बनाना, दैनिक कार्यान्वयन में सहभागिता, और/या कार्यान्वयन की निगरानी और राजस्व साझा करना शामिल हो सकता है।
- परियोजना में आपका समुदाय कौनसी भूमिकाएँ निभाना चाहता है? प्रकृति-आधारित परियोजना के लिए, क्या आप सीधे संरक्षण गतिविधियों का प्रबंधन या नेतृत्व करना चाहते हैं?

यहां ऐसे फ्रंटलाइनअधिवक्ताओं के सुझाव दिए गए हैं, जिन्होंने कार्बन परियोजना में शामिल होने के लिए समुदायों की सहायता की है:

- **भूमि के इस्तेमाल के लिए स्थानीय नियमों को सक्रिय रूप से परिभाषित करें और मुख्य गतिविधियों के लिए स्थान प्रस्तावित करें।** जब समुदाय भूमि के उपयोग के लिए स्थानीय नियमों — या **सामुदायिक उपनियमों** — को परिभाषित करने के लिए एक साथ आते हैं, तो वे सक्रिय रूप से संरक्षण और परियोजना की अन्य गतिविधियों के लिए योजनाओं को आकार दे सकते हैं। ये उप-नियम समुदायों को परियोजना गतिविधियों के डिज़ाइन में नेतृत्व या भागीदार बनाते हैं।
- सिर्फ़ परियोजना के मकसद से नए संस्थान बनाने के बजाय, **मौजूदा सामुदायिक शासन संरचनाओं के द्वारा जुड़ें।** जहां तक संभव हो सामूहिक निर्णय लेने और प्रबंधन के लिए मौजूदा प्रक्रियाओं का फायदा उठाना महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनके पास पूरे समुदाय में सामूहिक कार्रवाई को संगठित करने के लिए अनुभव और क्षमता होने की संभावना अधिक होती है। इससे यह भी पक्का हो सकता है कि परियोजना डेवलपर उन प्रतिनिधियों को खुद न चुनें जिनके ऊपर उनका प्रभाव है।
- **एक संयुक्त प्रबंधन निकाय का प्रस्ताव करें जिसमें समुदायों और परियोजना डेवलपर, दोनों के प्रतिनिधि शामिल हों।** यह समुदाय के प्रतिनिधियों को प्राथमिकताएं पहचानने, चिंताएं उठाने और परियोजना डेवलपर के साथ जारी बातचीत में बने रहने के लिए जगह देता है। यह संयुक्त निकाय प्रमुख फ़ैसलों पर चर्चा कर सकता है और परियोजना कार्यान्वयन के दौरान निगरानी कर सकता है। यह ऐसी किसी भी समस्या की पहचान करने का तरीका भी हो सकता है, जिसके लिए व्यापक समुदाय से सहमति की ज़रूरत हो — उदाहरण के लिए, परियोजना का विस्तार या भूमि के इस्तेमाल में ज़रूरी बदलाव।

राजस्व साझा करना: परियोजना से समुदायों को मिलने वाले लाभों की मात्रा और रूप बातचीत का मुख्य उद्देश्य है। राजस्व साझा करने के लिए बातचीत करते समय फ्रंटलाइन एडवोकेट्स द्वारा महत्वपूर्ण मानी जाने वाली मुख्य बातें यहां दी गई हैं:

- **कुल राजस्व का प्रतिशत माँगें।** अधिवक्ताओं ने पाया है कि लाभ साझा करने के सबसे मज़बूत तरीके में समुदायों के हिस्से को कुल राजस्व के प्रतिशत के तौर पर परिभाषित करना शामिल है। एक निश्चित भुगतान राशि के विपरीत, आय का प्रतिशत यह सुनिश्चित करता है कि समुदायों को मिलने वाली राशि आनुपातिक रूप से बढ़ती है, अगर उत्पन्न क्रेडिट की मात्रा या क्रेडिट के लिए बिक्री मूल्य में बढ़ोतरी होती है।

  सामुदायिक हिस्सेदारी को मुनाफे के बजाय कुल राजस्व (सकल राजस्व) के आधार पर परिभाषित किया जाना चाहिए (परिचालन लागत में कटौती के बाद शुद्ध राजस्व)। इससे कुल राजस्व ट्रैक करना और यह सुनिश्चित करना बहुत आसान हो जाता है कि समुदायों को उनका पूरा हिस्सा मिले। अगर राजस्व के हिस्से को मुनाफ़े के प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया जाता है, तो समुदायों के लिए यह जानना कि परिचालन लागत पर कितना खर्च किया गया है और यह आकलन करना कि यह राशि वैध है या नहीं मुश्किल हो सकता है। परियोजना डेवलपर भविष्य की गतिविधियों में

कमाई का फिर से निवेश कर सकते हैं या परियोजना का विस्तार कर सकते हैं, जिससे समुदायों के लिए अपने हिस्से का दावा करना मुश्किल हो जाता है।

- **न्यूनतम वार्षिक भुगतान सेट करने पर विचार करें।** कई मामलों में, किसी परियोजना को कार्बन क्रेडिट से कमाई शुरू होने में तीन से पाँच साल लग सकते हैं। अनुबंध पर हस्ताक्षर होने के तुरंत बाद न्यूनतम वार्षिक भुगतान सेट करने से कार्बन क्रेडिट की बिक्री शुरू होने से पहले किसी परियोजना के शुरुआती सालों में समुदायों को नियमित आय मिल सकती है। अगर आपको परियोजना के तहत भूमि के इस्तेमाल या आजीविका के तरीकों में बदलाव करना पड़े , तो किसी भी खोई हुई आय को भरपाई करने के लिए यह ख़ास तौर पर ज़रूरी है।

  कार्बन क्रेडिट की कीमत में भी समय के साथ काफी फर्क हो सकता है। अगर क्रेडिट की कीमत घटती है, तो न्यूनतम भुगतान से बाद के वर्षों में स्थिरता मिल सकती है। कार्बन क्रेडिट की बिक्री शुरू होने से पहले किए गए किसी भी भुगतान को परियोजना के जीवनकाल में समुदायों के कुल राजस्व हिस्से के हिस्से के रूप में गिना जा सकता है।

- **समुदाय अपने राजस्व हिस्से का उपयोग कैसे किया जाए इसे स्वतंत्र रूप से तय करे।** समुदायों को दिया जाने वाला राजस्व परियोजना में उनके योगदान का सम्मान करता है और यह समुदाय के सदस्यों का होता है। समुदायों को यह अधिकार है कि वे अंदरूनी तौर पर सोच-विचार करके सीधे तय करें कि वे इस धन राशि का इस्तेमाल कैसे करना चाहते हैं। परियोजना डेवलपर को यह तय नहीं करना चाहिए कि समुदाय अपने हिस्से का इस्तेमाल कैसे करते हैं।

  समुदाय के राजस्व हिस्से से धन प्राप्त करने और उसे प्रबंधित करने के लिए एक सामुदायिक ट्रस्ट बनाया जा सकता है। ट्रस्ट बोर्ड या संचालन समिति में समुदाय के प्रतिनिधि और स्वतंत्र सलाहकार होने चाहिए, जो वित्तीय प्रबंधन और पारदर्शिता के बारे में मार्गदर्शन दे सकें।

प्रकृति-आधारित परियोजना के लिए, जिन समुदायों की भूमि यह है, उन्हें सकल राजस्व का कम से कम 50% मिलना चाहिए। Grassroots Justice Network इसे वैश्विक मानदंड बनाने के लिए संघर्ष कर रहा है। समुदाय अपनी भूमि, स्थानीय पारिस्थितिक तंत्र का गहन ज्ञान और दीर्घकालिक पर्यवेक्षण का योगदान दे रहे हैं; जो सब परियोजना के सफल होने के लिए आवश्यक है। सामुदायिक भूमि पर किसी भी परियोजना के लिए अधिकांश राजस्व समुदायों के पास जाने का आह्वान करना, भूमि के प्रबंधन में उनकी ज़रूरी भूमिका का सम्मान करता है।

50% राजस्व हिस्से की मांग करना एक उपयोगी शुरुआत है और यह बातचीत के लिए "एंकर" के तौर पर काम कर सकता है। अगर कोई डेवलपर कम ऑफ़र देता है, तो सबूत का बोझ उन पर होता है, ताकि यह पता चल सके कि वे इस मांग को पूरा क्यों नहीं कर पा रहे हैं।

आपके खास संदर्भ में आपके समुदाय द्वारा बातचीत करने में सक्षम होने वाली चीज़ों को कई कारक प्रभावित करेंगे। इसमें शामिल है कि क्या समान विशेषताओं वाली अन्य संभावित परियोजना साइट हैं, परियोजना का आकार, परियोजना डेवलपर का प्रकार (जैसे कि लाभ के लिए बनाम गैर-लाभकारी संस्था के लिए), और परियोजना का वित्तीय मॉडल।

व्यवहारिक सुझाव:

- अपनी भूमि के इस्तेमाल और आजीविका पर पड़ने वाले प्रभावों को देखते हुए एक लक्षित राशि और न्यूनतम राशि निर्धारित करें जिसे आप स्वीकार करने को तैयार हैं। गौर करें कि आप विकल्पों से क्या कमा सकते हैं (जैसे कि मौजूदा भूमि उपयोग, अन्य संभावित निवेश)।
- किसी ऐसे आंकड़े के साथ सक्रिय रूप से बातचीत शुरू करें, जो आपकी लक्षित राशि से ज़्यादा हो।
- आर्थिक भुगतानों के अलावा, आप दूसरे लाभों के लिए भी बातचीत कर सकते हैं, जैसे कि स्थानीय आजीविका के लिए प्रशिक्षण या उपकरण; परियोजना के हिसाब से समुदाय के सदस्यों को रोज़गार देना; या परियोजना कार्यान्वयन के हिस्से के रूप में संरक्षण या वित्तीय प्रबंधन पर क्षमता निर्माण।

C. इनपुट पाने और एक समुदाय के तौर पर अंतिम निर्णय लेने के लिए एक प्रक्रिया को परिभाषित करें

अगर संभव हो, तो सामुदायिक स्वतंत्र, पूर्व, सूचित सहमति प्रोटोकॉल तैयार करें या उसे अपनाएं - एक सरल गाइड जिसमें बताया गया है कि आपका समुदाय कैसे व्यवस्थित होगा, उस पर चर्चा करेगा और निर्णय लेगा। सामूहिक रूप से निर्णय लेने के तरीके के बारे में एक योजना की रूपरेखा तैयार करते समय, इसमें शामिल करना ज़रूरी है:

- **जानकारी तक पहुँच।** सोच-समझकर निर्णय लेने के लिए ज़रूरी सभी महत्वपूर्ण जानकारी सूचीबद्ध करें और पहचानें कि विचार-विमर्श करने के लिए आप सामूहिक बैठकों से पहले या उसके दौरान अपने समुदाय में जानकारी कैसे साझा करेंगे। मुख्य जानकारी में परियोजना डेवलपर के बारे में जानकारी, आपकी भूमि और आस-पास के इलाकों पर प्रस्तावित गतिविधियाँ, समुदायों पर संभावित प्रभाव और समझौते की प्रस्तावित शर्तें (उदाहरण के लिए, पारदर्शिता के लिए खास प्रतिबद्धताएं, समुदायों के लिए पहुँच और उपयोग के अधिकार, वे क्षेत्र जहाँ समुदायों का निर्णय लेने और राजस्व साझा करने में समुदायों की राय है) के बारे में जानकारी शामिल है।
- **विचार-विमर्श और निर्णय लेने के लिए सहभागी प्रक्रियाएँ।** किसी प्रस्तावित समझौते पर विचार करने के लिए आप एक समुदाय के तौर पर साथ कैसे आएंगे, इसके लिए स्पष्ट प्रक्रियाओं को परिभाषित करें। पूरे समुदाय से नज़रिया और इनपुट इकट्ठा करने के लिए किन प्रक्रियाओं का इस्तेमाल किया जाएगा? अंतिम फ़ैसले कैसे किए जाएंगे?
- **महिलाओं, युवाओं और अल्पसंख्यक समूहों को फ़ैसले लेने में शामिल करने के तरीके।** अगर इन्हें शामिल करने के लिए खास कार्रवाइयां नहीं की जाती हैं, तो इन समूहों के निर्णय लेने की प्रक्रिया से बाहर रहने का खतरा है। इनमें से प्रत्येक समूह के लिए समर्पित मीटिंग्स आयोजित करना उपयोगी होता है, ताकि वे अपनी चिंताओं को बता सकें और निर्णय लेने में उनकी सीधी राय हो।
- **दस्तावेज़ीकरण।** पहचानें कि विचार-विमर्श करने की प्रक्रिया और अंतिम निर्णय का दस्तावेजीकरण कैसे किया जाएगा (उदाहरण के लिए आयोजित मीटिंग्स की सूची, जिसमें तारीखें, स्थान और उन लोगों की संख्या शामिल हुई, जिन्होंने भाग लिया था; सामुदायिक मीटिंग्स के नोट्स या मिनट; या इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण चरणों में भाग लेने वाले समुदाय के प्रतिनिधियों के हस्ताक्षरित प्रमाण)। अगर भविष्य में कोई अनिश्चितता या विवाद हो, तो निर्णय लेने की प्रक्रिया के रिकॉर्ड का इस्तेमाल सबूत के तौर पर किया जा सकता है।

एक बार जब आपका समुदाय पूरे समुदाय से जुड़ने और साथ मिलकर किसी निर्णय पर आने की योजना तय कर लेता है, तो उस प्रक्रिया के बारे में परियोजना डेवलपर को बताएँ।

व्यवहारिक सुझाव:

- समुदायों को विचार-विमर्श करने और निर्णय लेने के लिए आंतरिक प्रक्रिया का नेतृत्व करना चाहिए, परियोजना डेवलपर को नहीं। आप परियोजना डेवलपर से मीटिंग आयोजित करने के लिए कह सकते हैं, ताकि व्यापक समुदाय के साथ जानकारी साझा की जा सके। हालांकि, परियोजना डेवलपर के बिना अलग चर्चा करना और निर्णय/फ़ैसले लेना सबसे अच्छा है।
- किसी फैसले पर पहुँचने के लिए आप प्रक्रिया और आपके समुदाय के लिए कारगर हो ऐसी समय रेखा, दोनों परिभाषित कर सकते हैं। टाइमलाइन प्रस्तावित करके, आप इस प्रक्रिया में जल्दबाजी करने के लिए दबाव को दूर कर सकते हैं। साथ ही, यह समुदाय के अंदर प्रक्रिया को आगे बढ़ने में आपकी मदद कर सकता है।

नेपाल में मर्स्यांगडी कॉरिडोर परियोजना के लिए समुदाय आधारित स्वतंत्र, पूर्व, सूचित सहमति प्रोटोकॉल

इस प्रोटोकॉल को 2020 में स्वतंत्र, पूर्व, सूचित सहमति व राइट्स फोरम और LAHURNIP (मूल नेपाल के निवासियों के मानव अधिकारों के लिए वकीलों का संघ) द्वारा यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक (EIB) द्वारा वित्त पोषित मार्स्यांगडी कॉरिडोर ट्रांसमिशन लाइन परियोजना से प्रभावित मूल निवासी और गैर-मूल निवासी समुदायों से जुड़े जमीनी स्तर पर विचार-विमर्श के जरिए विकसित किया गया था। मूल निवासी विशेषज्ञों द्वारा निर्देशित और बाहरी सहयोगियों द्वारा समर्थित, प्रोटोकॉल ने स्थानीय ज्ञान को अंतर्राष्ट्रीय अधिकारों के फ़्रेमवर्क के साथ मिलाकर स्वतंत्र, पूर्व, सूचित सहमति के लिए एक प्रक्रिया विकसित की, जिसे स्वयं समुदायों द्वारा परिभाषित किया गया था।

प्रोटोकॉल तीन चरणों वाली स्वतंत्र, पूर्व, सूचित सहमति प्रक्रिया की रूपरेखा तैयार करता है, जिसका नेतृत्व प्रभावित मूल निवासी समुदाय करते हैं:

1. **सहमति से पहले:** सहमति हासिल होने तक परियोजना की सभी गतिविधियाँ रुकी होंगी। एक संयुक्त स्वतंत्र, पूर्व, सूचित कार्यान्वयन समिति - जिसमें समुदायों, सरकार और यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक के प्रतिनिधि होते हैं - इस प्रक्रिया की देखरेख करती है। मूल निवासी विशेषज्ञों द्वारा स्वतंत्र रूप से सामाजिक, पर्यावरणीय और सांस्कृतिक प्रभावों के अध्ययन किए जाते हैं। परियोजना डिज़ाइन, भूमि का मूल्यांकन, और स्थानीय समुदायों के लिए क्षतिपूर्ति के बारे में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय भाषाओं में जानकारी साझा की जानी चाहिए। समुदाय, भरोसेमंद कानूनी और वकालत करने वाले समूहों की मदद से, ज़बरदस्ती या राजनीतिक हस्तक्षेप के बिना, आज़ादी से विचार-विमर्श करते हैं।

2. **सहमति:** समुदाय, अपने प्रतिनिधि संस्थानों के ज़रिए मिलते हैं, ताकि यह तय किया जा सके कि सहमति दी जाए, अस्वीकार किया जाए या उसे टाल दिया जाए। फ़ैसले लिखे जाने चाहिए और उनका पूरा सम्मान किया जाना चाहिए: **"नहीं"** का मतलब है रुकें, **"हां"** से परियोजना सहमत शर्तों के तहत आगे बढ़ सकता है।

3. **सहमति के बाद:** अगर सहमति दी जाती है, तो परियोजना कैसे लागू की जाएगी, समुदायों के लिए मुआवज़ा और फ़ायदे, और शिकायत की व्यवस्था को समुदाय की पूरी भागीदारी के साथ लागू किया जाता है। परियोजना में किसी भी बदलाव के लिए नए सिरे से सहमति चाहिए।

केन्या में सामुदायिक भूमि पर कार्बन क्रेडिट परियोजना के लिए सामुदायिक मांगों को सक्रिय रूप से पेश करना

अलबीना चेबोई और एलियस किमायो, SEECBO (सेंगवर ऑफ़ एम्बोबुट, समुदाय आधारित संगठन) के द्वारा

Sengwer समुदाय पश्चिमी केन्या के Cherangany हिल्स में कई पीढ़ियों से रहता आ रहा है। वे शिकारी और संग्रहकर्ता हैं, और जंगल उनका घर है। वे इसे घर इसलिए कहते हैं, क्योंकि वे आदि काल से प्रकृति के साथ रहते आए हैं। पेड़ उन पर निर्भर करते हैं, और वे अपनी पैतृक भूमि में पाए जाने वाले पेड़ों और अन्य प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर करते हैं। उनके पास स्थानीय उपनियम और शासन संरचनाएं हैं, जो संरक्षण और व्यवस्थित तरीके से जीवन जीने से संबंधित उनकी दिन-प्रतिदिन की गतिविधियों का मार्गदर्शन करती हैं। वे समुदाय में शासन के सबसे निचले स्तर पर भी, समावेशन और सहभागिता को बहुत महत्व देते हैं।

Sengwer समुदाय की अगुआई में वरिष्ठ नागरिकों की परिषद सबसे ऊपर आती है। वे किसी भी रिसर्चर या निवेशक के लिए एंट्री पॉइंट होते हैं, जो हमारे लोगों या भूमि से जानकारी इकट्ठा करना चाहता है। वरिष्ठ नागरिकों की परिषद पहली चर्चा करती है और फिर समुदाय के सदस्यों को सहभागिता के ज़रिए अपने विचार और राय बताने देती है। भूमि सभी जीवित जीवों और निर्जीव चीज़ों का भरण-पोषण करती है और इसे सामुदायिक संपत्ति बनी रहनी चाहिए।

परियोजना के बारे में

Cherangany हिल्स में The Nature Conservancy (TNC) द्वारा एक कार्बन परियोजना विकसित की जा रही है। इसका लक्ष्य संधारणीय भूमि प्रबंधन प्रथाओं के ज़रिये नदी के अवसादन को कम करने के लिए निजी भूमि पर किसानों के साथ काम करके ख़राब हो चुके जंगलों और खेतों को बहाल करना है। इस काम में मदद करने के लिए, TNC ने Eldoret-Iten Water Fund (EIWF) की स्थापना की, जिसे Cherangany हिल्स में मोइबेन नदी के जलक्षेत्र को संरक्षित करने का काम सौंपा गया है। यह वॉटरशेड एल्जियो माराक्वेट काउंटी के चेबारा डैम और एल्डोरेट सिटी में किपकारेन नदी में मिलता है।

मुख्य परियोजना प्रस्तावक एल्डोरेट वाटर एंड सैनिटेशन कंपनी लिमिटेड (ELDOWAS) है, जो उम्मीद करती है कि इस पहल से सूखे मौसम के दौरान स्ट्रीम फ्लो में सुधार होगा और गंदलेपन को कम करके पानी के उपचार की लागत कम होगी। TNC ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी (GEF) और इंटरनेशनल फ़ंड फ़ॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट (IFAD) सहित अन्य निधियनकर्ताओं के साथ मिलकर परियोजना को लागू कर रहा है।

स्वच्छ पानी बढ़ाने के लिए किए गए हस्तक्षेप के हिस्से के तौर पर, EIWF इनके साथ भी काम कर रहा है:

- **स्थानीय समुदाय:** EIWF समुदाय के सदस्यों के साथ मिलकर काम करता है, ताकि सीढ़ीदार खेतों का निर्माण करके और खेतों पर नैपियर घास लगाकर खेत के प्रबंधन की अच्छी प्रथाओं को अपनाया जा सके। वे मिट्टी के क्षरण को रोकने के लिए एक हस्तक्षेप के तहत उगाने के लिए स्वदेशी पेड़ों के पौधों की आपूर्ति भी करते हैं।
- **काउंटी सरकारें:** काउंटी सरकारें परियोजना क्षेत्र के किसानों को कृषि विस्तार सेवाएँ देती हैं।
- **Kenya Forest Service (KFS):** KFS जलस्रोत के तट पर स्थित भूमि और आर्द्रभूमि की मैपिंग और संरक्षण करता है। वे स्वदेशी पेड़ उगाकर खराब हो चुके वन क्षेत्रों को बहाल करने के लिए समुदायों के साथ मिलकर काम करते हैं।

परियोजना में शामिल पार्टियों में शामिल हैं:

कार्यान्वयनकर्ता

- एल्जियो मार्कवेट काउंटी की सरकार
- उसीन गिशू की काउंटी सरकार
- एल्डोरेट आइटेन वॉटर फ़ंड
- एल्डोरेट वॉटर एंड सैनिटेशन कंपनी (संसाधनों का संरक्षक)
- जल संसाधन उपयोगकर्ता असोसिएशन (WRUA)
- मूल निवासी और स्थानीय समुदाय

सह-कार्यान्वयनकर्ता और संसाधन जुटाने वाले

- The Nature Conservancy (TNC)
- पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और वानिकी मंत्रालय

निधियनकर्ता

- कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय फ़ंड (IFAD)
- वैश्विक पर्यावरण सुविधा (GEF)

परियोजना डिज़ाइन में मूलभूत समस्याएँ

The Nature Conservancy (TNC) ने EIWF परियोजना को तैयार किया और डिज़ाइन किया, तब Sengwer मूल निवासी समुदाय को इसकी जानकारी नहीं दी गई, भले ही उनकी पैतृक भूमि परियोजना के संरक्षित क्षेत्र में थी। Sengwer ने पुराने समय से इस भूमि पर अपना पैतृक इलाक़ा होने का दावा किया और 19 मार्च 2021 को कोर्ट का आदेश मिला, जिसमें Kenya Forest Service (KFS) या किसी अन्य संस्था को ज़बरदस्ती उन्हें बेदखल करने से रोका गया, जब तक कि उनके भूमि के मामले की सुनवाई और निर्धारण नहीं हो जाता। जब तक भूमि के दावों की समीक्षा जारी है, कोर्ट ने ख़ास तौर पर बेदखली पर रोक लगा दी है।

Sengwer लोगों की चिंताएं संरक्षण परियोजनाओं के पिछले अनुभवों में निहित हैं, जिनमें कार्बन से संबंधित पहल भी शामिल हैं, जहां उन्हें मानव अधिकारों का गंभीर उल्लंघन हुआ था। हालाँकि बाद में TNC ने नॉर्दर्न मऊ वॉटर टॉवर में Ogiek समुदाय के साथ परामर्श बैठकें की, लेकिन शुरुआत में Sengwer को बाहर रखा गया था। इस बहिष्करण ने प्रतिस्पर्धी दावों वाले सामुदायिक समूहों के बीच लंबे समय से चले आ रहे संघर्षों को और गहरा कर दिया।

फरवरी 2023 से, Sengwer EIWF परियोजना की समीक्षा करने के लिए सामूहिक रूप से जुट गए। उन्होंने ज़रूरी दस्तावेज़ इकट्ठा किए और फ़ॉरेस्ट पीपल्स प्रोग्राम (FPP) जैसे सहयोगियों की मदद से परियोजना की जटिल अवधारणाओं और शब्दावली को समझने का काम किया।

मार्च 2023 तक, परियोजना की गतिशीलता और हितधारकों को स्पष्ट करने के बाद, Sengwer वरिष्ठ नागरिकों की परिषद ने सभी शामिल पक्षों को एक औपचारिक पत्र भेजा, जिसमें GEF, IFAD, एल्जियो मराकवेट की काउंटी सरकार, EIWF, TNC, ELDOWAS और पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और वानिकी मंत्रालय शामिल हैं। पत्र में पहले की परियोजनाओं पर आधारित चिंताओं को रेखांकित किया गया था, जिन्होंने उनके अधिकारों का उल्लंघन किया था और समुदाय की सच्ची भागीदारी के ज़रिए स्वतंत्र, पूर्व, सूचित सहमति (FPIC) की मांग की।

अप्रैल 2023 में, TNC ने स्वतंत्र, पूर्व, सूचित सहमति की तलाश के लिए Sengwer समुदाय में एक मीटिंग आयोजित करके प्रतिक्रिया दी। मीटिंग के दौरान, समुदाय ने 27 मांगें पेश कीं, जिनमें ये मुख्य बातें शामिल थीं:

1. **भूमि की स्थिति:** एम्बोबट जंगल में स्थित Sengwer लोगों की पैतृक भूमि, एक संरक्षित क्षेत्र है जिसकी राष्ट्रीय भूमि आयोग द्वारा समीक्षा की जा रही है।
2. **मानव अधिकारों की सुरक्षा:** समुदाय के सदस्यों की पैतृक भूमि के अंदर घरों को जलाया नहीं जाना चाहिए, उन्हें गिरफ़्तार नहीं किया जाना चाहिए, उन्हें डराया नहीं जाना चाहिए या उनका उत्पीड़न नहीं होना चाहिए।
3. **प्रतिनिधित्व:** परियोजना को समुदाय के नेतृत्व वाली पहलों का समर्थन करना चाहिए, एल्डोरेट-इटेन वॉटर फ़ंड परियोजना संचालन समिति में कम से कम दो प्रतिनिधि (एक पुरुष और एक महिला) शामिल हों।
4. **लाभ साझा करना**: परियोजना से मिलने वाले सभी लाभों, जिसमें Cherangany हिल्स में कार्बन क्रेडिट और पारिस्थितिक तंत्र से जुड़े दूसरे भुगतान शामिल हैं, से मूल निवासी समुदाय को भी फ़ायदा होना चाहिए।
5. **विशिष्ट विशेषज्ञता:** मूल निवासी समुदाय के मुद्दों में विशेषज्ञता रखने वाले एक सलाहकार को मूल निवासी लोगों के कार्य योजना (IPAP) को विकसित करने के लिए नियुक्त किया जाना चाहिए।

Sengwer, Ogiek और Cherangany समुदायों ने संयुक्त रूप से इंडिजिनस पीपल्स एक्शन प्लान पर सहमति व्यक्त की और उस पर हस्ताक्षर किए। Sengwer IPAP की सभी मांगें मान ली गईं, सिवाय भूमि के अधिकारों के, जिन्हें एक ऐतिहासिक समस्या माना गया था। हालांकि, एल्डोरेट-इटेन वॉटर फ़ंड ने वचन दिया है कि ज़बरदस्ती बेदख़ली नहीं होगी। IPAP ने समुदाय के नेतृत्व वाली कई गतिविधियों की रूपरेखा भी दी थी:

- **सामुदायिक सहभागिता:** व्यापक दर्शकों तक पहुँचने के लिए परामर्श बैठकें आयोजित करना और जानकारी प्रसारित करना और मूल निवासी लोगों (IP) की भागीदारी को आसान बनाना, लिंग संतुलन सुनिश्चित करना, अंतर-पीढ़ीगत प्रतिनिधित्व, और प्रथागत/पारंपरिक संगठनों की भागीदारी सुनिश्चित करना।
- **क्षमता निर्माण और सशक्तिकरण:** कार्बन क्रेडिट, शासन संरचना, और परियोजना और वित्तीय प्रबंधन पर प्रशिक्षण; ट्री नर्सरी की स्थापना और प्रबंधन के लिए कौशल तैयार करना;

लक्षित कौशल विकास के ज़रिए महिलाओं और युवाओं को सशक्त बनाना; और पर्यावरण के अनुकूल आजीविका पर प्रशिक्षण, जिसमें आय उत्पन्न करने वाली गतिविधियाँ (IGA) और स्व-रोज़गार शामिल हैं।

- **सतत आजीविका और पर्यावरण:** स्वदेशी और फलों के पेड़ों की नर्सरी (जैसे, एवोकैडो) स्थापित करना; प्राकृतिक संसाधनों से होने वाले संघर्षों को कम करने के लिए वर्षा जल संचयन (जैसे, पानी के बर्तन) को बढ़ावा देना; ऊर्जा कुशल स्टोव (jikos) को बढ़ावा देना; मधुमक्खी पालन और शहद उत्पादन में सहायता करना, जिसमें युवाओं के लिए छत्तों के निर्माण और शहद वैल्यू चेन (पैकेजिंग, मार्केटिंग) पर प्रशिक्षण; खेती के सर्वोत्तम तरीकों और जलीय निकाय के तट पर सुरक्षा पर प्रशिक्षण और तटवर्ती क्षेत्रों में स्वदेशी पेड़ लगाने के लिए प्रशिक्षण शामिल हैं।
- **जोखिम प्रबंधन व शिकायत से निपटना:** संवेदीकरण और सहायता के ज़रिए पहचाने गए सामाजिक और पर्यावरणीय जोखिमों का समाधान करना; और निगरानी और रिपोर्टिंग सिस्टम के साथ-साथ Griveance Redress Mechanism (शिकायत निवारण तंत्र, GRM) की स्थापना और संचालन करना।

कार्यान्वयन के दौरान, समुदाय को कई बाधाओं का सामना करना पड़ा। उन्हें बताया गया कि वे सीधे परियोजना निधि प्रबंधित नहीं करेंगे। इसके बजाय, Eldoret-Iten Water Fund (EIWF) उनकी ओर से वित्त प्रबंधन करेगा। परिणामस्वरूप, समुदाय ने एक ही प्राथमिकता वाली गतिविधि पर ध्यान देने पर सहमति व्यक्त की: ट्री नर्सरी की स्थापना और प्रबंधन। हालांकि, सीडलिंग के पहले ऑफ़टेक के दौरान भी, चुनौतियां बनी रहीं, ख़ासकर ELDOWAS द्वारा भुगतान में देरी से होने की वजह से।[6]

6 ओजवांग जे. ए., केन्या में एक वॉटर फ़ंड मूल निवासी सांस्कृतिक पहचान से जुड़ी समस्याओं को प्रकाश में लाता है, 2024। https://news.mongabay.com/2024/11/in-kenya-a-water-fund-brings-to-light-indigenous-cultural-identity-issues/

चरण 3: परियोजना डेवलपर के साथ बातचीत करना

बातचीत में कई ऑफ़र और जवाबी ऑफ़र शामिल होते हैं, जब तक कि शर्तों का एक ऐसा सेट नहीं मिल जाता जिन्हें सभी पक्ष स्वीकार करना चाहते हैं। बातचीत के दौरान, परियोजना डेवलपर और समुदाय एक-दूसरे की प्राथमिकताओं को और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि वे क्या हैं और किस पर समझौता करने को तैयार नहीं हैं। अगर सही तरीके से संपर्क किया जाए, तो बातचीत सच्ची साझेदारी की नींव तैयार कर सकती है।

बातचीत के दौरान, अपनी प्राथमिकताओं पर ध्यान दें और ऑफ़र का ध्यानपूर्वक मूल्यांकन करें। इन तीन मुख्य चीज़ों पर पूरा ध्यान दें:

1. **भूमि का शासन:** यह ज़रूरी है कि परियोजना समुदाय के भूमि अधिकारों और उनकी भूमि के प्रबंधन की क्षमता को पहचाने और उन्हें बनाए रखे। जितना हो सके, समुदायों को पर्यवेक्षण के काम का नेतृत्व करने और परियोजना डिज़ाइन और कार्यान्वयन में एक भागीदार के रूप में शामिल होने में सक्षम होना चाहिए। परियोजना डेवलपर को सामुदायिक शासन निकायों को पहचानना चाहिए और उनके साथ काम करना चाहिए।
2. **उचित मुआवजा:** राजस्व साझा करने की व्यवस्था का बारीकी से और विस्तार से आकलन किया जाना चाहिए। कार्बन क्रेडिट की बिक्री से होने वाली कुल कमाई (कुल राजस्व) के प्रतिशत के लिए बातचीत करें, ताकि समुदायों को भुगतान किया जा सके — बजाय इसके कि निश्चित भुगतान राशि या परिचालन लागत में कटौती के बाद होने वाले मुनाफ़े के प्रतिशत (निवल राजस्व)। किसी भी गैर-मौद्रिक लाभ जैसे कि नई अवसंरचना, स्थानीय रोज़गार, या आजीविका सहायता को भी अनुबंध में स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए और उन्हें डेवलपर के लिए लागू करने योग्य दायित्व बनाने के लिए एक खास बजट आवंटित किया जाना चाहिए।

साथ ही, मार्केटिंग और कार्बन क्रेडिट की बिक्री की शर्तों पर बातचीत करना याद रखें। उदाहरण के लिए, ऐसे प्रावधान मांगें जिनके चलते क्रेडिट को न्यूनतम गारंटीकृत मूल्य पर बेचा जाना चाहिए और किसी भी बाहरी मार्केटर्स के लिए कमीशन की सीमा तय करें।

3. **सामुदायिक अधिकारों के लिए सुरक्षा उपाय:** संविदा में भूमि के अधिकारों के लिए सुरक्षा उपाय, समुदाय की सहमति, और विवादों को सुलझाने और शिकायतों के समाधान के लिए उचित प्रक्रिया भी शामिल होनी चाहिए। यह सुनिश्चित करना ध्यान में रखें कि समुदाय किसी भी वित्तीय नुकसान या उनके नियंत्रण में न हो ऐसे कार्बन स्टॉक को हुए नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे (जैसे आग या प्राकृतिक आपदाएं)। कार्बन परियोजना की लंबी अवधि को देखते हुए, संविदा में समय-समय पर समीक्षा और नवीनीकरण के प्रावधान भी शामिल होने चाहिए। इससे समुदायों को समय के साथ शर्तों पर फिर से बातचीत करने का मौका मिलता है।

इन मूलभूत सुरक्षाओं को स्थापित करके, समुदाय अपने अधिकारों को सुरक्षित रखने और अपनी प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने के लिए संविदा को एक शक्तिशाली टूल बना सकते हैं। उतना ही महत्वपूर्ण है, बातचीत में सक्रिय नियंत्रण रखना जिससे आपको एक मज़बूत समझौता पाने में मदद मिलेगी। जब समुदाय स्पष्ट प्राथमिकताओं और प्रस्तावित शर्तों के सेट के साथ बातचीत में प्रवेश करते हैं, तो वे संचालन को डेवलपर के नेतृत्व से समुदाय के नेतृत्व में हटा लेते हैं। उसी तरह, परियोजना डेवलपर को टाइमलाइन चलाने की अनुमति देने के बजाय, आप बातचीत के लिए गति निर्धारित करके प्रक्रिया को परिभाषित कर सकते हैं।

I. तैयारी करना और अभ्यास करना

बातचीत की प्रक्रिया को सक्रिय रूप से चलाने के लिए समुदाय से बातचीत करने वाली टीम के लिए तैयारी और अभ्यास महत्वपूर्ण होते हैं। एक अच्छी तरह से तैयार टीम ज़्यादा आत्मविश्वासी होगी, उससे चालाकी करना मुश्किल होगा, और वह बातचीत की दिशा और गति को बेहतर तरीके से तय कर पाएगी। बातचीत के दौरान नियंत्रण में रहने के लिए बातचीत करने वाली टीम नीचे दिए गए कुछ कदम उठा सकती है:

- बातचीत **के लिए समुदाय के लक्ष्यों को पहचानें** और मुख्य मांगों का एक सेट तैयार करें। हर अनुरोध के लिए, ऐसे किसी भी बैकअप विकल्प की पहचान करें, जिसे आप स्वीकार करना चाहें। किसी भी स्वीकार्य विकल्प पर विचार करना उपयोगी होता है, ताकि बातचीत करने वाले टीम के सदस्य परियोजना डेवलपर को वास्तविक समय में जवाब देने के लिए तैयार रहें।
- **बातचीत करने वाली टीम में भूमिकाएँ असाइन करें।** सिर्फ़ एक प्रवक्ता पर भरोसा करने से टीम कमज़ोर हो जाती है। इसके बजाय, ज़िम्मेदारियाँ बांटें, ताकि आप एक संगठित, संयुक्त मोर्चा पेश कर सकें। उदाहरण के लिए, आपको निम्नलिखित भूमिकाओं में से कुछ पर विचार करना चाहिए:
    - मुख्य प्रवक्ता - चर्चा शुरू करता है और समुदाय की प्राथमिकताओं को प्रस्तुत करता है।
    - टेक्निकल लीड - परियोजना डिज़ाइन और इम्प्लीमेंटेशन के बारे में सवाल पूछता है।
    - फाइनेंस से जुड़ा व्यक्ति - वित्तीय जानकारी और राजस्व के बंटवारे के लिए प्रस्तावित व्यवस्थाओं की जांच करता है।
    - सामुदायिक आवाज़ें - अलग-अलग सामाजिक समूहों की चिंताओं को दर्शाती हैं, जिनमें महिलाएं, युवा और कोई भी अल्पसंख्यक समूह शामिल हैं।
    - नोटटेकर - डेवलपर द्वारा साझा की जाने वाली मुख्य जानकारी, मीटिंग के दौरान किए गए सभी समझौते और अगले चरणों पर सहमति को दस्तावेज़ीकृत करता है।

यह संरचना टीम को साफ़ और रणनीतिक रूप से संवाद करने में मदद कर सकती है, और सुनिश्चित करती है कि किसी महत्वपूर्ण समस्या की अनदेखी न की जाए।

- **दबाव बिंदुओं को पहचानें** जो बातचीत के दौरान आ सकते हैं। चाहे सुविचारित हो या नहीं, सत्ता की गति समुदायों को अशक्त कर सकती है। संभावित समस्याओं का पहले से अनुमान लगा लेना मददगार होता है, ताकि आप चुनौतियों का सामना कर सकें और रणनीतिक तरीके से जवाब दे सकें। उन्हें कम करने के लिए यहां कुछ सामान्य चुनौतियां और उन्हें घटाने के लिए रणनीतियां दी गई हैं:

तकनीकी अधिभार:

कार्बन परियोजना में कई तकनीकी तत्व शामिल होते हैं जिन्हें समझना मुश्किल हो सकता है। बातचीत के दौरान, डेवलपर तकनीकी शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं या बड़ी मात्रा में जानकारी ऐसे तरीके से पेश कर सकते हैं, जिससे आपको उलझन या परेशानी हो।

ज़रूरत पड़ने पर विचार-विमर्श रोकें और सरल भाषा में स्पष्टीकरण का अनुरोध करें। तकनीकी घटकों पर मार्गदर्शन देने के लिए आप स्वतंत्र सलाहकारों को लाने की माँग भी कर सकते हैं।

जानकारी तक पहुँच बनाने में कठिनाई:

हो सकता है कि डेवलपर ज़रूरी जानकारी साझा करने के लिए तैयार न हों या कहें कि कुछ जानकारी गोपनीय है और उसका खुलासा नहीं किया जा सकता (उदाहरण के लिए, दूसरी पार्टियों जैसे कि मार्केटर्स ऑफ़ कार्बन क्रेडिट के साथ मौजूदा संविदा)। इससे समझौते की प्रस्तावित शर्तों को समझने और उनका आकलन करने की आपकी क्षमता सीमित हो सकती है।

परियोजना गतिविधियों, भूमि उपयोग और सामुदायिक भूमि अधिकारों, और वित्त और अनुमानित राजस्व पर प्रभाव से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी की पारदर्शिता पर ज़ोर दें। ज़रूरी जानकारी मिलने तक बातचीत को पूरी तरह रोकने के लिए तैयार रहें।

जल्दी करने का दबाव:

डेवलपर समुदाय को किसी प्रस्तावित समझौते की जानकारी समझने या सामूहिक रूप से विचार-विमर्श करने के लिए पर्याप्त समय दिए बिना, सहमति देने या समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए तेज़ी से आगे बढ़ सकते हैं।

सहमति के लिए सामूहिक रूप से सूचित फ़ैसला लेना ज़रूरी है। बातचीत करने वाली टीम यह कह सकती है कि “हमें किसी भी फ़ैसले से पहले चर्चा के लिए इसे पूरे समुदाय के पास वापस ले जाना होगा।” अंदरूनी विचार-विमर्श के लिए ज़रूरी समय के बारे में दृढ़ रहें और परियोजना डेवलपर से आपको जो भी अतिरिक्त जानकारी चाहिए, उसे पहचानें।

परियोजना स्वीकृतियां या कार्बन मानक के साथ रजिस्ट्रेशन से संबंधित वास्तविक समय का दबाव हो सकता है। किसी भी बाहरी समय सीमा के बारे में जानकारी मांगें और अगर उचित हो, तो पहचानें कि इस समय सीमा में आपके समुदाय को किसी फ़ैसले पर पहुँचने के लिए क्या ज़रूरी होगा। कभी-कभी आप अपने फ़ायदे के लिए समय के दबाव का इस्तेमाल कर सकते हैं — अगर आप मुख्य मांगों पर अडिग रहते हैं, तो हो सकता है कि परियोजना डेवलपर समय सीमा से पहले किसी सहमति पर पहुँचने के लिए कुछ रियायतें देने को तैयार हो।

अधिग्रहण (को-ऑप्टेशन):

डेवलपर, बातचीत करने वाली टीम या समुदाय के नेताओं से समुदाय की सलाह लिए बिना, फ़ैसला लेने के लिए कह सकते हैं। सबसे खराब स्थिति में, डेवलपर परियोजना को अनुकूल तरीके से पेश करने या समुदाय को उनके प्रस्तावों पर सहमत होने के लिए मनाने की कोशिश करने के बदले में समुदाय के नेताओं को अलग-अलग लाभ दे सकते हैं।

बातचीत के दौरान आप निर्णय लेने के तरीके के बारे में पहले से तय कर लें, जिसमें यह भी शामिल है कि आप समझौते पर हस्ताक्षर करने से पहले प्रतिपुष्टि कैसे प्राप्त करेंगे और व्यापक समुदाय में आम सहमति तक कैसे पहुँचेंगे।

आप जो कदम उठाएँगे, उनके बारे में परियोजना डेवलपर को बताएँ। यह साफ़ रखें कि समुदाय की ओर से कोई भी तब तक साइन नहीं कर सकता, जब तक कि समुदाय के सदस्यों के बीच सामूहिक सहमति न हो।

अपनी मांगों को पेश करने और उनके किसी भी दबाव का रणनीतिक और वास्तविक समय में जवाब देने का अभ्यास करने के लिए परियोजना डेवलपर के साथ हर मीटिंग से पहले अभ्यास सत्र या बातचीत की नकल समुदाय में ही करें।

बातचीत की नकल

दो ग्रुप्स में बंट जाएं। एक समूह डेवलपर की भूमिका निभाएगा जबकि दूसरा समूह समुदाय से बातचीत करने वाली टीम की भूमिका निभाएगा।

परिदृश्य: परियोजना डेवलपर समझौते का मसौदा पेश करता है, जो लाभ तो देता है लेकिन जंगल के इलाकों तक पहुँच को सीमित करता है। समय के कारण प्रेज़ेन्टेशन जल्दी किया जाता है और समुदाय से बातचीत करने वाली टीम को समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा जाता है, ताकि परियोजना जल्द शुरू हो सके।

अभ्यास के लिएबिंदु:

- डेवलपर के प्रस्ताव का जवाब देने के बजाय, **अपने समुदाय की मुख्य प्राथमिकताओं और शर्तों को बताकर शुरुआत करें।**
- **स्पष्टीकरण देने वाले प्रश्न पूछें:** समुदायों को परियोजना में शामिल क्षेत्रों तक पहुंचने और उनका उपयोग करने के लिए क्या अधिकार होंगे? उन इलाक़ों का प्रबंधन कौन करेगा जो सिर्फ़ संरक्षण के लिए आरक्षित हैं? क्या आप अपने द्वारा प्रस्तुत प्रोजेक्ट दस्तावेज़ की प्रति साझा करेंगे?
- **खास बातों के लिए जोर दें:** समुदायों को किए जाने वाले भुगतानों की गणना कैसे की जाएगी? समुदायों को और किस तरह के लाभ मिलेंगे? संविदा की समय सीमा या अवधि क्या है? किसी भी विवाद या शिकायत का समाधान कैसे किया जाएगा?
- **अपनी निर्णय लेने की प्रक्रिया पर ज़ोर दें:** अगर जल्दी से हस्ताक्षर करने के लिए दबाव डाला जाए, तो "जब तक हम एक समुदाय के तौर पर चर्चा नहीं करते तब तक हम किसी भी चीज़ पर हस्ताक्षर नहीं कर सकते" कहने का अभ्यास करें। एक समुदाय के तौर पर आप जिस निर्णय लेने की प्रक्रिया का इस्तेमाल करना चाहते हैं उसे साझा करें और उस प्रक्रिया के आधार पर अगला चरण प्रस्तावित करें। व्यापक समुदाय में वापस जाने से पहले, परियोजना डेवलपर से जो भी जानकारी चाहिए, उसे पहचानें।

संक्षिप्त विवरण (डिब्रीफ़): चर्चा करें कि क्या अच्छा हुआ, टीम को कहां अनिश्चितता महसूस हुई और किस सहायता की ज़रूरत है। इससे बाद के सत्रों की तैयारी करने में काफी मदद मिलेगी, जिसमें समुदाय को वापस रिपोर्ट करना भी शामिल है।

II. किसी ऑफ़र का मूल्यांकन करना और जवाबी ऑफ़र रखना

बातचीत में कई ऑफ़र और जवाबी ऑफ़र शामिल होते हैं, जब तक कि शर्तों का एक ऐसा सेट नहीं मिल जाता जिन्हें सभी पक्ष स्वीकार करना चाहते हैं। हर बार जब परियोजना डेवलपर किसी समझौते के लिए शर्तों का प्रस्ताव करता है, तो समुदाय के लक्ष्यों की तुलना में उनके ऑफ़र का आकलन करें और जवाब में स्पष्ट रूप से संरचित जवाबी ऑफ़र तैयार करें।

उनके ऑफ़र का मूल्यांकन करते समय कुछ बातों पर ध्यान देना चाहिए:

- आपकी कौनसी मांगें शामिल हैं? कौन सी नहीं हैं?
- परियोजना डेवलपर ने क्या-क्या रियायतें दी हैं?
- आप अपने जवाबी ऑफ़र में कौन से सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों को संबोधित करना चाहते हैं?
- ऐसी किसी भी चीज़ की पहचान करें जो किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं हैं और अपनी जवाबी ऑफर में इन्हें स्पष्ट रूप से बातचीत से बहार रखने की मांग कीजिये। आपको अपने जवाब में साफ़ तौर पर इन्हें ऑफ़ द टेबल कहना चाहिए।

व्यवहारिक सुझाव:

- ऑफ़र की शर्तों को और आसानी से समझने के लिए उन्हें सरल बनाकर शुरुआत करें। अगर मदद हो, तो स्थानीय अनुभवों पर आधारित उपमाओं का इस्तेमाल करके मुख्य शब्दों की एक सामुदायिक शब्दावली बनाएँ। आप दृश्य उपकरण या आरेखों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, उदाहरण के लिए, यह बताने के लिए कि पार्टियों के बीच राजस्व कैसे साझा किया जाएगा।
- किन्हीं प्रस्तावित शर्तों को समझने और परियोजना की जिन व्यावहारिक सीमाओं के भीतर काम कर रहा है, उनकी पहचान करने के लिए, अगर ज़रूरत हो, तो बाहरी मार्गदर्शन लें। हालांकि आप अपने प्रस्तावों को सक्रिय रूप से आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन परियोजना डेवलपर के लिए क्या संभव है, इस पर असल अड़चनें भी होंगी।

जवाबी ऑफ़र बनाना

एक स्पष्ट जवाबी ऑफ़र तैयार करें, जो बातचीत में आपकी प्राथमिकताओं को रणनीतिक रूप से आगे बढ़ाए। एक अच्छी शुरुआत यह है कि उन प्राथमिकताओं और जिन पर समझौता नहीं हो सकता उन चीज़ों पर वापस ध्यान दे , जिन पर समुदाय ने पहले सहमति की थी। ये वो चीज़ें हैं जिन्हें किसी भी समझौते में शामिल किया जाना चाहिए, उदाहरण के लिए, परियोजना गवर्नेंस में समुदायों के लिए खास भूमिकाएँ, सामुदायिक भूमि अधिकारों के लिए सुरक्षा उपाय, और राजस्व के बंटवारे के लिए न्यूनतम प्रतिबद्धताएं।

समुदाय को यह भी तय करना चाहिए कि बातचीत के दौरान आप किन मुद्दों पर समझौता करना चाहते हैं। उदाहरण के लिए, आप कुछ गतिविधियों की समयसीमा के बारे में लचीले हो सकते हैं, कुछ लाभ कैसे दिए जाते हैं, या डेवलपर बनाम समुदाय कौनसी खास भूमिकाएँ निभाते हैं। “होना ही चाहिए” को “बातचीत कर सकते हैं” से अलग करके, समुदाय ऐसा जवाबी ऑफ़र दे सकता है, जो स्पष्ट, यथार्थवादी और उनकी प्राथमिकताओं पर आधारित हो।

व्यवहारिक सुझाव:

आप अपनी मांगों को पूरा करने के लिए बातचीत में अन्य पक्षों से फ़ायदा उठा सकते हैं (क) स्पष्ट, सुसंगत मांगों को बताकर, जिन पर समुदाय पूरी बातचीत के दौरान एकजुट रहते हैं और (ख) राष्ट्रीय कानून या आपकी मांगों का समर्थन करने वाले कार्बन मानक की स्पष्ट आवश्यकताओं पर ध्यान आकर्षित करके।

सिएरा लियोन के शेरबो रिवर इस्ट्यूअरी में न्यायपूर्ण डील हासिल करना

समुदाय, सिएरा लियोन में समुदाय के नेतृत्व वाले मैंग्रोव संरक्षण से जुड़ी कार्बन परियोजना के लिए राजस्व साझा करने के बारे में African Conservation Initiative (अफ़्रीकी संरक्षण पहल, ACI) के साथ विस्तृत बातचीत में शामिल हुए। शुरुआत में, अफ़्रीकी संरक्षण पहल ने समुदायों के साथ 30 से 35% राजस्व साझा करने का प्रस्ताव रखा था, जिसमें स्थानीय रोज़गार और वार्षिक लीज़ से भुगतान शामिल होंगे।

जहाँ समुदाय ने परियोजना में अनेक अवसर देखे, वहीं उन्होंने शुरुआती ऑफ़र को अपर्याप्त पाया और उसके बदले 50% राजस्व साझा करने का प्रस्ताव रखा जो इस बात के आधार पर था कि परियोजना सामुदायिक भूमि पर हो रही थी, समुदाय द्वारा मैंग्रोव के पर्यवेक्षण पर प्रत्यक्ष रूप से आधारित थी और मैंग्रोव से स्थानीय आजीविका के लिए लकड़ी की कटाई पर पाबंदियाँ लगेंगी।

अफ़्रीकी संरक्षण पहल की प्रतिक्रिया

वित्तीय व्यवहार्यता के बारे में चिंताओं का हवाला देते हुए अफ़्रीकी संरक्षण पहल ने 50% जवाबी प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने तर्क दिया कि वे समुदायों को 50% राजस्व नहीं दे सकते, क्योंकि:

1. **इससे परियोजना को "ब्रेक-ईवन" बनने में लगने वाले समय में देरी होगी** या उस बिंदु तक पहुँच में देरी होगी जब वार्षिक राजस्व पूरी तरह से परिचालन लागत को कवर करने लगेगा और परियोजना मुनाफ़ा कमाना शुरू कर देगा; और
2. **वे पहले ही एक निवल घाटे पर प्रचालित करने वाले थे** पहले 17 वर्षों की निवेश अवधि के दौरान।

ये चिंताएं उन प्रमुख वित्तीय मैट्रिक्स को दर्शाती हैं जिनका उपयोग निवेशक परियोजना का मूल्यांकन करने और यह निर्धारित करने के लिए करते हैं कि परियोजना को लागू करने के लिए आवश्यक निधि उपलब्ध कराएं या नहीं, ख़ासकर परियोजना के शुरुआती चरण में (इस मामले में, पहले 15+ वर्ष)।

समुदायों ने स्वीकार किया कि वित्तीय व्यवहार्यता एक महत्वपूर्ण चिंता है, लेकिन उन्होंने अफ़्रीकी संरक्षण पहल के दावों का बेहतर आकलन करने और उनका जवाब देने के लिए अतिरिक्त जानकारी का अनुरोध किया, जिसमें शामिल थे:

- **"वित्तीय व्यवहार्यता" को स्पष्ट करना,** जिसमें अफ़्रीकी संरक्षण पहल के राजस्व, लागत के अनुमानों और जहां परियोजना नुकसान में नहीं हो उसकी समयसीमा। निवेशकों की ज़रूरतों को समझने के लिए उन्होंने स्पष्टीकरण वाले सवाल भी पूछे। इससे बातचीत करने वाली टीम को यह तय करने का आधार मिला कि अफ़्रीकी संरक्षण पहल की चिंताओं को कितना महत्व दिया जाए और यह पता लगाया जाए कि आपसी समझौते के अवसर कहाँ हो सकते हैं।
- ACI's आर्थिक मॉडलों में **इस्तेमाल कार्बन क्रेडिट्स की कीमत** बाज़ार मूल्य अलग-अलग होते हैं और मॉडल में इस्तेमाल की गई कीमत सीधे अनुमानित राजस्व की मात्रा को आकार देती है, जो बदले में वित्तीय व्यवहार्यता का आकलन प्रभावित करती है।
- आजीविका सहायता और स्थानीय रोज़गार से होने वाले **गैर-आर्थिक लाभों के बारे में ज़्यादा विस्तृत जानकारी।** वे समझना चाहते थे कि आजीविका गतिविधियों के लिए प्रशिक्षण और उपकरणों की ओर कितना पैसा जाएगा, जिसका उद्देश्य मैंग्रोव से लकड़ी की कटाई पर प्रतिबंध के किसी भी प्रभाव को दूर करना है। वे यह भी जानना चाहते थे कि हर साल स्थानीय लोगों के लिए कितनी नौकरियाँ पैदा होंगी, भूमिकाएँ किस तरह की होंगी, और हर एक के लिए मुआवज़ा क्या होगा।

इस जानकारी का अनुरोध करके, समुदायों का लक्ष्य समान स्तर पर वित्तीय चर्चाओं में शामिल होना और बातचीत में फ़ायदा के तौर पर अफ़्रीकी संरक्षण पहल के अपने मेट्रिक्स का इस्तेमाल करना है।

जवाबी ऑफ़र विकसित करना

इस जानकारी के आधार पर, समुदायों ने जवाबी ऑफ़र के लिए विकल्पों का एक सेट विकसित किया, जो वित्तीय व्यवहार्यता के बारे में निवेशकों की चिंताओं के साथ समुदाय की उम्मीदों को संतुलित कर सकता है। दो प्रस्ताव सामने आए:

1. **ब्रेक-ईवन पॉइंट से जुड़ा राजस्व का परिवर्तनीय हिस्सा:** समुदायों को राजस्व का 40% हिस्सा तब तक मिलेगा जब तक परियोजना का खर्च और आय बराबर नहीं हो जाते; परियोजना के एक ऐसे बिंदु पर पहुँचने के बाद, जहाँ वार्षिक राजस्व वार्षिक लागत से अधिक होता है, तो समुदाय का हिस्सा बढ़कर 50% से अधिक हो जाएगा।
2. **परियोजना के जीवनकाल में धीरे-धीरे किए गए भुगतान:** समुदायों को परियोजना की 30-साल की अवधि में 50% रेवेन्यू साझा मिलेगा, लेकिन शुरुआती सालों में वार्षिक भुगतान कम और बाद के सालों में ज़्यादा होगा, ताकि परियोजना डेवलपर शुरुआती चरण में अन्य लागतों को कवर कर सके।

समुदायों ने अफ़्रीकी संरक्षण पहल के ऑफ़र की शर्तों में खास बदलाव भी प्रस्तावित किए :

- **राजस्व हिस्से के सीमित हिस्से के रूप में स्थानीय रोज़गार:** समुदायों ने स्थानीय नौकरियों को एक महत्वपूर्ण लाभ के तौर पर देखा और उन्हें राजस्व हिस्से के तौर पर शामिल करने पर सहमति व्यक्त की। हालांकि, वे समुदाय द्वारा प्रबंधित फ़ंड में रोज़गार और नकद भुगतान के बीच संतुलन खोजना चाहते थे। उन्होंने प्रस्ताव दिया कि रोज़गार समुदाय के आधे से ज़्यादा हिस्से का गठन नहीं कर सकता और सामुदायिक ट्रस्ट नौकरी के विवरण और भर्ती को परिभाषित करने में शामिल हो।
- **परियोजना प्रबंधन में सामुदायिक संस्थानों की भूमिका का विस्तार करना:** समुदायों ने प्रस्ताव दिया कि मौजूदा सामुदायिक निकाय, विलेज एरिया लैंड समितियां (VALC), सामुदायिक उपनियमों को लागू करके और स्थानीय रूप से परिभाषित नियमों के किसी भी उल्लंघन की निगरानी करके संरक्षण का प्रबंधन करें। यह परियोजना में आत्मनिर्णय और सामुदायिक नेतृत्व का सम्मान करेगा। इससे रोज़गार की कुछ लागत भी कम हो गई, जिससे सामुदायिक फ़ंड में जा पाए और फ़ंड खाली हो गए।

अंतिम समझौता

कई दौर की बातचीत के बाद, समुदाय और अफ़्रीकी संरक्षण पहल निम्नलिखित शर्तों पर सहमत हुए:

- यह परियोजना कार्बन क्रेडिट बिक्री से होने वाले कुल राजस्व का 40% सामुदायिक राजस्व हिस्से के रूप में आवंटित करेगी।
- राजस्व साझा करने के अलावा, अफ़्रीकी संरक्षण पहल यह भी करेगा:
    - वे परियोजना में जो भूमि क्षेत्र प्रदान करेंगे उसके लिए प्रत्येक चीफडम को वार्षिक भुगतान करना,
    - आजीविका की गतिविधियों के लिए उपकरण उपलब्ध कराना (जैसे मछली सुखाने के लिए ऑयस्टर रैक और सोलर ओवन),
    - और आजीविका गतिविधियों, संरक्षण और जीर्णोद्धार गतिविधियों के प्रबंधन, और परियोजना प्रबंधन और निगरानी के लिए कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना।

  साथ मिल कर, ये मौजूदा अनुमानों के कुल राजस्व का 5-6% है।

इस केस स्टडी से बातचीत को संचालन करने के तरीके के बारे में अच्छी जानकारी मिलती है।

ऑफ़र का मूल्यांकन करने और मजबूत जवाबी ऑफ़र के साथ आने से कई सबक मिलते हैं।

1. साफ़ तौर पर जिन पर समझौता संभव नहीं ऐसी शर्तों के सेट से शुरुआत करें।

किसी भी प्रस्ताव का जवाब देने से पहले, समुदायों को उन चीज़ों के बारे में स्पष्ट हो जाना चाहिए जिन में समझौता संभव नहीं है — वे मुख्य लक्ष्य जिनके बिना आप अनुबंध को रद्द कर देंगे।

अफ़्रीकी संरक्षण पहल मामले में, समुदायों ने दो मुख्य समझौता संभव नहीं है ऐसी चीज़ों की पहचान की:

- *राजस्व का एक समान हिस्सा* जो भूमि के संरक्षक के रूप में उनकी भूमिका और परियोजना की सफलता में निभाई गई मूलभूत भूमिका को दर्शाता है।
- परियोजना द्वारा बनाई गई बाहरी भूमिकाओं या निकायों के बजाय मौजूदा सामुदायिक निकायों (CLC और VALC) में भूमि प्रबंधन के लिए भूमिकाएं पेश करके परियोजना में *सामुदायिक शासन और नेतृत्व*।

2. उन रियायतों को पहचानें जो दूसरे पक्ष की ज़रूरतों के मुताबिक हों।

एक प्रभावी जवाबी ऑफ़र दूसरे पक्ष की चिंताओं को सिरे से अस्वीकार नहीं करता है। इसके बजाय, उन क्षेत्रों की तलाश करें जहाँ आप समझौता कर सकते हैं या ऐसे रणनीतिक विकल्प सुझा सकते हैं, जो हर तरफ की ज़रूरतों को पूरा करते हों।

समुदायों ने समय के साथ समुदायों को भुगतान वितरित करने के तरीके में सुविधा देकर लंबी अवधि के लिए घाटे में काम करने के बारे में अफ़्रीकी संरक्षण पहल की चिंताओं का सीधे जवाब दिया।

उन्होंने कुल राजस्व के हिस्से में बढ़ोतरी के बदले में अन्य रियायतें भी दीं:

- समुदाय इस बात पर सहमत थे कि स्थानीय रोज़गार को समुदाय के राजस्व हिस्से के तौर पर शामिल किया जाए, लेकिन उन्होंने इस पर एक सीमा तय की कि यह कुल राजस्व हिस्से का कितना प्रतिनिधित्व करता है।
- समुदायों ने माना कि राजस्व के हिस्से के अलावा, परियोजना में आजीविका के लिए महत्वपूर्ण सहायता भी शामिल है, उदाहरण के लिए, ऑयस्टर और मछली पकड़ने वाली सहकारी समितियों के लिए प्रशिक्षण और उपकरण। इन अतिरिक्त फ़ायदों की वजह से वे राजस्व के कम हिस्से पर विचार करने के लिए तैयार हो गए।

3. जवाबी ऑफ़र को साक्ष्य आधारित रखें।

अपने जवाबी ऑफ़र के पीछे की सोच के बारे में बताएं और जब भी संभव हो, दूसरे पक्षों की चिंताओं और ज़रूरतों का जवाब दें।

अफ़्रीकी संरक्षण पहल ने कहा कि अगर वे 50% राजस्व साझा की पेशकश करते हैं, तो वे परियोजना की अन्य सभी लागतों को कवर नहीं कर सकते, खासकर परियोजना के पहले चरण में। जवाब में, समुदायों ने राजस्व और परिचालन लागतों के बारे में अतिरिक्त जानकारी का अनुरोध किया; फिर उन्होंने काम करने योग्य विकल्पों का प्रस्ताव करने के लिए उन्हीं वित्तीय मैट्रिक्स का इस्तेमाल किया।

4. तत्काल और लंबी अवधि के दोनों तरह के लाभों पर विचार करें।

पक्का कर लें कि आपको हर प्रस्तावित लाभ की समय-सीमा समझ आ गई हो। परियोजना की पूरी अवधि के दौरान लाभों को संतुलित करने के तरीकों की तलाश करें और उन लाभों को प्राथमिकता दें जो लंबी अवधि के लिए मूल्य उत्पन्न करते रहेंगे।

बातचीत के दौरान, सिएरा लियोन में समुदायों को एहसास हुआ कि लकड़बग्घे लगाने, चूल्हे बनाने और ऑयस्टर की कटाई के लिए वैकल्पिक तरीके स्थापित करने से जुड़े कई काम तीन से चार साल बाद खत्म हो जाएंगे। जवाब में, उनके जवाबी ऑफ़र ने सामुदायिक राजस्व के हिस्से और संधारणीयता के लिए कौशल प्रशिक्षण के ज़रिए अन्य दीर्घकालिक वित्तीय लाभों पर ज़ोर दिया।

5. जानें कि समझौता कब करना है और फायदे को प्रतिबद्ध कैसे करना है।

आखिरकार, बात करने का उद्देश्य निर्धारित लक्ष्य हासिल करने से ज्यादा समुदाय को ऐसा लगे कि प्रतिबद्धताओं का समग्र सेट उनकी ज़रूरतों को पूरा करता है या नहीं यह ज्यादा है। समझौते के विभिन्न हिस्सों और यह आपने आज तक भूमि का उपयोग कैसे किया है और अलग विकल्पों की तुलना में कैसा है, इस पर विचार करें।

आखिर में, सिएरा लियोन में समुदायों ने 40% राजस्व का हिस्सा स्वीकार कर लिया, लेकिन परियोजना में इस्तेमाल की गई भूमि के लिए वार्षिक किराए का भुगतान और स्थानीय आजीविका के लिए अन्य प्रशिक्षण और सहायता भी हासिल की।

उतनी ही महत्वपूर्ण बात यह थी कि परियोजना डेवलपर ने परियोजना के कार्यान्वयन में समुदायों के साथ साझीदारी का वादा किया, जिसमें परियोजना के कार्यान्वयन के बारे में बड़े निर्णय संयुक्त रूप से लेने के लिए एक साझा प्रबंधन समिति, संरक्षण और भूमि उपयोग के प्रबंधन के लिए उत्तरदायी सामुदयिक निकाय और समुदाय के राजस्व के हिस्से से प्राप्त निधि का प्रबंधन करने के लिए एक सामुदायिक ट्रस्ट।

मज़बूत प्रावधान विकसित करना

नीचे दी गई तालिका में असल ज़िंदगी के उदाहरण दिए गए हैं कि कैसे समुदायों ने अपने हितों की सुरक्षा के लिए मज़बूत समझौते किए। प्रत्येक उदाहरण में प्रस्तावित शुरुआती शर्तों और एक मजबूत प्रावधान के बारे में बताया गया है, जिसे समुदायों ने जवाब में प्रस्तावित किया था।

भूमि अधिकार

सिएरा लियोन में समुदाय एक ऐसे परियोजना के लिए समझौते पर विचार कर रहे हैं, जो आसपास के मैंग्रोव से कार्बन को कैप्चर करेगा। मैंग्रोव सामुदायिक अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं - पुरुष आस-पास मछली पकड़ते हैं जबकि महिलाएँ जलाऊ लकड़ी और शैलफ़िश इकट्ठा करती हैं। उनका सांस्कृतिक महत्व भी है।

शुरुआत में उन्हें इस भाषा वाली संविदा दी गई थी:	समुदाय ने इस संशोधित भाषा के बारे में जानने के लिए एक वकील के साथ काम किया:
"भूमि मालिक पट्टेदार से लीज़ पर दी गई भूमि का इस्तेमाल किसी भी उद्देश्य से नहीं करेगा, जिसमें ये शामिल हैं, लेकिन उन्हीं तक सीमित नहीं है: कृषि, जिसमें चराई, खेती, या फ़सलों की खेती शामिल है; और लकड़ी इकट्ठा करना, जिसमें मैंग्रोव, लकड़ी या अन्य वन संसाधनों की कटाई या काटना शामिल है। लीज एग्रीमेंट की अवधि के लिए समुदायों द्वारा पहुँच सीमित रहेगी।"	*"गाँवों की समिति द्वारा समुदायों के बीच विचार-विमर्श के बाद विशेष मैंग्रोव संरक्षण क्षेत्रों को नामित किया जाएगा। संरक्षण के लिए निर्धारित क्षेत्रों को विशेष रूप से चिन्हों से चिह्नित किया जाएगा, जिससे पता चलेगा कि वे संरक्षण क्षेत्र हैं।* *आरक्षित या संरक्षण क्षेत्रों में मैंग्रोव काटना प्रतिबंधित है।* *लोग मैंग्रोव को काटे या नष्ट किए बिना संरक्षण क्षेत्रों में उपयोग के अन्य अधिकारों का आनंद लेना जारी रख सकते हैं।"*

जानकारी तक पहुँच

उत्तरी केन्या में समुदाय करीब दस सालों से ग्रासलैंड कार्बन परियोजना को सह-लागू कर रहे थे, लेकिन उन्हें इस बारे में जानकारी नहीं थी कि परियोजना से कितना राजस्व मिला था।

शुरुआती परियोजना कार्यान्वयन समझौते में, ऐसा कोई ख़ास प्रावधान नहीं था, जिसके लिए परियोजना के प्रस्तावक को कार्बन क्रेडिट की बिक्री से होने वाली कमाई के बारे में जानकारी समुदाय के साथ साझा करनी पड़े।	समझौते पर फिर से बातचीत करते समय, समुदाय ने पारदर्शिता और जानकारी तक पहुँच के लिए खास प्रतिबद्धताओं की मांग की, जिसमें कार्बन क्रेडिट के लिए वित्तीय विवरण और सेल्स रिपोर्ट शामिल हैं। नए समझौते के ड्राफ़्ट में यह शामिल है: *"प्रस्तावक, समुदायों को वार्षिक ऑडिट किए गए वित्तीय विवरण उपलब्ध कराएगा। प्रस्तावक संविदा की कॉपी, कार्बन क्रेडिट के लिए सेल्स रिपोर्ट और परियोजना के तहत सभी लेनदेन की रसीदें भी उपलब्ध कराएगा।"*

निर्णय लेने में सहभागिता

जैसे-जैसे वे सिएरा लियोन में मैंग्रोव की सुरक्षा करने वाली ब्लू कार्बन परियोजना पर विचार कर रहे थे, समुदाय भी परियोजना के प्रमुख पहलुओं पर स्पष्ट निर्णय लेना चाहते थे, जिसमें मैंग्रोव का चल रहा प्रबंधन भी शामिल है।

शुरुआती प्रस्तावित समझौते में समुदायों के लिए परियोजना में भाग लेने या निर्णय लेने पर नियंत्रण करने का कोई स्पष्ट अधिकार शामिल नहीं था।

समुदायों ने कहा कि निर्णय लेने और नेतृत्व में उनकी भागीदारी के बारे में समझौते में साफ़ तौर पर बताया जाए। ख़ास तौर पर, वे यह सुनिश्चित करना चाहते थे कि उनके भूमि पर अधिकार स्पष्ट रहें और समुदायों द्वारा निर्धारित स्थानीय नियम योजनाबद्ध संरक्षण गतिविधियों के केंद्र में हों।
उन्होंने मांग की कि अनुबंध यह परिभाषित करे कि समुदाय किस तरह भूमि उपयोग, संरक्षण और जीर्णोद्धार क्षेत्रों की जगह, और परियोजना द्वारा समर्थित वैकल्पिक आजीविका गतिविधियों की पहचान के बारे में निर्णयों में कैसे भाग लेंगे औरअनुमोदन प्राप्त करेंगे।

अंतिम समझौते ने समुदाय की मांगों को शामिल कर लिया:

"भूमि के इस्तेमाल पर परामर्श।
डेवलपर यह करेगा:
(i) यह सुनिश्चित करना कि समुदाय आधारित संगठन और उनके प्रतिनिधियों के ज़रिये मूल निवासी लोगों और स्थानीय समुदायों से परियोजना के ज़रिए भूमि इस्तेमाल के किसी भी प्रस्तावित फ़ैसले के बारे में पहले से सार्थक सलाह ली जाए, जिसमें संरक्षण और जीर्णोद्धार क्षेत्रों का पदनाम, स्थान, और सीमाएँ शामिल हैं;
(ii) परियोजना प्रबंधन योजना (PMP) में भूमि और संसाधनों के इस्तेमाल को नियंत्रित करने वाले सामुदायिक उपनियमों का सम्मान करें और उन्हें शामिल करें, बशर्ते ऐसे उपनियम लागू राष्ट्रीय कानूनों और परियोजना के उद्देश्यों के अनुरूप हों;
(iii) समय-समय पर होने वाली मीटिंग्स और फ़ीडबैक सत्रों सहित स्थानीय समुदायों के साथ परामर्श करे और उनके साथ सहयोग करें, ताकि यह पक्का किया जा सके कि उनके दृष्टिकोण से डेवलपर द्वारा परियोजना गतिविधियों के डिज़ाइन और चल रहे प्रदर्शन के बारे में पता चलता है।"

राजस्व साझा करना

पेरु में एक समुदाय से कार्बन डेवलपर ने संपर्क किया था, जिसमें वादा किया गया था कि जल्दी पैसा कमाया जाएगा। हालांकि समुदाय आर्थिक अवसरों की तलाश में है। एक पड़ोसी गाँव ने हाल ही में एक संविदा पर हस्ताक्षर किया है, जिससे बुजुर्गों को कुछ निधि मिली, लेकिन बाकी समुदाय को इससे बहुत कम आर्थिक फ़ायदा हुआ। इसके बजाय, ऐसा लगा कि परियोजना डेवलपर ज़्यादातर पैसे अपने पास रख रहा था।

समुदाय ने इस बारे में आंतरिक चर्चा करने में कई महीने लगाए कि परियोजना पर विचार किया जाए या नहीं और भूमि के उपयोग में कैसा परिवर्तन हो सकता है। स्वतंत्र, पूर्व, सूचित सहमति प्रक्रिया के बाद ही उन्हें हस्ताक्षर करने के लिए संविदा की एक कॉपी दी गई थी। इसमें यह प्रावधान शामिल था:

"समुदाय अपने विवेक से परियोजना डेवलपर को कार्बन बेचने के सभी अधिकार ट्रांसफर करता है और समुदाय कार्बन की बिक्री से किसी भी लाभ का दावा नहीं करेगा और उसे सिर्फ़ वार्षिक लीज़ पेमेंट के ज़रिए ही अपनी भूमि के इस्तेमाल का मुआवजा दिया जाएगा।"

आस-पास के गाँव में चुनौतियों के बारे में उन्होंने जो सुना, उसे देखते हुए, समुदाय ने एक स्थानीय संगठन से संपर्क किया, जिसे मूल निवासी लोगों को सलाह देने का अनुभव है। संगठन ने संविदा की समीक्षा की और इसके बजाय इस भाषा का सुझाव दिया:

"परियोजना से होने वाले कुल राजस्व का 50% सामुदायिक ट्रस्ट को बांटा जाएगा। ट्रस्ट में समुदाय के 3 सदस्य, 4 अवलोकनकर्ता, 3 स्वतंत्र प्रतिनिधि और परियोजना डेवलपर का प्रतिनिधित्व करने वाला 1 सदस्य शामिल होगा। परियोजना डेवलपर प्रतिनिधि को सामुदायिक हिस्से के इस्तेमाल से जुड़े फ़ैसले पर वोट करने की अनुमति नहीं दी जाएगी और इसके बजाय वे पर्यवेक्षक की भूमिका निभाएँगे। समुदाय के हिस्से के इस्तेमाल पर फ़ैसले बड़े समुदाय की सहमति से समुदाय के प्रतिनिधि पेश करेंगे। सामुदायिक ट्रस्ट को ट्रस्ट फ़ंड के इस्तेमाल का वार्षिक लेखा-जोखा सभी स्थानीय भाषाओं में सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराना चाहिए।"

परियोजना

बातचीत के दौरान, समुदायों को इस तरह के बयान सुनने को मिल सकते हैं:

> "आपका प्रस्ताव आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं है।"
> "इससे पहले कि हम समुदायों के साथ फ़ायदे साझा कर सकें, हमें पहले अपना निवेश रिकवर करना होगा।"
> "हम उस बिंदु पर नहीं पहुंचे हैं जहां परियोजना मुनाफा कमा रही है।"

ये शब्द तकनीकी लगते हैं, लेकिन इसका जवाब प्रभावी ढंग से देने के लिए आप मूलभूत जानकारी का इस्तेमाल कर सकते हैं।

1. **लिखित रूप में अपेक्षित राजस्व का अनुमान मांगें।** आपके लिए उचित मुआवजा क्या है यह सुनिश्चित करने के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण जानकारी हैं। परियोजना की वित्तीय जानकारी में खो जाने के बजाय, आप कुल आमदनी के प्रतिशत के तौर पर समुदाय के हिस्से पर बातचीत करके चीज़ों को सरल बना सकते हैं। इससे यह पक्का होता है कि समुदाय का हिस्सा साफ़ तौर पर तय हो और परियोजना की लागत और खर्चों में किसी भी बदलाव के बावजूद, उसका भुगतान किया जाएगा।
2. **ऑफ़र के असंतुलित होने के संकेतों की तलाश करें।** क्या ज़्यादातर राजस्व परियोजना डेवलपर को जा रहा है? राजस्व के बंटवारे से पता चलेगा कि दोनों पक्ष परियोजना में क्या लेकर आ रहे हैं। समुदायों के लिए, इसमें उनकी भूमि, पारिस्थितिकी तंत्र की गहरी जानकारी और अकसर श्रम शामिल है, जो परियोजना की सफलता के लिए ज़रूरी होता है। परियोजना डेवलपर स्टार्ट-अप की लागत, तकनीकी क्षमता और कई मामलों में परियोजना को लागू करने, कार्बन स्टॉक की निगरानी करने और कार्बन मानक निकाय को रिपोर्ट करने की ज़िम्मेदारी के लिए निधियन ला सकते हैं। इसके अलावा इन बातों पर नज़र रखें:

    - समुदाय को भुगतान तभी शुरू करना जब परियोजना खर्च की पुनःप्राप्ति कर ले और मुनाफा कर रहा हो। इसमें कई साल लग सकते हैं। इसमें हेर-फेर भी किया जा सकता है, क्योंकि परिचालन लागत को ट्रैक करना और उसका आकलन करना मुश्किल होता है।
    - डेवलपर या पार्टनर का हिस्सा जो उच्च राशि पर तय किए गए हैं, जबकि सामुदायिक हिस्सा बाज़ार की कीमतों के साथ जुड़ा होता है। इससे समुदायों पर वित्तीय जोखिम बढ़ जाता है।

3. समय के साथ स्थिरता सुनिश्चित करें। समुदायों को परियोजना से पूरी अवधि के दौरान राजस्व मिलना चाहिए।

परियोजना प्रमाणित होने से पहले क्रेडिट बेचना शुरू करने में आमतौर पर कई साल लग जाते हैं। इसका मतलब है कि परियोजना डेवलपर को लागत कवर करने के लिए निवेश सुरक्षित रखना होता है, जब तक कि परियोजना को बनाए रखने के लिए क्रेडिट सेल से पर्याप्त राजस्व न आ जाए - यह बहुत मुश्किल काम है। शुरुआती लागतों को कवर करने की चुनौती को देखते हुए, डेवलपर सुझाव दे सकते हैं कि समुदायों को भुगतान सिर्फ़ फ़ायदा होने पर ही शुरू किया जाए या वे पैसे जुटाने के लिए कम कीमत पर क्रेडिट को पहले से बेच सकते हैं।

जाँचें कि क्या:

- समझौते पर हस्ताक्षर होते ही सामुदायिक हिस्से के लिए भुगतान शुरू हो जाते हैं।
- अगर कार्बन क्रेडिट की कीमतें गिरती हैं, तो इस समझौते में समुदायों या रिज़र्व को न्यूनतम वार्षिक भुगतान शामिल है।
- कार्बन क्रेडिट उचित बाज़ार मूल्य पर बेचे जाएंगे - यानी ज़्यादा कीमत जिससे कमाई बढ़ जाती है।

व्यवहारिक सुझाव:
समुदाय परियोजना की शुरुआत से ही भुगतान की मांग कर सकते हैं और करना चाहिए, भले ही कार्बन क्रेडिट की बिक्री से होने वाली कमाई अभी तक आई हो या नहीं। भूमि के इस्तेमाल में बदलाव के कारण किसी भी खोई हुई आय या संसाधनों तक पहुँच को ऑफ़सेट करने के लिए समुदायों को अग्रिम भुगतान करना ज़रूरी है। परियोजना की शुरुआती लागतें डेवलपर की ज़िम्मेदारी का हिस्सा होती हैं और यह सामुदायिक फ़ायदों में देरी करने का कोई सही कारण नहीं है।

III. सामान्य चुनौतियां और प्रभावी ढंग से बातचीत करने के लिए सुझाव

A. कई कार्रवाई करने वालों के साथ काम करना

कार्बन परियोजना में कई कार्रवाई करने वाले शामिल हो सकते हैं, जिनमें मुख्य परियोजना डेवलपर, निवेशक या मार्केटर्स और कुछ मामलों में सरकारी एजेंसियां शामिल हैं। इससे किसी समझौते पर पहुँचना जटिल हो सकता है और बातचीत में समुदायों और अन्य पक्षों के बीच सत्ता की गतिशीलता बढ़ सकती है। यह समझना ज़रूरी है कि हर कार्रवाई करने वाला कौन है और परियोजना में वे क्या भूमिका निभाएँगे। अगर इसमें कई कार्रवाई करने वाले शामिल हैं, तो ऐसे अतिरिक्त सुरक्षा उपाय भी हैं जिन पर समुदायों को विचार करना चाहिए।

- **परियोजना डेवलपर या प्रस्तावक:** परियोजना डेवलपर परियोजना को स्थापित करता है और उसे लागू करता है। वे यह पक्का करने के लिए ज़िम्मेदार हैं कि परियोजना राष्ट्रीय कानून और कार्बन मानक के तहत सभी ज़रूरतों को पूरा करे, जिसके तहत इसे प्रमाणित किया जाएगा। परियोजना कार्यान्वयन अनुबंध में परियोजना डेवलपर मुख्य पक्ष होता है। समझौते के तहत, उन्हें सहमत सुरक्षा उपायों, साझेदारी की प्रतिबद्धताओं और फ़ायदों के बदले भूमि के मालिकों और किसी भी अन्य प्रमुख हितधारक से क्रेडिट ट्रेड करने का अधिकार मिलेगा। किसी भी सह-प्रस्तावक या संयुक्त कार्यान्वयनकर्ता को भी समझौते का हस्ताक्षरकर्ता होना चाहिए। अगर परियोजना के प्रस्तावक की कोई मूल कंपनी है, तो तय करें कि स्पष्टता या ज़्यादा जवाबदेही के लिए उन्हें भी समझौते पर हस्ताक्षर करने की ज़रूरत है।
- परियोजना को लागू करने के लिए **निवेशक** वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराते हैं, ख़ासकर शुरुआती चरण में, इससे पहले कि कार्बन क्रेडिट की बिक्री लागत को कवर कर सकती है। कुछ मामलों में निवेशक परियोजना डेवलपर को तकनीकी सहायता भी देते हैं। आमतौर पर, निवेशक परियोजना कार्यान्वयन समझौते में शामिल नहीं होते हैं। हालाँकि, उनका आमतौर पर परियोजना के प्रस्तावक के साथ एक अलग समझौता होता है और वे अपने निवेश पर ऐसी शर्तें निर्धारित कर सकते हैं जिन्हें परियोजना प्रस्तावक को पूरा करना होगा (उदाहरण के लिए, एक निश्चित समय सीमा के भीतर निवेश पर खास रिटर्न की गारंटी देना)।

- **तीसरे पक्ष के मार्केटर्स** परियोजना प्रोपोनेंट की ओर से ख़रीदारों को क्रेडिट बेचते हैं। उनकी भूमिका परियोजना का प्रचार करना, संभावित खरीदारों के साथ संबंध विकसित करना और क्रेडिट का अच्छा मूल्य प्राप्त करना है। अगर परियोजना किसी मार्केटर या ब्रोकर का इस्तेमाल कर रहा है, तो एक अलग परचेज़ संविदा होगा, जो किसी भी क्रेडिट सेल पर मार्केटर के कमीशन को परिभाषित करेगा और परियोजना के प्रस्तावक पर अन्य शर्तें भी सेट कर सकता है।

  समुदायों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि परियोजना कार्यान्वयन समझौते (या समुदाय और परियोजना डेवलपर के बीच अनुबंध) की शर्तों को प्राथमिकता दी जाए और परियोजना के प्रस्तावक द्वारा अन्य कार्रवाई करने वालों के साथ साइन किए गए किसी भी अनुबंध को हटा दिया जाए। समुदायों को किसी भी मार्केटिंग संविदा पर हस्ताक्षर करने से पहले उनकी समीक्षा करने और उन्हें मंज़ूरी देने की मांग करनी चाहिए।

- **सरकारी एजेंसियां:** ज़्यादातर परियोजना के लिए, सरकार की भूमिका एकनियामक के रूप में होती है, जो परियोजना के पंजीकरण या अनुमति के लिए ज़रूरी शर्तें तय करता है और जवाबदेही पक्का करने के लिए उसकी निगरानी करता है। उन्हें समझौते का हस्ताक्षरकर्ता नहीं होना चाहिए और न ही उन्हें समुदायों और परियोजना डेवलपर के बीच बातचीत में शामिल होना चाहिए। उन्हें केवल तभी हस्तक्षेप करने की आवश्यकता होती है जब स्वतंत्र, पूर्व सूचित सहमति जैसे सुरक्षा उपायों का सम्मान नहीं किया जाता है।

  कुछ मामलों में, एक सरकारी एजेंसी परियोजना डेवलपर या परियोजना के समर्थकों में से एक हो सकती है, अगर परियोजना एक संरक्षित क्षेत्र शामिल है, राज्य के स्वामित्व या प्रबंधन वाली भूमि पर स्थित है, या क्षेत्राधिकार REDD+ परियोजना है। अगर ऐसा है, तो इससे बातचीत पर बहुत असर पड़ेगा। सकारात्मक पहलू पर, हो सकता है कि सरकार पहले से ही समुदायों के लिए एक निर्धारित राजस्व हिस्से के लिए प्रतिबद्ध हो, स्थानीय समुदायों के साथ सह-प्रबंधन के लिए उसकी मौजूदा नीतियां हों, और समझौते की शर्तों का अनुपालन करने के लिए वह ज़्यादा जवाबदेह हो।

  दूसरी तरफ़, सरकार की भागीदारी से आमदनी सुरक्षित करने पर दबाव पड़ता है और अक्सर समुदायों के लिए उपलब्ध हिस्से में कमी आती है। कई संदर्भों में, सरकार की भागीदारी से समुदायों के लिए अपनी शर्तों पर बातचीत करना कठिन हो जाता है और ऐसे संदर्भों में जहां समुदायों के पास स्पष्ट भूमि अधिकार नहीं हैं, उन्हें बेदख़ल करने का जोखिम हो सकता है। अगर आपके संदर्भ में ऐसा है, तो कार्बन मानकों में आवश्यकताएँ कुछ सुरक्षा प्रदान कर सकती हैं।

जब कई कार्रवाई करने वाले बातचीत में शामिल होते हैं, तो इससे समुदायों के लिए अतिरिक्त जोखिम पैदा हो जाते हैं, लेकिन अगर समुदाय इसमें शामिल अलग-अलग कार्रवाई करने वालों को समझकर संयुक्त नीति पेश करने के लिए संगठित होते हैं, तो इन जोखिमों को कम किया जा सकता है। प्रभावी ढंग से जुड़ने के लिए:

- **शक्ति विश्लेषण करें।** इसमें शामिल सभी कार्रवाई करने वालों और परियोजना के बारे में उनकी रुचियों, भूमिकाओं और निर्णय लेने के अधिकारियों को पहचानें। इससे आपको अपनी मांगों को तय करने और उनसे प्रभावी तरीके से जुड़ने के बारे में रणनीति बनाने में मदद मिलेगी। कुछ कार्रवाई करने वालों को सहयोगी या चैंपियन के रूप में शामिल करने के अवसर भी हो सकते हैं। इस टूल किट में पावर मैपिंग के बारे में सैक्शन देखें जहाँ आप उपयोग योग्य व्यवहारिक टूल्स पाएंगे।
- **इंडीजिनस पीपल्स ऐक्शन प्लान या स्वतंत्र, पूर्व, सूचित सहमति प्रोटोकॉल जैसे** सामुदायिक प्रोटोकॉल विकसित करें। ये टूल अपेक्षाओं का दस्तावेजीकरण कर सकते हैं, जिन पर समझौता संभव नहीं उन चीज़ों को परिभाषित कर सकते हैं और बातचीत के लिए प्रक्रिया तैयार कर सकते हैं। पृ. 70 पर सामुदायिक प्रोटोकॉल का बातचीत पर नियंत्रण पाने के लिए उपयोग करने के तरीकों के आइडिया देखें।

- **प्रतिनिधियों को पहचानें और इसमें शामिल समुदायों के बीच** एकता बनाए रखें। स्पष्ट रूप से परिभाषित निर्णय लेने की प्रक्रिया स्थापित करें, जिसमें आधिकारिक प्रतिनिधि हों जो समुदाय की ओर से बातचीत करेंगे और किस तरह से विस्तृत समुदाय यह निर्णय लेगा कि अंतिम शर्तें स्वीकार करनी हैं या नहीं। पूरी प्रक्रिया के दौरान, अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए, इसमें शामिल सभी समुदायों में एक साथ मिलकर एक संयुक्त मोर्चा पेश करें और सौदेबाज़ी करें।

कई मामलों में, समुदाय की ओर से भी कई ग्रुप शामिल होते हैं। अपनी तरफ़ से, पक्का कर लें कि आपने पहचान लिया है कि समुदायों के लिए वैध हस्ताक्षरकर्ता कौन है। यह एक मौजूदा सामुदायिक शासन निकाय होना चाहिए जिसे स्थानीय अधिकार धारक वैध मानते हैं। बातचीत करने वाली टीम को इसमें शामिल सभी समुदायों के लिए निष्पक्ष, वैध प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना चाहिए और महिलाओं, युवाओं और ऐसे किसी भी अन्य सामाजिक समूह की प्राथमिकताओं को शामिल करने के लिए खास कदम उठाने चाहिए, जो निर्णय लेने से बाहर रहने के जोखिम में हो सकते हैं।

B. फूट डालो और जीत हासिल करो की रणनीतियां

समुदायों के पास बातचीत करने की सबसे बड़ी ताकत होती है, जब वे सामूहिक रूप से और एक संयुक्त गुट के रूप में बातचीत करते हैं। परियोजना डेवलपर समुदायों की स्थिति कमज़ोर करने के लिए उनको बांटने की कोशिश कर सकते हैं। यह अलग-अलग रूप ले सकता है। उदाहरण के लिए, परियोजना डेवलपर, परियोजना के क्षेत्र में अलग-अलग समुदायों के साथ अलग-अलग समझौते कर सकता है। अगर हर समुदाय व्यक्तिगत रूप से बातचीत करता है, तो उनके पास क्षमता कम होती है और डेवलपर दूसरे समुदायों पर सबसे कमज़ोर समझौते की शर्तों पर सहमत होने के लिए दबाव डाल सकता है।

वैकल्पिक रूप से, डेवलपर समुदाय के प्रतिनिधियों को चुनने की कोशिश कर सकता है या अलग-अलग सामुदायिक संस्थानों में से किसी एक को चुन सकता है कि वे किस निकाय के साथ बातचीत करना चाहते हैं। इससे डेवलपर का बातचीत कर रही टीम पर प्रभाव होने का या फिर उनके किसी ऐसे सामुदायिक निकाय को चुनने का जोखिम हो सकता है जिसका परियोजना में एक खास हित हो। यह उन कई तरीकों में से एक है जिन से डेवलपर समुदाय के विभिन्न हितों में से एक का फायदा उठाने का प्रयास कर सकता है।

अगर समुदाय सामूहिक सौदेबाजी का तरीका अपनाते हैं, तो वे सबसे मज़बूत स्थिति में होंगे:

- मुख्य प्राथमिकताओं को समाने वाली साझा माँगों पर संरेखित हों।
- सहमत हों कि जब तक समझौते की शर्तों पर सामूहिक सहमति नहीं बन जाती, तब तक ना ही कोई भी समुदाय और न ही किसी समुदाय का कोई भी सदस्य समझौते पर हस्ताक्षर करेगा।
- बातचीत करने वाली एक टीम बनाएं जिसमें सभी सामाजिक समूहों का प्रतिनिधित्व हो।
- बातचीत टीम से नियंमित संचार और रिपोर्टों का वचन दें।
- बातचीत के दौरान समुदायों में या फिर समुदाय के भीतर के विभिन्न समूहों से अलग-अलग दृष्टिकोण की अपेक्षा करें और सभी आवाज़ों को सुनने और संयुक्त रूप से अगले चरण पर सहमित करने के लिए स्थान का निर्माण करें।

किसी बड़े परियोजना क्षेत्र में समन्वय करना और एक साथ काम करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। जब परियोजना में एक बड़े क्षेत्र में बड़ी संख्या में समुदाय शामिल होते हैं, तो समुदायों के समूह बनाने पर विचार करें। समुदायों का हर समूह इकट्ठा होकर, सभी समूहों की प्राथमिकताओं पर सहमत हो सकता है। इसके बाद बातचीत करने वाली टीम एक एकीकृत स्थिति तैयार कर सकती है, जिस पर सभी क्लस्टर सहमत हों और साथ मिलकर आगे बढ़ सकें।

बातचीत के दौरान चाहे जो भी चुनौतियाँ आएं, याद रखें कि ज्यादातर मामलों में **आपके पास बातचीत को रोकने या ना कहने की ताकत है** और आवश्यकता होने पर आप पूरी तरह से बातचीत से दूर हट सकते हैं।

समझौते पर हस्ताक्षर करने से पहले

परियोजना समझौते के अंतिम मसौदे की समीक्षा करते समय इन बातों पर ध्यान दें:

1. **पार्टियां**
   - क्या संविदा में वे सभी कार्रवाई करने वाले शामिल हैं, जो परियोजना के प्रबंधन के लिए ज़िम्मेदार हैं?
   - क्या हर पक्ष की भूमिकाएँ और ज़िम्मेदारियाँ साफ़ तौर पर परिभाषित हैं? इसमें वे सुरक्षोपाय शामिल होने चाहिए जिनका सम्मान करने के लिए परियोजना डेवलपर वचन दे रहे हैं और समुदायों के निर्णय लेने और परियोजना संचालन में हिस्सा लेने के लिए स्पष्ट प्रक्रियाएं होनी चाहिए।

2. **परियोजना विवरण**
   - क्या मुख्य गतिविधियाँ और भूमि उपयोग पर पड़ने वाले किसी भी प्रभाव को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है और समुदायों को स्वीकार्य है?
   - क्या परियोजना की जगह और सीमाओं को समझौते में परिभाषित किया गया है? क्या सामुदायिक उपयोग के लिए सुरक्षित रहने वाले क्षेत्र की पहचान भी की गई है?
   - क्या परियोजना की अवधि तय की गई है? क्या संविदा छोटी अवधि के लिए है, जिसमें एक निर्धारित समय सीमा के साथ फिर से बातचीत की जाएगी और उसका नवीनीकरण किया जाएगा?

3. **ज़िम्मेदारियां और देयताएं**
   - क्या परियोजना डेवलपर और आपके समुदाय, दोनों की ज़िम्मेदारियाँ साफ़ तौर पर परिभाषित हैं? क्या आप समझौते के तहत अपने दायित्वों से संतुष्ट हैं (जैसे संधारणीय कटाई का उपयोग करना, संरक्षण क्षेत्रों को अलग रखना, कुछ संसाधनों का उपयोग सीमित करना, आदि)?
   - क्या आप भूमि या उन संसाधनों तक पहुँच खो देंगे जिन पर आप निर्भर हैं? अगर ऐसा है, तो कब तक?

- अगर कार्बन स्टॉक खो जाए, उदाहरण के लिए, इस्तेमाल की वजह से या जंगल की आग जैसी अनियोजित घटनाओं की वजह से, तो क्या होगा? क्या समुदाय को आर्थिक रूप से ज़िम्मेदार ठहराया जाता है?

4. राजस्व साझा करना और अन्य लाभ

- क्या समझौता स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है कि समुदायों को कितना और कब भुगतान किया जाएगा?
- राजस्व के समुदाय के हिस्से की निधि कैसे डिलिवर की जाएगी? पैसों के इस्तेमाल के बारे में फ़ैसले लेने को कौन नियंत्रित करेगा?
- क्या संविदा में अन्य लाभ (रोज़गार, अवसंरचना, प्रशिक्षण, आदि) स्पष्ट रूप से बताए गए हैं? क्या उनमें एक निर्धारित बजट और समय-सीमा शामिल है?
- क्या परियोजना डेवलपर के लिए कार्बन क्रेडिट सेल्स से होने वाली कमाई पर नियमित वित्तीय विवरण और रिपोर्ट साझा करने की आवश्यकता है?

समझौते पर हस्ताक्षर करने से पहले के अंतिम चरण के तौर पर, बातचीत करने वाली टीम को समझौते का अंतिम मसौदा समुदाय के पास विचार-विमर्श के लिए वापस लाना चाहिए। समुदाय द्वारा की जा रही प्रमुख प्रतिबद्धताओं, सामुदायिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए सुरक्षा उपाय, और राजस्व साझा करने की व्यवस्था और परियोजना डेवलपर द्वारा प्रदान किए जाने वाले किसी भी अन्य गैर-मौद्रिक लाभ पर सामूहिक सहमति की जाँच करें। जब आप विचार-विमर्श कर रहे हों, तो महिलाओं, युवाओं और अन्य अल्पसंख्यक समूहों के लिए जगह बनाएं, ताकि वे योगदान कर सकें और ऐसी किसी भी समस्या को उठा सकें, जिसका समाधान अंतिम समझौते में किया जाना चाहिए।

समझौते पर हस्ताक्षर हो जाने के बाद, मुख्य बिंदुओं को समुदाय में व्यापक रूप से साझा करें, ताकि हर कोई समझ सके कि किस बात पर सहमति हुई थी। अगर संभव हो, तो प्रिंट की हुई प्रतियाँ बांटें। समुदाय स्तर पर प्रतियाँ रखना भी ज़रूरी है। समुदाय में कोई भी अनुरोध करने पर आसानी से समझौते की एक कॉपी तक पहुँच सकता है। इसी तरह, आपको मार्केटर्स के साथ या परियोजना डेवलपर और सरकारी एजेंसियों या किसी अन्य तीसरे पक्ष के बीच हुए किसी भी समझौते की कॉपी अपने पास रखनी चाहिए।

सीमित भागीदारी और अस्पष्ट कार्बन अधिकारों की चुनौतियां: फ़िलीपीन्स में सैंटा मारिया समुदाय की केस स्टडी

रफ़ाएल पजारेस, ELAC के द्वारा

सैंटा मारिया समुदाय सेंट्रल फ़िलीपीन्स के एक पहाड़ी बारांगे (गाँव) में स्थित है। समुदाय की आबादी 600 निवासियों की है और यह कापिसानान सा माग ऊमा सांता मारिया (KAMS) लोगों के संगठन का घर है। 2000 में, KAMS को सरकार द्वारा समुदाय आधारित वन प्रबंधन (CBFM)[2] संविदा दी गई थी।

2023 में, एक ऑइल कंपनी द्वारा वित्त पोषित एक गैर-सरकारी संगठन ने कार्बन पुनःवनारोपण परियोजना के प्रस्ताव के साथ समुदाय से संपर्क किया।

न्याय की समस्या

परियोजना शुरू होने के बाद से, परियोजना में समुदाय की भूमिका, राजस्व के बंटवारे और कार्बन अधिकारों के स्वामित्व से जुड़ी समस्याएं रही हैं। समुदायों ने परियोजना लागू करने के लिए काम करने वाले समुदाय के सदस्यों को मिलने वाले मुआवज़े को लेकर चिंता जताई है। समुदाय ने एक और चिंता व्यक्त की, वह थी पुनर्वनीकरण परियोजना से होने वाले कार्बन क्रेडिट से होने वाले राजस्व में समुदाय के हिस्से के बारे में स्पष्टता का अभाव।

हालांकि परियोजना के सफल होने पर उन्हें फ़ायदे देने का वादा किया गया था, लेकिन समुदाय को यह जानकारी नहीं दी गई थी कि उन्हें क्या और कब मिलेगा। अभी तक, समुदायों को कोई भुगतान नहीं किया गया है। यहाँ तक कि डेवलपमेंट में शामिल समुदायों के सदस्यों के लिए वेतन और ट्री नर्सरी के रख-रखाव का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है। दूसरे समुदाय, जो एक ही परियोजना को दूसरे क्षेत्रों में लागू करते हैं, उन्हें भी इसी तरह के अनुभव हुए हैं।

2 समुदाय आधारित फ़ॉरेस्ट मैनेजमेंट एग्रीमेंट (CBFMA) पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन विभाग और लोगों के संगठन (PO) के बीच 25 साल का नवीकरणीय समझौता है। CBFMA समुदायों को एक निर्धारित क्षेत्र में वन संसाधनों के प्रबंधन, सुरक्षा और उपयोग का कानूनी अधिकार देता है, बशर्ते वे किसी स्वीकृत प्रबंधन योजना का पालन करें।

हालांकि समुदाय और परियोजना के प्रस्तावक के बीच एक संविदा होती है, लेकिन उस समझौते को तैयार करने में समुदाय का कोई हाथ नहीं था। असल में, समुदाय के प्रतिनिधि दावा करते हैं कि उन्हें तीस पन्नों के समझौते की समीक्षा करने और उस पर हस्ताक्षर करने के लिए सिर्फ़ कुछ मिनट दिए गए थे। पारदर्शिता की कमी और समुदाय की उचित भागीदारी के आभाव के कारण समुदाय के सदस्यों के बीच व्यापक अविश्वास पैदा हो गया है। कई समुदाय के नेताओं को डर है कि यदि परियोजना के समर्थक वितरित करने में विफल रहते हैं, तो अन्य सदस्य यह संकेत देंगे कि नेताओं ने लाभ अपने तक ही सीमित रखा है।

व्यापक स्तर पर, फ़िलीपीन्स में कार्बन रीफ़ॉरेस्टेशन परियोजनाओं के स्वामित्व के संबंध में स्पष्ट परिभाषाएं न होने से समुदायों के लिए महत्वपूर्ण जोखिम पैदा हो जाते हैं। सभी प्राकृतिक संसाधन राज्य के हैं, जिनमें वन क्षेत्र भी शामिल हैं। चूँकि CBFM के लाभार्थियों को भूमि पर मालिकाना हक नहीं दिया जाता है, वैसे ही उन्हें उनके द्वारा लगाए गए पेड़ों का मालिक नहीं माना जाता है। परिणामस्वरूप, जो समुदाय CBFM समझौते के तहत वन क्षेत्रों का प्रबंधन कर रहे हैं, वे अक्सर श्रमिकों के तौर पर कार्बन परियोजना में भाग लेने के लिए मजबूर हो जाते हैं या अगर राजस्व का कोई हिस्सा होता है, तो उन्हें कार्बन क्रेडिट राजस्व में सबसे छोटे साझा दिए जाते हैं।

सैंटा मारिया समुदाय की प्रतिक्रिया

समुदायों को पार्टनर के तौर पर देखा जाना चाहिए, न कि सिर्फ़ लाभार्थियों या कर्मचारियों के सदस्यों के तौर पर। इस मामले में, समुदाय परियोजना के बारे में निर्णय लेने का हिस्सा नहीं है और जिस समझौते पर उन्होंने हस्ताक्षर किए थे, वह किसी भी शर्त पर सहमत होने से पहले ही तैयार कर लिया गया था, जिससे उनके लिए बातचीत करने का कोई भी अवसर मिट जाएगा। इसने समुदाय के नेताओं को परियोजना कार्यान्वित करने वाले की ईमानदारी पर सवाल उठाने के लिए प्रेरित किया है। फिर भी, समुदायों को मिलने वाले फ़ायदों के बारे में साफ़ तौर पर बताने के लिए, उन्होंने परियोजना कार्यान्वित करने वाले से बातचीत जारी राखी हैं।

हालांकि अभी तक इसका कोई समाधान नहीं हुआ है, लेकिन समुदाय प्रभावी तरीके से जुड़ने के तरीके तलाश रहा है। हालांकि, फ़िलीपीन्स में कार्बन बाज़ार (कार्बन मार्केट) के लिए कानूनी ढांचा न होने की वजह से, लंबे और महंगे मुकदमेबाजी के बिना संविदा को चुनौती देने के कुछ ही रास्ते हैं। परियोजना कार्यान्वयनकर्ता प्रतिक्रिया देने में धीमा रहा है और उसने धीरे धीरे समुदाय से बातचीत काम भी की है

सैंटा मारिया केस फ़िलीपीन्स में कार्बन परियोजना में प्रणालीगत चुनौतियों को उजागर करता है — अपारदर्शी संविदा, सूचित सहमति का अभाव, और गैरवाजिब लाभ साझा करना। मज़बूत राष्ट्रीय नीतियों और पारदर्शिता के तंत्र के बिना, समुदाय शोषणकारी समझौतों के जोखिम में बने रहते हैं। पार्टनर समुदायों को कार्बन बाज़ार (कार्बन मार्केट) और संविदा वार्ताओं के संबंध में पर्याप्त जानकारी और प्रशिक्षण प्रदान करके, CSO अन्य समुदायों को उन स्थितियों से बचने में मदद कर सकते हैं, जहाँ उन्हें पार्टनर की तरह मानने के बजाय साधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है।

चरण 4: परियोजना समझौता लागू करना

किसी परियोजना डेवलपर के साथ निष्पक्ष, कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौता करना समुदायों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। फिर भी समुदायों का जुड़ाव यहीं खत्म नहीं होता है। समझौता हो जाने के बाद, कार्यान्वयन के बारे में जारी निर्णय लेने में भाग लेकर इसे जीवंत करना और अनुबंध में प्रतिबद्धताओं की सक्रिय रूप से निगरानी करके यह सुनिश्चित करना ज़रूरी है कि उन्हें पूरा किया जा रहा है।

I. परियोजना संचालन

परियोजना डेवलपर के साथ संविदा में निर्णय लेने और परियोजना प्रबंधन के लिए संचालन संरचना तय किए जाने चाहिए। अक्सर तीन तरह के संचालन निकाय होते हैं, जो परियोजना में अलग-अलग भूमिकाएँ निभाते हैं:

1. परियोजना डेवलपर के साथ एक संयुक्त प्रबंधन समिति, जो पूरे परियोजना क्षेत्र में कार्यान्वयन के बारे में प्रमुख निर्णयों और परियोजना की निगरानी के लिए ज़िम्मेदार है
2. समुदायों के राजस्व के हिस्से को प्रबंधित करने के लिए एक सामुदायिक ट्रस्ट
3. भूमि प्रबंधन के लिए सामुदायिक संस्थाएँ, जो समुदाय के सदस्यों द्वारा संसाधनों तक पहुँच और उपयोग की निगरानी करती हैं (उदाहरण के लिए, सामुदायिक उपनियमों को परिभाषित करके और उन्हें लागू करके)। कुछ मामलों में, ये संस्थान प्रकृति-आधारित परियोजना में संरक्षण गतिविधियों का प्रबंधन भी करते हैं।

पक्का करें कि समुदाय में हर कोई शासन के विशिष्ट ढांचों और परियोजना के लिए भूमिका निभाते हैं उसे समझते हैं। इन भूमिकाओं को किसी परियोजना समझौते पर बातचीत करने में साफ़ तौर पर परिभाषित किया जाना चाहिए। जैसे ही परियोजना शुरू हो जाता है, इन संस्थानों को परियोजना की समग्र अवधि में अपनी भूमिकाओं को प्रभावी ढंग से निभाने के लिए क्या आवश्यक है, इस पर करीब से नज़र डालें।

- **एक मज़बूत बुनियाद सेट करें:** प्रत्येक संचालन संरचना कैसे काम करेगी, इसके लिए स्पष्ट नियम तैयार करें, उदाहरण के लिए, किसी संविधान या उप-नियमों के ज़रिए, जो ज़िम्मेदारियों को परिभाषित करता है और निर्णय कैसे किए जाएंगे। इसके अलावा, यह तय करें कि ये संरचनाएँ किस तरह जानकारी साझा करेंगी और व्यापक समुदाय को वापस रिपोर्ट करेंगी। ऐसे किसी भी फ़ैसले की पहचान ज़रूर करें, जिसके लिए पूरे समुदाय की ओर से मंज़ूरी या सहमति की ज़रूरत हो।

- **प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण:** परियोजना संचालन संरचना या सामुदायिक संस्थानों में समुदाय के प्रतिनिधियों के लिए भूमि प्रबंधन के लिए यह ज़रूरी है कि वे सत्ता से जुड़ सकें। पहचानें कि आपके समुदाय के प्रतिनिधियों को इस बारे में प्रशिक्षण की ज़रूरत है या नहीं:

    - शासन करने के कौशल: संगठनात्मक प्रबंधन, जानकारी साझा करना और जवाबदेही की व्यवस्था, और सामूहिक निर्णय लेने में सुविधा प्रदान करना।
    - कानूनी साक्षरता: डेवलपर और किसी भी मार्केटर्स के साथ संविदा को समझना, परियोजना रजिस्टर करने और सरकार और कार्बन मानकों से अनुमोदन बनाए रखने के लिए परियोजना डेवलपर द्वारा पूरी की जाने वाली आवश्यकताओं की जानकारी, और शिकायतों को हल करने के लिए प्रक्रियाएं।
    - वित्तीय प्रबंधन: बजट बनाना, वित्तीय रिपोर्ट को समझना, खर्चों पर नज़र रखना, पारदर्शी रिकॉर्ड रखना।

आप परियोजना डेवलपर, भरोसेमंद सहयोगियों या उन अन्य समुदायों से प्रशिक्षण का अनुरोध कर सकते हैं, जिनके पास भूमि में निवेश का अनुभव है। अगर संभव हो, तो परियोजना के पहले 2 से 3 सालों में निरंतर क्षमता निर्माण के स्रोत ढूंढने की कोशिश करें। इससे यह पक्का होगा कि परियोजना कार्यान्वयन के दौरान आपने जो सीखा है उसे अमल में लाने में आपको मदद मिले।

समय के साथ जब समुदाय के नए प्रतिनिधि शासी निकाय या समितियों में आते हैं, तो वे मौजूदा या बाहर जाने वाले समुदाय के नेताओं से उन्हें सलाह देने के लिए कहते हैं, ताकि उन्हें अपनी नई भूमिकाओं में प्रभावी होने के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल प्रदान किए जा सकें।

- **जवाबदेही के लिए तंत्र:** इस बारे में सोचें कि आप शुरू से ही जवाबदेही कैसे सुनिश्चित करेंगे।

  समुदाय के प्रतिनिधियों के लिए

  - उनकी भूमिका और ज़िम्मेदारियों के बारे में बताएँ।
  - पक्का करें कि समुदाय के उन पर भरोसे और भूमिका को प्रभावी ढंग से पूरा करने की उनकी क्षमता के आधार पर प्रतिनिधि चुनने की कोई स्पष्ट प्रक्रिया हो। अलग-अलग भौगोलिक और सामाजिक समूहों के लिए भी प्रतिनिधित्व शामिल करें, जिसमें महिलाएं, युवा और कोई भी अल्पसंख्यक समूह शामिल हैं।
  - पहचानें कि गलत व्यवहार की किसी भी समस्या का समाधान कैसे किया जाएगा।
  - आवधिक पुनर्निर्वाचन या फिर हर कुछ सालों में नेतृत्व पदों पर परिवर्तन की योजना बनाएं।

  परियोजना डेवलपर के लिए

  - किसी भी विवाद या शिकायत को हल करने की प्रक्रिया पर सहमत हों।
  - जैसे ही समस्याएं और चिंताएं होती हैं, उन्हें डेवलपर के साथ सक्रियता से उठाएं।
  - अगर परियोजना डेवलपर जवाब देने में विफल रहता है या अनुबंध या अन्य कानूनों के तहत उन्हें पूरी होने वाली प्रतिबद्धताओं को बार-बार तोड़ता है, तो समस्याओं को संबंधित अधिकारियों के पास ले जाएं।

सबूत के समर्थन के साथ सीधा संचार अक्सर यह सुनिश्चित करने में बहुत उपयोगी होता है कि परियोजना डेवलपर चिताओं के लिए प्रतिक्रिया दे। और चाहे आप परियोजना डेवलपर से बात कर रहे हों या विनियामक अधिकारियों से, जो समस्याएँ हुई हैं, उनका स्पष्ट दस्तावेजीकरण ज़रूरी है। इस सेक्शन में बाद में हम समझौते की शर्तों की देखरेख करने के तरीकों और जहाँ वादे पूरे न किए जा रहे हों वहाँ दस्तावेज़ीकरण के लिए साक्ष्य इकट्ठा करने के बारे में और बात करेंगे।

II. फ़ंड पाने और मैनेज करने की तैयारी करना

उम्मीद है कि आप सफलतापूर्व अपने समुदाय के साथ स्वतंत्र रूप से अपने राजस्व के हिस्से के प्रबंधन के बारे में बात कर पाए। इससे समुदाय को इस बात पर सीधा नियंत्रण मिलता है कि निधि का इस्तेमाल कैसे किया जाए। इसका मतलब यह भी है कि निधि को सही तरीके से प्रबंधित किया जाए, यह पक्का करने के लिए आप सामूहिक रूप से ज़िम्मेदार हैं - जो कि चुनौतीपूर्ण हो सकता है।

ख़ुद को सफलता के लिए तैयार करने के लिए आप कई कदम उठा सकते हैं। निधि का इस्तेमाल कैसे किया जाएगा, यह तय करने के लिए और खर्च पर नज़र रखने और रिपोर्ट करने के लिए स्पष्ट प्रक्रियाओं को परिभाषित करने से भी बाद में जब पैसा आता है और उसे देना शुरू होता है, तो समुदाय के भीतर भ्रम या विवादों को रोका जा सकता है।

कानूनी और वित्तीय प्रणालियां स्थापित करें

- एक समर्पित सामुदायिक बैंक खाता खोलें, जिसमें कई हस्ताक्षरकर्ता हों।
- अगर उचित हो, तो किसी सामुदायिक ट्रस्ट या समुदाय-आधारित संघ जैसी कानूनी संस्था की स्थापना करें, जो समुदाय की ओर से आधिकारिक तौर पर निधि प्राप्त कर सके। ऐसी कोई भी संरचना समुदाय के स्वामित्व वाली होनी चाहिए, कंपनी द्वारा नहीं बनाई जानी चाहिए या सरकार द्वारा थोपी नहीं जानी चाहिए।
- एक संचालन समिति सेट करें, जो निधि का प्रबंधन करे और निगरानी की पारदर्शिता सुनिश्चित करे। इस समिति में ऐसे समुदाय के प्रतिनिधि शामिल होने चाहिए जिन पर पूरा भरोसा हो और जिन्हें वित्तीय प्रबंधन का अनुभव हो, अगर संभव हो।
- साफ़ तौर पर तय करें कि निधि के निश्चित इस्तेमाल के बारे में फ़ैसले कैसे किए जाएंगे - उदाहरण के लिए, क्या सामुदायिक समूह या गाँव खास परियोजना का प्रस्ताव दे सकते हैं, उनका मूल्यांकन कैसे किया जाएगा, और किन प्रस्तावों के लिए फ़ंड देना है, इस पर अंतिम फ़ैसला कौन करता है।

एक समुदाय के तौर पर निधि के इस्तेमाल के लिए एक प्लान तैयार करें

- एक समुदाय के तौर पर या समुदायों के समूह में मिलकर प्राथमिकताओं (जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, आजीविका) को पहचानें।
- इस बारे में चर्चा करें कि क्या सामूहिक परियोजना (जैसे स्कूल, क्लीनिक, अन्य अवसंरचना) और परिवारों को सीधे भुगतान शामिल करना है या नहीं।
- जितना हो सके, समुदाय के विकास में मदद करने के लिए निधि का सबसे अच्छा इस्तेमाल कैसे किया जाए, यह तय करने के लिए सहभागी तरीकों (ज़रूरतों का आकलन, रैंकिंग, वोटिंग) का इस्तेमाल करें।

पारदर्शिता सुनिश्चित करें

- नियमित रूप से (क) परियोजना डेवलपर से प्राप्त भुगतानों और (ख) सामुदायिक फ़ंड से प्राप्त राशियों के बारे में जानकारी समुदाय के सदस्यों के साथ साझा करें। इसे कम से कम हर साल किया जाना चाहिए (उदाहरण के लिए, किसी सामुदायिक सभा के ज़रिए) और अनुरोध करने पर यह समुदाय के किसी भी सदस्य को भी उपलब्ध होना चाहिए।
- अगर संभव हो, तो सामुदायिक निधि का कम से कम हर तीन साल में स्वतंत्र वित्तीय ऑडिट करवाएं।

हर 3 से 5 साल में समीक्षा करें और अपडेट करें

- मॉनिटर करें कि निधि इच्छित लाभार्थियों तक पहुँच रही है या नहीं।
- बदलती प्राथमिकताओं या ज़रूरतों को दर्शाने के लिए हर कुछ सालों में निधि का इस्तेमाल कैसे किया जाएगा, इस बारे में सामुदायिक समझौता फिर से देखें।

समुदाय के राजस्व के हिस्से को प्रबंधित करना

यह फ़्लोचार्ट समुदायों को एक स्पष्ट प्लान तैयार करने में मदद करने के लिए डिज़ाइन किया गया है कि किसी कार्बन परियोजना से उनके राजस्व के हिस्से को कैसे प्रबंधित किया जाए।

1. कुल कितने पैसे उपलब्ध हैं?

परियोजना डेवलपर या सामुदायिक ट्रस्ट से अप-टू-डेट वित्तीय विवरणों का अनुरोध करें और निधि का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है, इस पर किसी भी नियंत्रण की पहचान करें।

2. निधि के इस्तेमाल की सबसे पहली प्राथमिकताएं क्या हैं?

सामूहिक रूप से प्राथमिकताओं को पहचानने के लिए, इस पर विचार करें:

- शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, इंफ्रास्ट्रक्चर, या अन्य क्षेत्रों जैसी व्यापक श्रेणियों की ज़रूरतों और प्राथमिकताओं की पहचान करने के लिए मौजूदा सामुदायिक बैठकों का उपयोग करना।
- अलग-अलग सामाजिक समूहों से मिलना, ताकि उनकी मुख्य प्राथमिकताओं को समझा जा सके।
- ज़्यादा जानकारी पाने के लिए, समर्पित सामुदायिक परामर्श (जैसे कि सामुदायिक सभा) आयोजित करना।
- समुदायों के लिए विचार-विमर्श करने या वोट करने के लिए विकल्पों का एक सेट पेश किया जा रहा है।

विचारों को जनरेट करने के लिए मौजूदा मीटिंग स्पेस में व्यापक श्रेणियों, जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं, या इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में चर्चा करके शुरुआत करना मददगार हो सकता है। सामुदायिक निधि का प्रबंधन करने वाली समिति उस इनपुट का इस्तेमाल उन विकल्पों को विकसित करने के लिए कर सकती है, जिन्हें वे विचार-विमर्श और सामूहिक निर्णय लेने के लिए व्यापक समुदाय में वापस ला सकते हैं।

3. हर श्रेणी के लिए कितनी निधि दी जाएगी?

एक बार जब आप सामूहिक रूप से प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान कर लें, तो यह निर्धारित कर लें कि प्रत्येक के पास निधि का कितना हिस्सा जाएगा। स्वास्थ्य या शिक्षा जैसी व्यापक श्रेणियों के अलावा, इस बात पर भी विचार करें कि इन्हें मिलने वाली राशि को संतुलित कैसे किया जाए:

- परिवारों को सीधे भुगतान (अगर ज़रूरी हो) और सामूहिक विकास परियोजना
- तत्काल ज़रूरतें बनाम बड़ी या लंबी अवधि के निवेश
- परियोजना क्षेत्र के अलग-अलग भौगोलिक क्षेत्र या सामाजिक समूह — निधि पूरे समुदाय में समान रूप से कैसे वितरित की जाएगी?

4. किन दिशा-निर्देशों से निधि के लिए खास परियोजना के प्रस्ताव और चयन के बारे में जानकारी मिलेगी?

- आपने जिन अलग-अलग श्रेणियों की पहचान की है, उनमें खास निवेश या निधियन प्रस्तावों के बारे में निर्णय लेने की प्रक्रिया तैयार करें। क्या समुदाय के सदस्य या गाँव खास परियोजना के लिए प्रस्ताव सबमिट करेंगे? अगर ऐसा है, तो प्रस्तावों में क्या-क्या शामिल होना चाहिए, कौन तय करेगा कि किन अनुरोधों के लिए निधि दी गई है, और परियोजना चुनते समय वे किन मानदंडों पर विचार करेंगे?
- इसके अलावा, निधि के इस्तेमाल पर नज़र रखने के लिए सरल प्रक्रियाओं को परिभाषित करें - यानी हर उद्देश्य के लिए कितना खर्च किया गया था और खर्चों का दस्तावेजीकरण करने के लिए कौन से रिकॉर्ड रखे जाएंगे?
- आखिर में, यह पक्का कर लें कि परियोजना को प्रपोज़ करने और उन पर निर्णय लेने में शामिल हर व्यक्ति इस प्रक्रिया में आने वाले चरणों और अपनी खास जिम्मेदारियों को समझता हो। समुदाय के सदस्यों को इस प्रक्रिया के बारे में नियमित रूप से याद दिलाएं, आदर्श रूप से साल में कम से कम दो बार।

5. समय के साथ खर्च करने की योजनाओं की समीक्षा कैसे की जाएगी और उन्हें अपडेट कैसे किया जाएगा?

निधि के इस्तेमाल के लिए, सामुदायिक योजना की नियमित समीक्षाएं और अपडेट की योजना बनाएं। उदाहरण के लिए, हर तीन साल में, आप यह साझा करने का निर्णय ले सकते हैं कि आज तक धन का उपयोग कैसे किया गया है और समुदाय के सदस्यों के लिए सामूहिक रूप से निधि प्राथमिकताओं या परियोजनाओं पर निर्णय लेने की प्रक्रिया के पुनर्गठन पर चर्चा कर सकते है। इससे समुदाय को सामूहिक रूप से यह सोचने का मौका मिलता है कि यह प्रक्रिया आज तक कैसी रही है और जो भी नई ज़रूरत सामने आई है, उस पर विचार करने का।

III. समझौते की शर्तों की निगरानी करना और उन्हें लागू करना

एक सफल साझेदारी के लिए उचित समझौता प्राप्त करना एक आवश्यक आधार है, फिर भी यह सिर्फ़ शुरुआत है। परियोजना की गतिविधियां शुरू होने पर, समुदायों को समय-समय पर निगरानी रखनी चाहिए कि परियोजना डेवलपर संविदा की शर्तों और राष्ट्रीय कानून और अंतरराष्ट्रीय कार्बन मानकों के तहत अन्य प्रमुख ज़रूरतों का अनुपालन कर रहा है या नहीं। महत्वपूर्ण प्रावधानों की सक्रियता से निगरानी करके, आप उन्हें व्यवहार में ला सकते हैं। इससे आप चुनौतियों को जल्दी पहचान सकते हैं और यह पक्का कर सकते हैं कि सभी प्रतिबद्धताओं का पूरा सम्मान किया जाए।

कार्यान्वयन की निगरानी करते समय, उन प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान दें, जो समुदायों को सीधे प्रभावित करते हैं, खासकर:

- भूमि का उपयोग और स्थानीय पारिस्थितिक तंत्र पर पड़ने वाले प्रभाव,
- स्थानीय समुदायों के लिए पहुँच और इस्तेमाल के अधिकार,
- वित्तीय पारदर्शिता और राजस्व साझा करना, और
- विवाद या शिकायत

प्रकृति-आधारित परियोजनाओं के लिए, यह आकलन करना भी ज़रूरी है कि संरक्षण की प्रतिबद्धताओं का सम्मान किया जा रहा है या नहीं, जिसमें परियोजना डेवलपर, समुदाय के सदस्य और समुदाय से बाहर के अन्य लोग शामिल हैं, जो नियमित रूप से स्थानीय भूमि या संसाधनों का उपयोग करते हैं।

पहले चरण के तौर पर, आप दोनों द्वारा साइन की गई संविदा में परियोजना डेवलपर द्वारा प्रतिबद्ध खास अनिवार्य आवश्यकताओं को पहचानें। उदाहरण के लिए, इसमें वे गतिविधियाँ शामिल हो सकती हैं, जिन्हें परियोजना डेवलपर ने सामुदायिक भूमि पर लागू करने की योजना बनाई है, समुदायों के पास उपयोग या प्रबंधन अधिकार हैं, और राजस्व साझा करने के प्रति प्रतिबद्धताएं शामिल हो सकती हैं।

तथ्यों की जांच के प्रावधानों की पहचान करने के बाद, सबूत इकट्ठा करने के लिए सरल तरीकों का इस्तेमाल करें। जहाँ भी संभव हो, ऐसे सबूतों पर ध्यान दें, जिन्हें दस्तावेज़ीकृत करना और सत्यापित करना आसान हो। क्या ऐसी कोई खास ज़रूरतें हैं जिनकी दृश्य निरीक्षण के ज़रिए तथ्यों की जाँच की जा सकती है? अगर ऐसा है, तो वे शुरू करने के लिए एक अच्छी जगह हो सकती हैं क्योंकि समुदाय के सदस्य सीधे आकलन कर सकते हैं और उन पर टाइम स्टैम्प और जियोलोकेशन वाली तस्वीरों के ज़रिये सबूत दस्तावेज़ीकृत कर सकते हैं।

समस्याएँ आने से पहले, समय-समय पर मुख्य क्षेत्रों पर सक्रियता से नज़र रखने की योजना बनाएं। परियोजना के शुरुआती चरण में यह साल में कई बार हो सकता है और समय के साथ इसमें बदलाव कम हो सकता है। निरीक्षण से समुदाय की सामूहिक निगरानी और परियोजना के विभिन्न पहलुओं पर क्षमता निर्माण का अवसर मिलता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इससे आप समस्याओं को जल्दी पहचान सकते हैं और उनका समाधान कर सकते हैं और सबूत इकट्ठा कर सकते हैं, जिनका इस्तेमाल अगल परियोजना डेवलपर समस्या सा समाधान न करे तो आप सरकारी नियामक एजेंसियों या कार्बन मानक के ज़रिए किसी समस्या का समाधान करने के लिए कर सकते हैं।

आइए उन खास पहलुओं पर करीब से नज़र डालें, जिन पर आप नज़र रखना चाहेंगे और उन टूल और तरीकों पर भी नज़र डालें, जो हर एक के लिए उपयोगी हो सकते हैं।

1. **परियोजना की गतिविधियाँ और भूमि का उपयोग:** जाँच करें कि क्या परियोजना में मुख्य गतिविधियाँ योजना के अनुसार और उन जगहों पर हो रही हैं जिन पर सहमति हुई है। इसमें परियोजना डेवलपर द्वारा भूमि का उपयोग, संरक्षण गतिविधियाँ जिनके लिए वे ज़िम्मेदार हैं, और आजीविका सहायता शामिल है, जिसके लिए उन्होंने सहमति दी है। परियोजना डेवलपर की रिपोर्ट और स्थानीय समुदायों द्वारा विज़ुअल अवलोकन की तुलना परियोजना समझौते में की गई प्रतिबद्धताओं से करें। भूमि या प्राकृतिक संसाधनों के कार्यान्वयन या संभावित दुरुपयोग में किसी भी कमी को पहचानें।
2. **प्राकृतिक संसाधनों तक पहुँचने और उनका इस्तेमाल करने के सामुदायिक अधिकार:** निरीक्षण करें कि परियोजना भूमि, पानी, जंगल, चराई की जगह और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मदद करने वाले अन्य संसाधनों तक पहुँच को कैसे प्रभावित कर रहा है। खास तौर पर, ऐसे किसी भी उदाहरण का दस्तावेजीकरण करें, जहां समुदाय के सदस्यों को परियोजना समझौते के तहत उन संसाधनों को पहुँच करने या उनका इस्तेमाल करने की क्षमता से वंचित किया जाता है, जिनके पास उनके अधिकार हैं।

3. **सामुदायिक उपनियम या पर्यवेक्षण प्रतिबद्धताएं:** समुदायों के लिए यह देखना भी ज़रूरी है कि वे ख़ुद अनुबंध में निर्धारित प्रतिबद्धताओं को कैसे पूरा कर रहे हैं, जिसमें उप-नियमों का सम्मान करना और सहमति के अनुसार संसाधनों का प्रबंधन करना शामिल है। इन तत्वों की निगरानी करने से यह पता चलता है कि समुदाय अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभा रहा है या नहीं और परियोजना में अन्य समस्याओं के बारे में चिंता जताते समय स्पष्टता मिलती है।
4. **वित्तीय पारदर्शिता और राजस्व साझाकरण:** आकलन करें कि संविदा में सहमति के अनुसार परियोजना से भुगतान और कोई अन्य लाभ दिए जा रहे हैं या नहीं। इसके अलावा, समुदायों को यह भी ट्रैक करना चाहिए कि सामुदायिक राजस्व के हिस्से का इस्तेमाल कैसे किया जा रहा है और क्या यह उन प्राथमिकताओं से मेल खाता है जिन्हें समुदायों ने पहचाना है। इन तत्वों की निगरानी करने से समुदायों को यह सत्यापित करने में मदद मिलती है कि राजस्व साझा करने और अन्य लाभों से संबंधित प्रमुख प्रावधान पूरे हुए हैं या नहीं और अगर विसंगतियां दिखाई देती हैं, तो चिंता जताने या स्पष्टीकरण का अनुरोध करने का आधार प्रदान करता है।
5. **निर्णय लेने और अन्य सुरक्षा उपायों में भागीदारी:** देखें कि निर्णय लेने, स्वतंत्र, पूर्व, सूचित सहमति और शिकायत निवारण में भागीदारी से जुड़ी प्रतिबद्धताओं का सम्मान किया जा रहा है या नहीं। इससे यह पक्का करने में मदद मिलती है कि मुख्य सुरक्षा उपाय और संयुक्त निर्णय लेने की प्रतिबद्धताएं परियोजना के पूरे जीवन चक्र के दौरान सक्रिय रूप से लागू की जाएं।

परियोजना डेवलपर को कार्बन उत्सर्जन में कमी और कुछ मामलों में अन्य पर्यावरणीय परिणामों (जैसे कि जैव विविधता पर प्रभाव) पर व्यापक डेटा देना आवश्यक है। हालांकि, समुदाय कार्बन उत्सर्जन में कमी की पूरी निगरानी के लिए ज़िम्मेदार नहीं हैं, हो सकता है कि आपको ज़्यादा जवाबदेही के लिए इस प्रक्रिया में शामिल होना पड़े। अगर ऐसा है, तो परियोजना डेवलपर से कहें कि वह स्थानीय निवासियों को इसमें भाग लेने या पर्यावरण निगरानी करने के लिए प्रशिक्षित करे। यह स्थानीय रोज़गार का ज़रिया भी हो सकता है।

अनुबंध की शर्तों की निगरानी करना

	किस चीज़ पर नज़र रखें	जानकारी कैसे इकट्ठा करें
परियोजना की गतिविधियाँ और भूमि का इस्तेमाल	• क्या मुख्य गतिविधियाँ उन जगहों पर हो रही हैं, जिन पर सहमति हुई है और बताई गई समय रेखा पर? • क्या संरक्षण और आजीविका सहायता गतिविधियाँ परियोजना समझौते में दिए गए पैमाने और गुणवत्ता से मेल खाती हैं? • क्या परियोजना डेवलपर द्वारा भूमि का कोई अनुचित उपयोग किया गया है? अगर ऐसा है, तो उसके क्या प्रभाव हुए हैं?	• प्रमुख गतिविधियों को रिकॉर्ड करने के लिए लॉगबुक का इस्तेमाल करें, जैसे कि आजीविका गतिविधियों के लिए प्रशिक्षण और आपूर्ति की व्यवस्था; पुनर्स्थापना गतिविधियों के लिए स्थान और क्षेत्र; आदि। • फ़ील्ड विज़िट के दौरान समझौते की प्रतियां साथ लाएं, ताकि प्रतिबद्धताओं की तुलना देखी गई बातों से की जा सके। • यह चिह्नित करने के लिए कि गतिविधियाँ कहाँ अपेक्षित थीं और वे असल में कहाँ हुई थीं, साधारण सहभागी मानचित्रों का उपयोग करें। • किसी भी बड़ी घटना को रिकॉर्ड करने के लिए लॉगबुक का इस्तेमाल करें, जैसे कि सामुदायिक भूमि पर अतिक्रमण या पानी के स्रोतों पर असर। प्रभावों का दस्तावेजीकरण करने के लिए फ़ोटो या छोटे वीडियो लें।

	किस चीज़ पर नज़र रखें	जानकारी कैसे इकट्ठा करें
पहुँच और इस्तेमाल के अधिकार	• क्या परियोजना ने समुदायों की उन संसाधनों तक पहुँचने की क्षमता पर कोई अप्रत्याशित सीमाएँ बना दी हैं, जिन पर वे निर्भर हैं? • क्या परियोजना गतिविधियों का आजीविका के तरीकों पर अन्य नकारात्मक प्रभाव पड़ा है?	• ऐसे किसी भी उदाहरण का दस्तावेजीकरण करें, जहां परियोजना समझौते में प्रतिबद्धताओं या स्थानीय उपयोग के अधिकारों के लिए अन्य सुरक्षा के बावजूद समुदाय के सदस्यों को संसाधनों की पहुँच या उपयोग से वंचित कर दिया गया था। • उन क्षेत्रों की पहचान करने के लिए सहभागी मानचित्रण (पार्टिसिपेटरी मैपिंग) का इस्तेमाल करें जहाँ पहुँच बदला गई है या जहाँ संघर्ष होने लगे हैं। • अगर ज़रूरी हो, तो किसी भी तरह के प्रभावों की पहचान करने के लिए, अलग-अलग आजीविका समूहों, महिलाओं और युवाओं के साथ सामूहिक चर्चाएं आयोजित करें।
सामुदायिक भूमि पर्यवेक्षण	• क्या सामुदायिक उपनियमों का सम्मान किया जा रहा है और उन्हें लागू किया जा रहा है?	• टिप्पणियों, उल्लंघनों और की गई किसी भी कार्रवाई का दस्तावेजीकरण करने के लिए सामुदायिक भूमि प्रबंधन निकायों की रजिस्टरों या लॉगबुक का इस्तेमाल करें। • अगर मददगार हो, तो उन क्षेत्रों को चिह्नित करने के लिए, जिन्हें सुरक्षा की ज़रूरत है या यह पहचानने के लिए कि नियमों का उल्लंघन कहाँ हुआ है, सहभागी मानचित्रण (पार्टिसिपेटरी मैपिंग) का इस्तेमाल करें।

	किस चीज़ पर नज़र रखें	जानकारी कैसे इकट्ठा करें
वित्तीय पारदर्शिता और राजस्व साझाकरण	• क्या आपको नियमित वित्तीय रिपोर्ट मिलती है, जिसमें कार्बन से होने वाले राजस्व, परियोजना लागत और लाभ आवंटित होने की स्पष्ट जानकारी होती है? • क्या समुदाय को संविदा में सहमति की गई पूरी राशि या राजस्व का हिस्सा मिला था? क्या भुगतान समय पर किए गए थे? • क्या समुदायों द्वारा पहचानी गई प्राथमिकताओं और निधि के इस्तेमाल के लिए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सामुदायिक राजस्व हिस्से का वितरण किया गया है?	• परियोजना समझौते में जानकारी साझा करने के प्रति प्रतिबद्धताओं की समीक्षा करें और परियोजना डेवलपर और/या सामुदायिक असेंबली के साथ मीटिंग से पहले जानकारी का अनुरोध करने के लिए फ़ॉलो अप लें। • प्राप्त धन राशि और तारीखों की पुष्टि करने के लिए, सामुदायिक बैंक स्टेटमेंट देखें। • परियोजना से कमाए गए राजस्व की पुष्टि करने के लिए, परियोजना से मिलने वाले वित्तीय विवरणों और कार्बन क्रेडिट सेल्स रिपोर्ट की समीक्षा करें और यह निर्धारित करें कि परियोजना समझौते की प्रतिबद्धताओं के आधार पर समुदायों को कितना लाभ मिलना चाहिए। • परियोजना के फ़ाइनेंस और सामुदायिक निधि के इस्तेमाल के बारे में स्वतंत्र ऑडिट करवाएं।

	किस चीज़ पर नज़र रखें	जानकारी कैसे इकट्ठा करें
अन्य सुरक्षा उपाय	• क्या समुदाय निर्णय लेने में शामिल हैं जैसा कि परियोजना समझौते में परिभाषित किया गया है? • अगर कोई बड़ा बदलाव हुआ है (उदाहरण के लिए, परियोजना क्षेत्र में विस्तार या भूमि उपयोग में महत्वपूर्ण बदलाव), तो क्या परियोजना डेवलपर ने समुदाय से सहमति ली थी? • क्या शिकायत निवारण तंत्र उपलब्ध हैं और शिकायतों को हल करने में प्रभावी हैं?	• परियोजना डेवलपर और समुदायों के बीच महत्वपूर्ण मीटिंग्स में चर्चा की गई तारीखों, उपस्थिति और समस्याओं का साधारण रिकॉर्ड रखें, जिसमें समुदाय के सदस्यों द्वारा उठाई गई समस्याओं के जवाब में परियोजना डेवलपर द्वारा की गई सभी प्रतिबद्धताएं भी शामिल हैं। • प्रमुख मुद्दों पर निर्णय कैसे लिए गए यह दस्तावेज़ीकृत करें, जिसमें यह भी शामिल है कि समुदाय के प्रतिनिधि और व्यापक समुदाय सदस्य शामिल थे या नहीं। • जहाँ चिंताएँ, तारीखें, प्रतिक्रियाएँ और परिणाम रिकॉर्ड किए गए हों, वहाँ शिकायत लॉग रखें। • जाँच करें कि शिकायतों पर प्रतिक्रिया मिलने में कितना समय लगता है और यह निर्धारित करें कि परियोजना डेवलपर की ओर से धीमी या अपर्याप्त प्रतिक्रिया की वजह से किसी समस्या को सरकारी विनियामक या कार्बन मानक के पास ले जाने की ज़रूरत है या नहीं।

वित्तीय जानकारी की समीक्षा करना

जवाबदेही के लिए वित्तीय पारदर्शिता ज़रूरी है, जिसमें समुदायों को यह सत्यापित करना भी शामिल है कि उन्हें राजस्व का अपना पूरा हिस्सा मिल गया है। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, समझौते में साफ़ तौर पर परिभाषित होना चाहिए कि परियोजना डेवलपर्स को समुदायों को क्या जानकारी उपलब्ध करानी होती है — जिसमें वित्तीय विवरण और सेल्स रिपोर्ट शामिल हैं — और किस समय सीमा में।

यह पक्का करने के लिए कि राजस्व साझाकरण के दायित्वों को पूरा किया जा रहा है, परियोजना के लिए (1) वार्षिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट और (2) बेचे गए कार्बन क्रेडिट की संख्या और प्रत्येक बिक्री की कीमत का दस्तावेजीकरण करने वाली सेल्स रिपोर्ट की समीक्षा करना उपयोगी होता है।

फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कैसे समझें

फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक निश्चित समयावधि में आमदनी और खर्च रिकॉर्ड करने के लिए एक मानक फ़ॉर्मेट का अनुसरण करते हैं। जब समुदाय वित्तीय विवरणों में महत्वपूर्ण जानकारी को पढ़ और समझ पाते हैं, तो वे यह सत्यापित करने के लिए बेहतर स्थिति में होते हैं कि सहमति के अनुसार उन्हें राजस्व में से अपना हिस्सा मिल रहा है या नहीं। इससे आपको ज़्यादा जानकारी भी मिलती है, जिसका इस्तेमाल आप समझौते की अवधि के आखिर में उस अनुबंध पर फिर से बातचीत करते समय कर सकते हैं।

सबसे उपयोगी दस्तावेज़ आय का स्टेटमेंट होता है, जिसे अक्सर “प्रॉफ़िट एंड लॉस स्टेटमेंट” भी कहा जाता है। मुख्य घटकों में शामिल हैं:

- **राजस्व:** कार्बन क्रेडिट की बिक्री और किसी भी अन्य स्रोत से होने वाली कुल आय। कार्बन क्रेडिट से होने वाले राजस्व को “बिक्री से होने वाली कुल आय” के रूप में सूचीबद्ध किया जा सकता है।
- **परिचालन खर्च:** परियोजना लागू करने, कार्बन मानक के हिसाब से पुष्टि करने और क्रेडिट की मार्केटिंग से जुड़ी लागतें।
- **निवल आय:** परिचालन खर्च के बाद होने वाला मुनाफ़ा और अन्य लागतों की कटौती की जाती है।

परियोजना डेवलपर द्वारा साझा किए गए राजस्व के आंकड़ों की जांच करने के लिए समुदाय स्वतंत्र स्रोतों से मिली जानकारी का उपयोग कर सकते हैं।

- **पुष्टि करें कि कितने क्रेडिट बेचे गए हैं।** कार्बन स्टैंडर्ड में आमतौर पर एक पंजीकरण संस्था (रजिस्ट्री) होती है जिसमें बेचे गए क्रेडिट की संख्या का डेटा शामिल होता है। देखें कि बेचे गए क्रेडिट की संख्या उसी समयावधि के लिए रजिस्ट्री में सार्वजनिक रूप से बताई गई क्रेडिट से मेल खाती है या नहीं।
- **हर क्रेडिट के बिक्री मूल्य की तुलना मार्केट के बेंचमार्क से करें।** किसी खास परियोजना प्रकार (जैसे वनों की कटाई में कमी (REDD+), पुनर्वनीकरण (ARR), कृषि भूमि प्रबंधन (ALM), आदि) की औसत कीमतों के लिए सबसे हाल की **पारिस्थितिकी तंत्र मार्केटप्लेस रिपोर्ट** देखें। साथ ही, अपने परियोजना की पिछली सेल्स रिपोर्ट देखें - अगर कीमत में काफी बदलाव आया है, तो स्पष्टीकरण मांगें।
- अपने राजस्व साझाकरण समझौते के आधार पर **समुदायों को मिलने वाली राशि की गणना** करें। आपको मिलने वाली राशि की पुष्टि करने के लिए वित्तीय विवरणों का इस्तेमाल करें (अक्सर परियोजना से होने वाले कुल राजस्व का एक प्रतिशत)।
- **प्राप्त राशि की पुष्टि करने के लिए अपने बैंक स्टेटमेंट देखें।** पुष्टि करें कि परियोजना के वित्तीय विवरणों में सामुदायिक राजस्व हिस्से के रूप में दी गई पूरी राशि आपके खाते में ट्रांसफर की गई थी।

नियमित समय अवधि पर, कम से कम हर दो से तीन साल में परियोजना के फाइनेंस का स्वतंत्र ऑडिट करवाना चाहिए।

प्रवर्तन के लिए रास्ते

स्पष्ट समझौतों और सद्भावपूर्ण वार्ताओं के साथ भी, विवाद या ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न हो सकती हैं, जहाँ कोई परियोजना डेवलपर अपनी प्रतिबद्धताओं का पालन नहीं करता है। अगर ऐसा होता है, तो समुदायों के पास विवाद सुलझाने और यह सुनिश्चित करने के विकल्प होते हैं कि समझौते की शर्तें लागू हों। नीचे दिए गए चरणों में व्यावहारिक रास्ते बताए गए हैं, जिन्हें ज़मीनी स्तर पर वकील अपना सकते हैं, जिसकी शुरुआत समाधान के लिए सबसे सरल, सबसे सीधे रास्तों से होती है।

1. **परियोजना डेवलपर से सीधे संपर्क करें**
   पहला और अक्सर सबसे आसान कदम होता है परियोजना डेवलपर से अपनी चिंताओं को साझा करना। कई गलतफहमियां या विवाद सीधे जुड़ाव के ज़रिए हल किए जा सकते हैं, खासकर जब समुदायों के पास स्पष्ट सबूत और प्रस्तावित समाधान होता है।

   - समस्या का साफ़-साफ़ दस्तावेजीकरण करके शुरुआत करें: (i) क्या वादा किया गया था; (ii) क्या हुआ या क्या नहीं हुआ; और (iii) समुदाय द्वारा इकट्ठा किए गए सहायक प्रमाणों का वर्णन करें।
   - अपनी चिंताओं के बारे में बताने और मीटिंग का अनुरोध करने के लिए डेवलपर को लिखें। डेवलपर से कहें कि वह उचित समय सीमा में जवाब दे।
   - मीटिंग के दौरान, उस समस्या के बारे में स्पष्ट रूप से बताइए, जिस पर ध्यान देने की ज़रूरत है और जो सबूत आपने इकट्ठा किए हैं, उन्हें देख लें। अगर संभव हो, तो किसी खास समाधान या कार्रवाई का प्रस्ताव दें, जिससे परियोजना डेवलपर समस्या का समाधान कर सके। परियोजना डेवलपर के साथ पावर डायनामिक्स को कम करने में मदद करने के लिए, किसी समुदाय के वकील, स्थानीय नेता, या भरोसेमंद एनजीओ प्रतिनिधि को मीटिंग में लाना मददगार हो सकता है।

2. **शिकायत निवारण या मध्यस्थता की व्यवस्था का इस्तेमाल करें**

   ज़्यादातर मामलों में, परियोजना डेवलपर से अपेक्षा की जाती है कि वे अपना खुद का परियोजना-स्तरीय शिकायत तंत्र बनाए रखें, जिसे समुदाय के सदस्यों के लिए पहुँच करना आसान होना चाहिए। अगर सीधे बातचीत से समस्या हल नहीं होती है, तो समुदाय इस सिस्टम के ज़रिए औपचारिक शिकायत सबमिट कर सकते हैं।

शिकायत प्रक्रिया का इस्तेमाल करते समय ध्यान देने योग्य बातें:

- वक्तव्य को छोटा और तथ्यात्मक रखें: बताइए कि किस बात पर सहमति हुई, क्या हुआ, समस्या समुदाय को कैसे प्रभावित करती है, और समस्या उठाने के लिए आपने पहले ही कौन से कदम उठाए हैं।
- साफ़ तौर पर बताएं कि आपको आगे क्या करना है, जैसे कि डेवलपर समस्या को हल करने के लिए कोई ख़ास कार्रवाई कर सकता है।

  जब किसी शिकायत का समाधान उनकी आंतरिक प्रक्रिया के ज़रिए नहीं किया जा सकता, तो कुछ डेवलपर स्वतंत्र मध्यस्थता या मध्यस्थता के लिए सहमत हो जाते हैं। इन तंत्रों से किसी तटस्थ तीसरे पक्ष को समस्या की समीक्षा करने और उचित समाधान की दिशा में काम करने के लिए कहा जाता है। हालांकि ज़्यादा संरचित, उन्हें इसलिए डिज़ाइन किया गया है कि उन तक पहुँचा जा सके और आमतौर पर उन्हें वकील की ज़रूरत नहीं होती है। इन चैनलों का इस्तेमाल करने से यह पक्का करने में मदद मिल सकती है कि डेवलपर समस्या को गंभीरता से ले और समाधान के लिए एक स्पष्ट, समयबद्ध प्रक्रिया का पालन करे।

3. **सरकारी विनियामक या कार्बन मानक के ज़रिए प्रवर्तन करें**

   अगर समस्या बनी रहती है, तो समुदाय समस्या और परियोजना के प्रकार के आधार पर संबंधित सरकारी निकायों, जैसे कि पर्यावरण मंत्रालय, कार्बन परियोजना की देखरेख करने वाली एजेंसी और/या मूल निवासी मामलों के अधिकारियों तक समस्या की जानकारी दे सकते हैं। सरकारी विनियामकों के पास जाँच करने, चेतावनी जारी करने, परमिट निलंबित करने और/या डेवलपर से सुधारात्मक कार्रवाई करने का अनुरोध करने का अधिकार है।

इसी तरह, प्रमुख कार्बन मानकों (जैसे, Verra, Gold Standard) में अनुपालन टीमें होती हैं, जो अपने नियमों या परियोजना प्रतिबद्धताओं के उल्लंघन की जाँच कर सकती हैं। मानक के पास सीधे शिकायत सबमिट करने से ऑडिट किया जा सकता है, परियोजना को अस्थायी रूप से निलंबित किया जा सकता है, और आवश्यक सुधारात्मक उपाय किए जा सकते हैं। जैसा कि ऊपर बताया गया है, सरकारी एजेंसियों या कार्बन मानकों की शिकायतों में समस्या का स्पष्ट दस्तावेजीकरण और इसे हल करने के पहले किए गए प्रयासों के रिकॉर्ड शामिल होने चाहिए।

समुदायों के पास व्यावहारिक विकल्प होते हैं, ताकि वे यह पक्का कर सकें कि डेवलपर अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करें। सीधे संवाद से शुरुआत करके और ज़रूरत पड़ने पर शिकायत प्रणालियों और विनियामक चैनलों से गुज़रने से, हर रास्ता समस्याओं को साफ़ और भरोसेमंद तरीके से बढ़ाने में मदद करता है। ठोस दस्तावेज़ों और सामूहिक आयोजन की मदद से, समुदाय परियोजना डेवलपर को ज़िम्मेदार ठहरा सकते हैं और उन फ़ायदों की सुरक्षा कर सकते हैं, जिनका उनसे वादा किया गया था।

IV. परियोजना समझौते पर फिर से बातचीत करना

किसी परियोजना समझौते की एक निर्धारित अवधि होगी और इसमें समझौते की शर्तों की समीक्षा करने, उन्हें अपडेट करने या फिर से बातचीत करने की समय सीमा शामिल होनी चाहिए। आमतौर पर, समझौते की समीक्षा हर 5 से 10 साल में की जाएगी। जब समझौता नवीनीकरण या फिर से बातचीत के लिए आता है, तो समुदायों के पास यह आकलन करने का एक महत्वपूर्ण अवसर होता है कि कार्यान्वयन आज तक कैसे हुआ है और उन प्रमुख क्षेत्रों की पहचान करने के लिए जिन्हें हल करने की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए, अगर समझौते में ऐसी शर्तें हैं जिन्हें लागू करना मुश्किल हो गया है या जो समुदायों के लिए काम नहीं कर रही हैं, तो उन्हें अपडेट करने का यह सही समय है।

फिर से बातचीत की किसी भी प्रक्रिया में प्रवेश करते समय, समुदायों को अपने प्रस्तावों को उन समस्याओं के आधार पर रखना चाहिए जिनकी पहचान निरंतर निगरानी के ज़रिए की गई है। लॉगबुक, मीटिंग रिकॉर्ड, वित्तीय जानकारी या फ़ील्ड में टिप्पणियों से इकट्ठा किए गए साक्ष्य से यह स्पष्ट करने में मदद मिल सकती है कि क्या समझौते में विशिष्ट दायित्वों को उम्मीद के मुताबिक लागू नहीं किया जा रहा है या कुछ शर्तें अब काम करने योग्य नहीं हैं। इस जानकारी का उपयोग करने से समुदाय अपने अनुभव के आधार पर चिंताएं जता सकता है और समायोजन का अनुरोध कर सकता है। यह समुदाय से किए जा रहे राजस्व साझाकरण की समीक्षा करके सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण पल है कि समुदाय को मिल रही निधि कुल राजस्व के अनुपात में बढ़े। समुदाय समय के साथ धीरे-धीरे अपनी आय में हिस्सेदारी बढ़ाने का प्रस्ताव कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप कुल आय के 40% हिस्से को समुदाय को मिलने पर सहमति देते हैं, तो आप इसे और 5% बढ़ाने का अनुरोध कर सकते हैं — ख़ासकर अगर परियोजना ऊंची कीमत हासिल कर रहा है और/या परियोजना डेवलपर ने पहले ही अपनी शुरुआती अग्रिम लागत वसूल कर ली है।

कुल मिलाकर, फिर से बातचीत में सामुदायिक नेतृत्व को मज़बूत करने, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने, और उचित राजस्व साझाकरण पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

Mpanshya चीफ़डम, ज़ाम्बिया में संचालन संरचनाएं और सामुदायिक फ़ायदे

जेसिंटा कुंडा, ज़ाम्बिया लैंड अलायंस के द्वारा

Mpanshya चीफ़डम में Chimusanya समुदाय एक कार्बन परियोजना में शामिल है, जिसे बायोकार्बन पार्टनर्स (BCP), एक निजी कंपनी द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है है। Mpanshya चीफ़डम कार्बन ट्रेडिंग में शामिल बारह चीफ़डम में से एक है। Mpanshya चीफ़डम में, परियोजना में कुल 32 समुदाय शामिल हैं। परियोजना शुरू होने पर, चीफ़डम का एक इलाका, Chipeket, ने इस संदेह में शामिल होने से इनकार कर दिया कि चीफ़डम उनकी ज़मीन बेचने जा रहा है; हालाँकि, जब उन्हें चीफ़डम के अन्य क्षेत्रों से लाभ देखने को मिला, तो उन्होंने भी परियोजना में शामिल होने का फैसला किया।

Chimusanya के समुदाय ने परियोजना के लिए समर्पित लगभग 81,000 हेक्टेयर भूमि अलग रखी है। परियोजना के लिए अलग रखी जाने वाली भूमि की पहचान करते समय, गाँव के वरिष्ठ और प्रधान व्यक्ति, साथ ही समुदाय के सदस्यों से सलाह ली गई। जिस भूमि की पहचान की गई थी वह सांप्रदायिक भूमि है और इस परियोजना से किसी को विस्थापित नहीं किया गया था।

Mpanshya चीफ़डम में परियोजना को सुचारू रूप से चलाने में मदद करने के लिए तीन संरचनाएँ स्थापित की गई थीं:

- विलेज एक्शन ग्रुप्स (VAG) लोगों द्वारा चुने जाते हैं और उनकी भूमिका में समुदाय के सदस्यों को लामबंद करना और यह सुनिश्चित करना शामिल है कि समुदाय के सदस्य कार्बन पेमेंट से वित्त पोषित होने वाली विकास परियोजनाओं पर चर्चा करने और उन पर सहमत होने के लिए एक साथ आएं। Mpashhya चीफ़डम को पाँच (5) ज़ोन में बांटा गया है, जिनमें से प्रत्येक का प्रतिनिधित्व एक VAG द्वारा किया जाता है: Chimusanya, Rufunsa, Chansanje, Chipeketi और Chitengele।
- सामुदायिक संसाधन बोर्ड (CRB) की भूमिका समुदाय के हितों का प्रतिनिधित्व करना और परियोजना से जुड़ी सारी जानकारी का रिकॉर्ड रखना है।
- फ़ॉरेस्ट स्काउट्स जंगल की रखवाली और उसकी सुरक्षा करते हैं। वे यह सुनिश्चित करते हैं कि समुदाय के सदस्यों सहित, कोई भी जंगल में न जाए या उससे कुछ भी न काटा जाए।

परियोजना संविदा और लाभ साझा करने की व्यवस्था

प्रधान, समुदाय के सदस्य और वॉर्ड डेवलपमेंट समिति के अध्यक्ष ने बताया कि समुदाय के बीच 30 साल की अवधि के लिए कोई समझौता या अनुबंध होता है और इस प्रावधान की समीक्षा हर 7 साल में की जाएगी। यह अनुबंध 2015 में हस्ताक्षरित हुआ था, हालांकि, समुदाय को फ़ायदे कुछ साल पहले ही मिलने लगे थे। जहाँ तक समुदाय के सदस्य समझते हैं, 55% राजस्व कंपनी को, 45% समुदाय को और 5% प्रधान को जाता है। उम्मीद है कि पार्टियां कुछ सालों में संविदा की समीक्षा करेंगी।

समुदाय के सदस्यों को CRB और VAG के ज़रिए हर साल भुगतान किया जाता है। फंड उपलब्ध होने पर सूचित करके BCP हर साल समुदाय को शामिल करता है और समुदाय के सदस्य इकट्ठा होकर सामुदायिक विकास परियोजनाओं का चयन करके फ़ंडिंग करते हैं। हालांकि, BioCarbon Partners कार्बन क्रेडिट की बिक्री से होने वाली कुल आय के बारे में जानकारी समुदायों के साथ साझा नहीं करते हैं। समुदायों के मुताबिक, उन्हें बस इतना बताया जाता है कि पैसा तैयार है और उन्हें अपनी परियोजनाएं सबमिट करनी चाहिए। 2024 में समुदायों को फ़ायदा नहीं मिला, लेकिन उन्हें बताया गया कि पैसे बाद में दिए जाएंगे। अब तक, कंपनी ने बोरहोल लगाए हैं, 4 सामुदायिक स्कूल बनाए हैं, और एक बार किसानों के लिए इनपुट के लिए भुगतान भी किया है। एक समय पर, समुदाय के सदस्य इस बात पर सहमत हुए कि वे लोहे की चादरें और नकद भुगतान चाहते हैं, लेकिन केवल कुछ ही लोगों को ये प्राप्त हुए, क्योंकि परियोजना उन्हें व्यक्तियों के बजाय घरों को दे रही थी। समुदाय के सदस्यों और वॉर्ड डेवलपमेंट समिति के प्रतिनिधियों ने एक सामुदायिक मीटिंग के दौरान बताया कि प्रत्यक्ष नकद लाभ (डायरेक्ट कैश बेनिफ़िट) चुनौतियां पेश करते हैं क्योंकि केवल कुछ परिवारों को ही फ़ायदा होता है और भुगतान छोटे होते हैं। यह देखते हुए, उन्होंने स्कूल जैसी परियोजनाओं को प्राथमिकता देने का फैसला किया, जिससे चीफ़डम में रहने वाले सभी लोगों को फायदा होगा। इन चुनौतियों के बावजूद, समुदाय के पास यह चुनने के लिए मापदंड हैं कि किसे नकद फ़ायदा मिलेगा, जिसमें समुदाय के बुजुर्ग और गरीब परिवार शामिल हैं।

जब Chipeketi ने परियोजना में शामिल होने का फैसला किया, तो वे नकद दिए जाने पर सहमत हो गए और Chimusanya में समुदाय के कुछ सदस्यों को कैश मिला, लेकिन सबसे ज़्यादा भुगतान K400 (लगभग 17 USD) था। इन फ़ायदों के साथ, Chimusanya समुदाय ने हैमर मिल्स में निवेश किया है और समुदाय के सदस्य अपने मक्के को मीली मील में बदलने के लिए K2 (लगभग 0.024USD) का भुगतान करते हैं। लिया जाने वाला शुल्क बहुत कम होता है और यह सिर्फ़ मिलों के रख-रखाव और समुदाय के सदस्यों का अंतिम संस्कार होने पर उनकी मदद करने के लिए किया जाता है।

न्याय से जुड़ी समस्याएँ

- समुदाय के लिए 45% का आवंटन पर्याप्त नहीं है: समुदाय और VAG के कुछ सदस्यों को लगता है कि यह परियोजना सामुदायिक भूमि पर है, इसलिए समुदायों को मिलने वाला राजस्व ज़्यादा होना चाहिए।
- फ़ायदों का भुगतान: समुदाय के सदस्यों ने बताया कि कंपनी डेवलपमेंट परियोजना के लिए फ़ंडिंग करके फ़ायदे देती है। जब बायोकार्बन पार्टनर्स CRB को सूचित करते हैं कि पैसा बांटने के लिए तैयार है, तो CRB समुदाय की ज़रूरतों का आकलन करने के लिए VAG के साथ काम करता है, जिसके दौरान लगभग 3 परियोजनाओं की पहचान की जाती है और उन्हें प्राथमिकता के अनुसार रैंक दिया जाता है। इसके बाद, कंपनी को इसकी जानकारी दी जाती है, जो फिर सेवा प्रदाताओं से सीधे बातचीत करके परियोजना डिलीवर करती है। समुदाय के सदस्य CRB के लिए सेवा प्रदाताओं को शामिल करना और परियोजना को सीधे लागू करना पसंद करेंगे, जिससे उन्हें हर परियोजना की लागत की बेहतर जानकारी और समझ मिलेगी।
- वित्तीय रिपोर्ट तक पहुँच की कमी: समुदाय के पास समुदाय के हिस्से के लिए अलग से रखी गई राशि और सामुदायिक विकास परियोजनाओं के बजट के बारे में वित्तीय जानकारी तक पहुँच नहीं है।

समुदाय की योजना है कि आने वाले सालों में संविदा की समीक्षा होने पर, सामुदायिक फ़ायदे मैनेज करने के लिए, राजस्व आबंटन और संरचना में बदलाव का प्रस्ताव रखा जाए।

अनुलग्नक

अनुलग्नक ए: सिएरा लियोन से कार्बन पार्टनरशिप समझौते का नमूना

यह कार्बन पार्टनरशिप समझौता [जलवायु परिवर्तन अधिनियम/राष्ट्रीय कार्बन रणनीति] के तहत..... 202 के दिन किया गया है... [समुदाय के नाम] के स्थानीय समुदाय के

बीच,

में..... चीफ़डम,..... ज़िले में,..... [क्षेत्र] सिएरा लियोन गणराज्य, जिसका प्रतिनिधित्व कार्बन कमिटी के..... के..... द्वारा इस समझौते पर हस्ताक्षर करने के उद्देश्य से किया गया था..... समुदाय (इसके बाद "पार्टनर ए" कहा जाएगा, जिसमें जहां संदर्भ ऐसा स्वीकार करता है, उनके उत्तराधिकारी या असाइन को शामिल किया जाएगा)

और

[परियोजना डेवलपर का नाम], या [सिएरा लियोन में सेवा के लिए पता] (इसके बाद इसे "पार्टनर बी" कहा जाएगा, जिसमें अभिव्यक्ति शामिल होगी, जहां संदर्भ इस बात को स्वीकार करता है, इसके उत्तराधिकारी और असाइन किए गए हैं)

प्रस्तावना

1. सिएरा लियोन पेरिस समझौते का एक पक्ष है और उसने जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDC) सबमिट किए हैं।
2. सिएरा लियोन सरकार टिकाऊ विकास, जलवायु लचीलापन, जैव विविधता सुरक्षा, और सामुदायिक अधिकारों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है, जैसा कि इन उपकरणों में दिया गया है:

    - प्रथागत भूमि अधिकार अधिनियम 2022
    - पर्यावरण सुरक्षा एजेंसी अधिनियम 2022
    - राष्ट्रीय संरक्षित क्षेत्र प्राधिकरण और संरक्षण ट्रस्ट फंड अधिनियम

- जलवायु परिवर्तन अधिनियम/राष्ट्रीय कार्बन रणनीति
- अन्य प्रासंगिक क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन, जिनमें मानव और लोगों के अधिकारों पर अफ़्रीकी चार्टर, मूल निवासी लोगों के अधिकारों संबंधी संयुक्त राष्ट्र की घोषणा और जैविक विविधता पर कन्वेंशन शामिल हैं;

3. पार्टी ए वह स्थानीय समुदाय है, जिसे प्रथागत भूमि अधिकार अधिनियम 2022 के तहत और रीति-रिवाज द्वारा उस भूमि पर "प्रथागत भूमि अधिकार" की परिभाषा के तहत प्रथागत भूमि अधिकार अधिनियम 2022 की धारा 1 में निर्धारित प्राथमिक और द्वितीयक अधिकारों की पूरी रेंज का अधिकार है, जो कि इस समझौते का विषय है।

4. पार्टी बी एक ऐसी कंपनी है जिसे सिएरा लियोन के कानूनों के तहत बिज़नेस करने के लिए निगमित किया गया है, ... [XYZ Ltd. की पूर्ण या आंशिक स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में, एक सीमित देयता कंपनी के रूप में, जो..... के कानूनों के तहत निगमित है और जो..... के रूप में.....] में काम कर रही है।

5. पार्टी बी ने पार्टी ए, पैरामाउंट चीफ़ और चीफ़डम काउंसिल के अन्य सदस्यों, ...ज़िले के सक्षम प्राधिकारियों और [पर्यावरण मंत्रालय/पर्यावरण संरक्षण एजेंसी] के अधिकारियों को पार्टी ए के साथ साझेदारी समझौता करने की इच्छा व्यक्त की है, जिसका उद्देश्य संयुक्त रूप से उस ज़मीन पर [सभी] रेनफॉरेस्ट/सामुदायिक वन/मैंग्रोव की सुरक्षा, प्रबंधन, प्रबंधन और अंततः [सभी] रेनफॉरेस्ट/सामुदायिक वन/मैंग्रोव का विस्तार करना है वॉलंटरी कार्बन बाज़ार (कार्बन मार्केट)/ कंप्लायंस मार्केट में बिक्री के लिए कार्बन क्रेडिट जेनरेट करने के लिए।

6. पार्टी बी ने पार्टी ए, पैरामाउंट चीफ़ और चीफ़डम काउंसिल के अन्य सदस्यों को परियोजना से संबंधित जानकारी प्रदान की है, जिसमें परियोजना की प्रकृति, स्कोप, जोखिम और अवसर, बिज़नेस प्लान और परियोजना से संबंधित अन्य सभी जानकारी लिखित रूप में और मौखिक रूप से उनके द्वारा समझी गई भाषा में दी गई है।

7. पार्टी बी ने पर्यावरण संरक्षण एजेंसी के जलवायु परिवर्तन निदेशालय की कार्बन परियोजना विनियामक इकाई में परियोजना को पंजीकृत किया है और सिएरा लियोन में कार्बन क्रेडिट परियोजना शुरू करने के लिए संबंधित सरकारी एजेंसियों से ज़रूरी लाइसेंस प्राप्त कर लिए हैं।

8. पार्टी ए ने स्वैच्छिक कार्बन बाज़ार (कार्बन मार्केट) में बिक्री के लिए कार्बन क्रेडिट जनरेट करने के लिए पार्टी ए की भूमि पर [सभी] रेनफ़ॉरेस्ट/सामुदायिक फ़ॉरेस्ट/मैंग्रोव की संयुक्त रूप से सुरक्षा, स्टीवर्ड, संरक्षण, प्रबंधन और अंततः विस्तार करने के लिए पार्टी बी के ऑफ़र को स्वीकार कर लिया है।

9. पार्टी ए और पार्टी बी ने..... 2025 से..... के दिन से इस साझेदारी समझौते की प्रस्तावित शर्तों पर चर्चा करने के लिए कइ सामुदायिक मीटिंग्स आयोजित कीं 2025 का ....दिन। साझेदारी समझौते का ड्राफ़्ट तैयार किया गया था और..... 2025 के..... दिन से..... 2025 तक सामुदायिक मीटिंग्स में प्रस्तुत किया गया था। उन सामुदायिक मीटिंग्स में प्रतिक्रिया दी गइ थी और साझेदारी समझौते के मसौदे में संशोधन किए गए थे। समझौते के मसौदे को अंतिम रूप से..... 2025 के दिन..... चीफ़डम,..... ज़िले में एक सार्वजनिक बैठक में किया गया।

अब, इसलिए, पार्टियां इस तरह सहमत हैं:

1. उद्देश्य, दायरा और अवधि

1.1 यह समझौता पार्टी ए और पार्टी बी के अधिकारों, भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के साथ-साथ कार्बन क्रेडिट परियोजना के विकास और संचालन में संरचना और राजस्व साझा व्यवस्था के बारे में बताता है।

1.2 पार्टियां यह सुनिश्चित करेंगी कि परियोजना प्रभावी जलवायु कार्रवाई में योगदान दे। पार्टी बी खरीदारों को चुनने के लिए एक फ़्रेमवर्क तैयार करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि क्रेडिट सिर्फ़ उन कंपनियों को बेचे जाएंगे जो कार्बन क्रेडिट ख़रीदने से पहले अपने टालने योग्य उत्सर्जन को सक्रिय रूप से कम कर रही हैं।

1.3 परियोजना क्षेत्र [स्थान] में [XXX] हेक्टेयर होगा, जैसा कि नीचे दिए गए शेड्यूल में बताया गया है और जैसा कि इस समझौते के साथ संलग्न सर्वेक्षण योजना/मानचित्र संख्या..... पर दिखाया गया है।

1.4 इस समझौते की अवधि हस्ताक्षर करने की तारीख से [X] वर्ष होगी। इस समझौते को पार्टियों या उनके उत्तराधिकारियों द्वारा 50 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है या ऐसी शर्तों पर असाइन किया जा सकता है जिन पर बातचीत की जाएगी। कोई भी पक्ष जो इस तरह के एक्सटेंशन की इच्छा रखता है, वह मौजूदा अवधि की समाप्ति से छह महीने पहले दूसरे पक्ष को उनके इरादे के बारे में सूचित करेगा और सूचना के बाद एक के बाद ही बातचीत शुरू हो जाएगी।

2. भूमि, पानी और कार्बन अधिकार

2.1 पार्टी बी यह मानती है कि परियोजना में शामिल भूमि, पानी और अन्य प्राकृतिक संसाधन प्रथागत/औपचारिक क़ानून द्वारा नियंत्रित होते हैं और यह कि प्रथागत भूमि अधिकार अधिनियम 2022 या अन्य प्रासंगिक कानूनों के तहत समुदाय/परिवार या व्यक्ति के पास इन संसाधनों के मालिकाना हक हैं।

2.2 पार्टी बी यह भी मानती है कि कार्बन अधिकार भूमि के स्वामित्व के अधिकारों से जुड़े होते हैं और इस समझौते के अंतर्गत आने वाली भूमि के कार्बन अधिकार पार्टी ए में निहित हैं।

2.3 कोई भी परियोजना गतिविधियाँ समुदाय के सदस्यों द्वारा सामुदायिक भूमि, जंगल, आर्द्रभूमि, जल निकाय या अन्य प्राकृतिक संसाधनों तक पहुँच का उल्लंघन नहीं करेंगी या उन तक पहुँच को प्रतिबंधित नहीं करेंगी, सिवाय इसके कि इस समझौते के अनुसार या ऐसी गतिविधियों को करने से पहले प्राप्त समुदायों की स्पष्ट लिखित और मौखिक रूप से स्वतंत्र, पूर्व, सूचित सहमति (FPIC) की स्पष्ट लिखित और मौखिक रूप से स्वतंत्र, पूर्व, सूचित सहमति (FPIC) दी गई हो।

2.4 पार्टी बी इस समझौते द्वारा दिए गए अधिकार या हित के अलावा भूमि, पानी और अन्य प्राकृतिक संसाधनों में किसी भी अधिकार या दिलचस्पी की तलाश नहीं करेगी या उन्हें रजिस्टर नहीं करेगी।

3. स्वतंत्र, पूर्व, सूचित सहमति (FPIC) और जानकारी तक पहुँच

3.1 पार्टियां इस बात की पुष्टि करती हैं कि समुदाय से दस्तावेज़ की गई स्वतंत्र, पूर्व, सूचित सहमति को इस समझौते में शामिल किसी भी गतिविधि को करने से पहले प्रथागत भूमि अधिकार अधिनियम 2022 और प्रथागत भूमि अधिकार विनियम 2023 के प्रावधानों के अनुसार प्राप्त किया गया था।

3.2 दोनों पक्ष इस बात से सहमत हैं कि परियोजना में कोई महत्वपूर्ण बदलाव होने पर सहमति मांगी जाएगी और उन्हें प्राप्त किया जाएगा।

3.3 परियोजना के डिज़ाइन, कार्बन के तरीके, संभावित प्रभाव, राजस्व से जुड़ी उम्मीदें और अधिकारों से जुड़े प्रभावों से जुड़ी जानकारी यह थी:

- साफ़ और सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त फ़ॉर्मेट में उपलब्ध कराया गया
- स्थानीय भाषाओं में अनुवादित (क्रियो, मेंडे, टेम्ने, लिम्बा, आदि)
- ऑडियो फ़ॉर्मेट में रिकॉर्ड किया गया है और स्थानीय रेडियो और सामुदायिक मीटिंग्स के ज़रिए इसका प्रचार किया गया है।

3.4 स्वतंत्र, पूर्व, सूचित सहमति प्रक्रिया को कानूनी या मानवाधिकार विशेषज्ञता वाले एक स्वतंत्र तीसरे पक्ष के संगठन द्वारा सुगम बनाया गया था और इसका सत्यापन EPA के जलवायु परिवर्तन निदेशालय की कार्बन परियोजना विनियामक इकाई द्वारा किया गया था।

4. पार्टी ए के अधिकार, दायित्व और जिम्मेदारियां

4.1 पार्टी ए के पास भूमि, पानी और दूसरे प्राकृतिक संसाधनों का मालिकाना हक होगा, जो कि इस समझौते का विषय है।

4.2 पार्टी ए इस समझौते से कवर होने वाली भूमि के अंदर किसी भी वनस्पतियों और/या जीवों को काटने, हटाने, जलाने या नष्ट करने से परहेज करेगी। पार्टी ए विश्वसनीय कार्बन सिंक के तौर पर ऐसी किसी भी और सभी गतिविधियों से दूर रहेगा, जिनसे इस समझौते से कवर होने वाली भूमि की व्यवहार्यता को खतरा हो।

4.3 4.2 में दिए गए दायित्वों का उल्लंघन किए बिना, पार्टी ए को इस समझौते में शामिल भूमि पर निम्नलिखित पहुँच और इस्तेमाल के अधिकार मिलते रहेंगे: (क) मौजूदा फ़ुटपाथ या पगडंडियों का इस्तेमाल करके गुज़रने का अधिकार (ख) उपयुक्त और स्वीकृत फ़िशिंग किट का उपयोग करके भूमि के भीतर की धाराओं से स्थायी रूप से मछली पकड़ने का अधिकार (सी) स्वच्छता और स्वच्छता के उद्देश्यों के लिए इस समझौते द्वारा कवर की गई भूमि के भीतर जल संसाधनों से पानी इकट्ठा करने और/या उपयोग करने का अधिकार (d) जड़ी-बूटियाँ, शहद, फल और अन्य औषधीय पौधों को इकट्ठा करने का अधिकार (यों) निजी या घरेलू कामों जैसे कि रतन के लिए कुछ नवीकरणीय चढ़ाई वाले पौधों की स्थायी रूप से कटाई करें।

4.4 पार्टी ए इस समझौते के तहत भूमि और प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा के लिए सामुदायिक समितियों की स्थापना करेगी और उनका रखरखाव करेगी, उप-कानून विकसित करेगी और उन्हें लागू करेगी।

4.5 पार्टी ए किसी अन्य व्यक्ति या संस्था के साथ ऐसा कोई समझौता नहीं करेगी, जो इस समझौते के तहत उसके दायित्वों के अनुरूप न हो।

4.6 पार्टी ए इसके द्वारा इस समझौते के तहत जेनरेट किए गए सभी कार्बन क्रेडिट का मालिकाना हक देती है और पार्टी बी को ऐसे कार्बन क्रेडिट, ग्रीनहाउस गैस में कटौती, और उत्सर्जन में कमी के किसी भी अन्य सत्यापित तरीके को बेचने का विशेष अधिकार देती है।

4.7 पार्टी ए इसके द्वारा पार्टी बी, उसके स्टाफ़, एजेंट या ठेकेदार को इस समझौते में कवर की जाने वाली भूमि तक अप्रतिबंधित पहुँच प्रदान करती है, ताकि वह इसकी सुरक्षा से संबंधित कोई भी और सभी गतिविधियाँ कर सकें, साथ ही उत्सर्जन में कमी के मापन और सत्यापन से संबंधित गतिविधियाँ कर सकें।

4.8 समुदाय के विकास के लिए इस समझौते के तहत प्राप्त राजस्व का समान उपयोग और उपयोग के लिए एक योजना तैयार करें।

5. पार्टी बी के अधिकार, दायित्व और जिम्मेदारियां

5.1 पार्टी बी, उपरोक्त 4.6 के अनुरूप, इस समझौते के तहत उत्पन्न किए गए सभी कार्बन क्रेडिट का मालिकाना हक रखेगी और इस समझौते की शर्तों के अनुसार ऐसे कार्बन क्रेडिट, ग्रीनहाउस गैस में कटौती और उत्सर्जन में कटौती के किसी भी अन्य सत्यापित तरीके को बेचने का विशेष अधिकार होगा।

5.2 पार्टी बी, उसके स्टाफ़, एजेंट या ठेकेदार, के पास इस समझौते के अंतर्गत आने वाली भूमि तक किसी भी तरह की पाबंदी नहीं है, ताकि वह इसकी सुरक्षा से जुड़ी कोई भी और सभी गतिविधियाँ कर सकें और साथ ही उत्सर्जन में कमी की माप और सत्यापन से जुड़ी गतिविधियाँ कर सकें।

5.3 पार्टी बी यह सुनिश्चित करेगी कि परियोजना [जलवायु परिवर्तन अधिनियम/राष्ट्रीय कार्बन रणनीति] के प्रावधानों और वॉलंटरी कार्बन मानक की ज़रूरतों का अनुपालन करे, जिसके तहत परियोजना को पंजीकृत किया गया है।

5.4 पार्टी बी यह सुनिश्चित करेगी कि परियोजना का प्रबंधन किया जाए और पर्यावरण, सामाजिक और शासन संबंधी जोखिमों को सिएरा लियोन के नियमों और इस प्रकृति की परियोजनाओं के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत मानकों और दिशानिर्देशों के अनुसार कम किया जाए। पार्टी बी ज़रूरत के हिसाब से परियोजना को पंजीकृत करेगी और सभी ज़रूरी कानूनी परमिट पाएगी।

5.5 पार्टी बी यह सुनिश्चित करेगी कि वह परियोजना के सर्वोत्तम हित में और ईमानदारी के साथ तीसरे पक्ष के साथ सभी वार्ताओं को अंजाम दे।

5.6 पार्टी बी, परियोजना से होने वाले राजस्व और किए गए खर्च के बारे में पार्टी ए को समय-समय पर वित्तीय विवरण देगी। पार्टी बी परियोजना के तहत सभी ट्रांजेक्शन के लिए संविदा, इनवॉइस और रसीदों की कॉपी भी उपलब्ध कराएगा।

5.7 पार्टी बी इस समझौते के तहत कार्बन क्रेडिट की किसी भी बिक्री से पहले पार्टी ए के साथ सहमति के अनुसार फंड प्रदान करेगी, ताकि इस समझौते में शामिल भूमि की सुरक्षा, संरक्षण और प्रबंधन के लिए गतिविधियाँ की जा सकें। जिन गतिविधियों को कवर किया जाना है उनमें समुदायों के लिए वैकल्पिक आजीविका पथ विकसित करना, पार्टी ए या भूमि मालिक परिवारों को सीधे अग्रिम भुगतान, सामुदायिक सहभागिता मीटिंग्स और कौशल प्रशिक्षण शामिल हो सकते हैं।

6. पार्टी ए और पार्टी बी द्वारा आगे के समझौते

6.1 राजस्व साझा करना। दोनों पक्ष इस बात से सहमत हैं कि कार्बन क्रेडिट बिक्री [और परियोजना के नाम पर मिलने वाले अनुदान] से होने वाले सकल राजस्व का कम से कम 45% पार्टी ए को ही मिलेगा।

6.2 पार्टी ए के राजस्व हिस्से को पार्टी बी द्वारा इन चीज़ों पर लागू किया जाएगा: (क) परियोजना में नियोजित समुदाय के सदस्यों के वेतन का भुगतान, कुल राशि के 20% से अधिक नहीं (ख) पार्टियों द्वारा सहमत वैकल्पिक आजीविका गतिविधियों पर खर्च, कुल राशि के 20% से अधिक नहीं (सी) सत्यापित भूमि मालिक परिवारों को सीधे भुगतान, जिनकी भूमि इस समझौते द्वारा कवर की गई भूमि का हिस्सा है, कुल राशि के 10% से अधिक नहीं (डी)

सामुदायिक विकास (एफ) के लिए कुल राशि का कम से कम 50% का भुगतान, जहां बकेट (ए) से (सी) तक के भुगतान इसके नीचे आते हैं सीमा, बचे हुए सभी फंड बकेट (डी) में जोड़ दिए जाएंगे।

6.3 सामुदायिक विकास के लिए पार्टी ए का राजस्व हिस्सा पार्टी बी द्वारा एक सामुदायिक कार्बन फ़ंड में ट्रांसफर किया जाएगा, जिसका प्रबंधन 7.1 के तहत संयुक्त परियोजना ओवरसाइट मैकेनिज़्म की उप-समिति द्वारा किया जाएगा।

6.4 कार्बन क्रेडिट डिस्बर्समेंट के आधार पर, राजस्व साझा करना [तिमाही आधार पर], [छमाही] या [सालाना] किया जाएगा और ऐसे सभी डिस्बर्समेंट का दस्तावेजीकरण करके पार्टी ए को उपलब्ध कराया जाएगा।

6.5 सामुदायिक विकास परियोजना के लिए फंड से डिस्बर्समेंट एक सामुदायिक विकास कार्य योजना (CDAP) के अनुसार होगा, जिसमें कई समुदाय शामिल होंगे और यह स्थानीय सरकार के विकास एजेंडे के अनुरूप होगा।

6.6 किसी भी CDAP के लिए कोई डिस्बर्समेंट नहीं किया जाएगा, जिसमें एक विकास परियोजना शामिल हो, जो इस अनुबंध के तहत भूमि और प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा या इस अनुबंध के तहत जारी किए जा सकने वाले कार्बन क्रेडिट की अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है।

7. शासन और सहभागिता

7.1 एक कार्बन साझेदारी देखरेख समिति (CPOC) की स्थापना की जाएगी, जिसमें शामिल हैं:

- पार्टी ए के प्रतिनिधि (जिसमें दो महिलाएं और एक युवा शामिल हैं)
- पार्टी बी के 5 प्रतिनिधि
- चीफ़डम/मों का पैरामाउंट चीफ़ जहाँ इस अनुबंध के अंतर्गत आने वाली भूमि स्थित है

- 1 ज़िला या नगर कौंसिल का प्रतिनिधि
- 1 जलवायु परिवर्तन पर काम करने वाले सिविल सोसायटी संगठन का प्रतिनिधि

7.2 CPOC गारंटी के आधार पर सीमित कंपनी होगी और वह इन पर नज़र रखेगी:

- परियोजना कार्यान्वयन, जिसमें पार्टी बी के कर्मचारियों, एजेंटों या ठेकेदारों के रोज़गार शामिल नहीं हैं
- सामुदायिक सहभागिता जिसमें विलेज एरिया और चीफ़डम लैंड समितियों के साथ समन्वय शामिल है
- राजस्व वितरण- एक उप-समिति के ज़रिए सामुदायिक कार्बन फ़ंड का प्रबंधन, जिसमें पार्टी ए से अधिकांश वोटिंग सदस्य आते हैं।
- सामुदायिक विकास परियोजनाओं की निगरानी करना।
- विवाद सुलझाना

7.3 कार्बन साझेदारी देखरेख समिति की बैठक हर तिमाही में कम से कम एक बार होगी, और मिनट सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराए जाएंगे और वितरण के लिए स्थानीय भाषाओं में ऑडियो फॉर्मेट में ट्रांसलेट किए जाएंगे।

7.4 पार्टी ए की विलेज एरिया लैंड समितियां (VALC) अपने-अपने गांवों में इस अनुबंध से कवर होने वाली भूमि की सुरक्षा और उसका प्रबंधन करने के लिए उप-कानून लागू करेंगी। हर गाँव में इस अनुबंध द्वारा कवर की गई भूमि के प्रबंधन या सुरक्षा से उत्पन्न होने वाली शिकायतों, विवादों या मतभेदों का समाधान सबसे पहले VALC द्वारा किया जाएगा। अपने कर्तव्यों को पूरा करने में, VALC इस परियोजना के तहत आने वाले किसी भी कर्मचारी, एजेंट या ठेकेदार के साथ मिलकर काम करेगा।

7.5 इस समझौते के कार्यान्वयन के संबंध में VALC और किसी कर्मचारी, एजेंट या ठेकेदार के बीच विवाद या अंतर को समाधान के लिए कार्बन साझेदारी देखरेख समिति के पास भेजा जाएगा। कार्बन साझेदारी देखरेख समिति ऐसे विवादों से निपटने की प्रक्रिया और समय सीमा निर्धारित करेगा।

7.6 VALC अपने इलाके के लिए CDAP के विकास पर सामुदायिक परामर्श का नेतृत्व करेंगे और क्लस्टर VALC के प्रतिनिधि कार्बन साझेदारी देखरेख समिति की उप-समिति में सबमिशन के लिए CDAP को समेकित और अंतिम रूप देने के लिए काम करेंगे।

7.7 चीफ़डम लैंड कमिटी, चीफ़डम में उप-कानूनों को लागू करने में मदद करेगी।

7.8 पार्टी ए के समुदाय के सदस्य, जो कार्बन साझेदारी देखरेख समिति द्वारा निर्धारित की जाने वाली न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, उन्हें प्रशिक्षित किया जाएगा और उन्हें कार्बन मॉनिटरिंग गतिविधियों में शामिल किया जाएगा।

8. उत्सर्जन में कटौती

8.1 जारी किए गए सभी क्रेडिट का पता लगाया जा सकता है और उन्हें संबंधित वॉलंटरी कार्बन या अनुपालन रजिस्ट्री में सार्वजनिक रूप से सत्यापित किया जा सकता है।

8.2 अपने कार्बन फ़ुटप्रिंट को कम करने के लिए, परियोजना उत्सर्जन में कमी के पदानुक्रम के सिद्धांतों को अपनाएगा:

- परियोजना के संचालन से होने वाले किसी भी ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को रोकें
- हरित तकनीक के इस्तेमाल से उत्सर्जन कम करना
- अतिरिक्त ज़ब्ती गतिविधियों (जैसे, फिर से वनीकरण) के ज़रिए किसी भी बचे हुए उत्सर्जन को निकालें या बेअसर करें

8.3 परियोजना स्थानीय कानूनों द्वारा निर्धारित पर्यावरण मानकों के अनुरूप भी होगा।

9. लागू कानून और विवाद समाधान

9.1 यह समझौता सिएरा लियोन के क़ानून के अनुसार संचालित और समझा जाएगा।

9.2 दोनों पक्ष इस समझौते की व्याख्या और इसे लागू करने से संबंधित सभी विवादों को सौहार्दपूर्ण ढंग से हल करने की कोशिश करेंगे और ऐसे विवादों पर चर्चा करने और उन्हें हल करने के लिए CPOC को मंच के रूप में इस्तेमाल करेंगे।

9.3 जहाँ CPOC में कोई विवाद हल नहीं होता है, तो सिएरा लियोन गणराज्य की अदालतों के माध्यम से निवारण के लिए पक्षों के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, एक या दोनों पक्ष समाधान के लिए जलवायु परिवर्तन निदेशालय के पास विवाद जमा कर सकते हैं या मध्यस्थता अधिनियम 2022 या किसी वैधानिक पुन: अधिनियमन या प्रतिस्थापन के प्रावधानों के अधीन मध्यस्थता द्वारा इसे निपटाने का विकल्प चुन सकते हैं।

9.4 जब तक विवाद का समाधान बाकी है, तब तक दोनों पक्ष इस समझौते के तहत अपने दायित्वों को पूरा करना जारी रखेंगे।

10. समापन

10.1 किसी भी पक्ष के पास इस स्थिति में इस समझौते को निलंबित करने या समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित है:

- स्वतंत्र, पूर्व, सूचित सहमति के प्रावधानों का उल्लंघन
- धोखाधड़ी या ग़लतबयानी
- सहमत राजस्व देने में विफलता
- इस समझौते द्वारा कवर की गई भूमि और प्राकृतिक संसाधनों की इस हद तक रक्षा करने में विफलता कि यह इस समझौते के तहत जारी कार्बन क्रेडिट की अखंडता को प्रभावित करती है

11. निगरानी और अनुपालन

11.1 पार्टी बी, पर्यावरण सुरक्षा एजेंसी की कार्बन साझेदारी देखरेख समिति और कार्बन परियोजनाओं विनियामक इकाई (CPRU) को वार्षिक अनुपालन रिपोर्ट सबमिट करेगी।

11.2 पार्टी बी, ऐसे अनुरोध में बताए गए समय के अंदर सीपीआरयू से जानकारी के लिए किसी भी लिखित अनुरोध का अनुपालन करेगा।

11.3 पार्टी बी परियोजना के भीतर समुदाय के सदस्यों को विभिन्न भूमिकाओं में शामिल करेगी, जिसमें सामाजिक और पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए

मैपिंग, रीस्टोरेशन, निगरानी और मापन शामिल है। जहाँ समुदायों में कुछ कौशल उपलब्ध नहीं होते हैं, वहाँ पार्टी बी ऐसे कौशल बनाने के लिए एक योजना तैयार करेगी और उसे लागू करेगी।

12. विविध

12.1 यह समझौता, इसमें बताए गए सभी समझौते और दस्तावेज़, और शेड्यूल से इसमें जुड़े मामलों के संबंध में पक्षों की पूरी समझ होती है।

12.2 इस समझौते और किसी भी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय या स्वैच्छिक कार्बन क्रियाविधि की आवश्यकता के बीच टकराव की स्थिति में, अधिक सुरक्षात्मक मानक लागू होंगे।

12.3 यह समझौता इस प्रकार होगा:

- हस्ताक्षर करने से पहले स्थानीय भाषा (भाषाओं) में अनुवाद किया गया
- स्थानीय भाषा (भाषाओं) में ऑडियो फ़ॉर्मेट में रिकॉर्ड किया गया
- संबंधित सरकारी निकाय के साथ पंजीकृत किया गया

12.4 अगर इस समझौते के किसी भी प्रावधान को किसी भी कारण से अमान्य माना जाता है, तो ऐसी अमान्य होने से अन्य प्रावधानों की वैधता या संचालन प्रभावित नहीं होगा, सिवाय इसके कि ऐसी अमान्यता के निर्माण को लागू करने के लिए जहां आवश्यक हो। इस समझौते के बाकी हिस्सों की वैधता को प्रभावित किए बिना इस समझौते से इस अमान्य प्रावधान को हटा दिया जाएगा।

12.5 अगर पार्टी ए के मामले में निम्नलिखित को नोटिस भेजा जाता है:..... और पार्टी बी के मामले में नोटिस निम्नलिखित को भेजा जाता है, तो पार्टियों को नोटिस सही तरीके से दिया जाएगा:.....

12.6 इस समझौते के नवीनीकरण के अलावा किसी भी कार्रवाई के लिए नोटिस की अवधि एक माह होगी।

इस बात का गवाह है कि पक्षों ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं:

पार्टी ए के प्रतिनिधि:

1. _____
2. _____
3. _____

पार्टी बी के प्रतिनिधि:

1. _____
2. _____

साक्षी:

1. _____
2. _____

अनुलग्नक बी: अतिरिक्त केस स्टडीज़

लाइबेरिया में निवेश अनुबंधों के लिए पूर्व शर्त के तौर पर सामुदायिक भूमि अधिकारों को मान्यता

जोनाथन डब्ल्यू. याह, SDI के द्वारा

इस केस स्टडी में लाइबेरिया की रिवरसेस काउंटी में Blue Earth Capital और ज़ियाड्यू कबीले के बीच कार्बन समझौते पर बातचीत करने के प्रयासों की पड़ताल की गई है। Blue Earth Capital स्विट्ज़रलैंड में स्थित एक प्रभाव निवेश फर्म है जो कार्बन सिंक में निवेश करने और स्वैच्छिक कार्बन बाजार में उत्पन्न क्रेडिट का व्यापार करने पर ध्यान केंद्रित करती है।

Blue Earth Capital ने ज़ियाड्यू कबीले की सामुदायिक भूमि विकास प्रबंधन समिति (CLDMC) को निवेश के इरादे से एक पत्र भेजा था। पत्र में कार्बन सिंक बनाने के उद्देश्य से ज़ियाड्यू कबीले से 68,000 हेक्टेयर वनभूमि लीज़ पर देने के Blue Earth Capital के प्रस्ताव के बारे में विस्तार से बताया गया था। यह व्यवस्था सभी पुष्टि किए गए "संघर्ष-मुक्त[1]" वन क्षेत्रों को कवर करेगी और यह 25 वर्षों तक चलेगी, जिसमें अतिरिक्त दस वर्षों के लिए नवीनीकरण करने का विकल्प होगा। हालाँकि, जब ज़ियाड्यू कबीले ने समझौते के संबंध में Blue Earth Capital के साथ बातचीत करने का प्रयास किया, तो उनके पास लाइबेरिया के भूमि अधिकार अधिनियम 2018 के तहत एक बाध्यकारी कानूनी समझौते में प्रवेश करने के लिए आवश्यक औपचारिक गवर्नेंस स्ट्रक्चर और कानूनी मान्यता का अभाव था।

Blue Earth Capital द्वारा लक्षित 68,000 हेक्टेयर से छोटे क्षेत्र और क्लोह चीफ़डम के केवल एक हिस्से पर ज़ियाड्यू कबीले के पास प्रथागत अधिकार थे। अगर ज़ियाड्यू कबीले को औपचारिक रूप से मान्यता दे दी गई होती और उसके पास भूमि के लिए कोई कागज़ात होते, तो भी उसे पूरे चीफ़डम की ओर से बातचीत करने का अधिकार नहीं होता। टीक्पेह कबीले, ज़ियाड्यू कबीले के साथ एक सीमा साझा करता है और लक्षित वन क्षेत्र के हिस्से के लिए उसके प्रथागत दावे हैं। बातचीत वैध तरीके से आगे बढ़ने के लिए, क्प्लोह चीफ़डम के सभी सदस्यों, जिनमें टीक्पेह कबीला भी शामिल है, को पहले एक संगठित शासन ढांचा स्थापित करना होगा और कानूनी रूप से पंजीकृत होना चाहिए। Blue Earth Capital के साथ बातचीत की प्रक्रिया के दौरान ये मूलभूत पहलू महत्वपूर्ण कमियां थीं।

---

1 लाइबेरिया भूमि अधिकार अधिनियम (2018) अनुच्छेद 33.3: प्रथागत भूमि की सतह में किसी भी तरह के हस्तक्षेप या उपयोग के लिए समुदाय की स्वतंत्र, पूर्व, सूचित सहमति (FPIC) की ज़रूरत होती है।

टीक्पेह कबीले को छोड़कर और सिर्फ़ Blue Earth Capital और ज़ियाड्यू कबीले के बीच एक संविदा स्थापित करने से संभावित रूप से संघर्ष हो सकता था। ज़ियाड्यू कबीले को कानूनी प्रतिनिधित्व हासिल करने के लिए संसाधन जुटाने में चुनौतियों का सामना करना पड़ा और कार्बन निवेशक के साथ उनकी बातचीत के बारे में सोच-समझकर निर्णय लेने के लिए आवश्यक सहभागिता के प्रयासों के लिए पर्याप्त फंड जुटाने में भी चुनौतियों का सामना करना पड़ा।

सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट (SDI), रिवरसेस काउंटी में ज़ियाड्यू और टीकपेह कुलों के पड़ोसी समुदायों में सामुदायिक भूमि पंजीकरण के प्रयासों का नेतृत्व कर रहा था। SDI ने उन समुदायों को इस बारे में भी प्रशिक्षित किया था कि जब निवेशक उनसे संपर्क करते हैं तो उन्हें किस तरह प्रतिक्रिया देनी चाहिए। फलस्वरूप, समुदायों ने SDI को लेटर ऑफ़ इंटेंट और उस ड्राफ़्ट समझौते की समीक्षा करने के लिए आमंत्रित किया, जिसे Blue Earth Capital ने उनके साथ साझा किया था। SDI ने एक कानूनी सलाहकार को नियुक्त किया, जिसने कानूनी राय दी, जो दो अलग-अलग मीटिंग्स के लिए आधार बनी: एक समुदाय के साथ और दूसरी Blue Earth Capital के साथ।

सामुदायिक मीटिंग के दौरान, कानूनी सलाहकार ने उपस्थित लोगों को सूचित किया कि Blue Earth Capital पर उनकी प्रतिक्रिया 2018 के भूमि अधिकार अधिनियम के अनुरूप होनी चाहिए, जिसके लिए एक उचित शासन ढांचा स्थापित करना और कानूनी रूप से पंजीकृत होना आवश्यक है। अनुच्छेद 35.1 के अनुसार, इस संरचना को व्यवस्थित करना ज़रूरी है, इससे पहले कि समुदाय को अनुच्छेद 35.2 के तहत कानूनी पहचान मिल सके, जिससे वह बाध्यकारी समझौते में प्रवेश कर सके। उन्होंने समुदाय से आग्रह किया कि Blue Earth Capital के साथ अनुबंध शुरू करने से पहले एक शासन रूपरेखा स्थापित की जाए। उन्होंने यह भी कहा कि अनुबंध समुदाय के हित में हो भी सकती है और नहीं भी, क्योंकि ये वार्ताएं जलवायु परिवर्तन से जुड़ी समस्याओं के लिए राष्ट्रीय नीति और कानूनी ढांचे के बिना हुई हैं।

इसी तरह की भावनाओं से Blue Earth Capital के प्रतिनिधियों को अवगत कराया गया, हालांकि, उन्होंने SDI को आश्वासन दिया कि सामुदायिक सहमति से कार्बन परियोजना के अगले चरणों के बारे में सूचित करने के लिए व्यवहार्यता अध्ययन शुरू हो जाएगा। रिवरसेस में कार्बन सौदे के बारे में मीडिया कवरेज की वजह से, Environmental Protection Agency of Liberia (लाइबेरिया की पर्यावरण संरक्षण एजेंसी) ने एक चेतावनी जारी की और समाचार आउटलेट में प्रकाशित किया कि उसकी "शामिलगिरी और मंज़ूरी। लाइबेरिया में कार्बन क्रेडिट सौदों के लिए गैर-पराक्रम्य पूर्वावश्यकताएं हैं।"

SDI से जानकारी और कानूनी मार्गदर्शन मिलने के बाद, समुदायों ने Blue Earth Capital के साथ समझौते पर हस्ताक्षर नहीं करने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया। इस समझौते पर हस्ताक्षर करने से वे संविदा में बताई गई भावी देनदारियों के लिए संभावित रूप से प्रतिबद्ध हो जाते। कानूनी मान्यता के बिना, इससे उनके भूमि के अधिकार भी ख़तरे में पड़ सकते थे।

Blue Earth Capital द्वारा अपनी भूमि पर कार्बन रियायतें हासिल करने की कोशिश के बाद, ज़ियाड्यू कबीले और टीक्पेह कबीले दोनों ने दिसंबर 2024 में अपनी पारंपरिक भूमि पर क़ानूनी टाइटल सफलतापूर्वक हासिल कर लिया। यह केस स्टडी इस बात पर प्रकाश डालती है कि मजबूत भूमि कानून सामुदायिक भूमि की सुरक्षा और सामूहिक निर्णय लेने की प्रक्रियाओं को सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण ढांचा बनाते हैं।

ब्राज़ील के Amazon में REDD+ परियोजना में स्वतंत्र, पूर्व, सूचित सहमति और कानूनी अधिकार

जॉनी एफ़ गिफ़ोनी के द्वारा

Rio Anapu-Pacaja REDD+ परियोजना ब्राज़ीलियाई Amazon में पैरा राज्य में पोर्टेल नगर पालिका में स्थित है। इसमें "स्टेट एग्रोएक्स्ट्रेक्टिविस्ट सेटलमेंट परियोजनाओं (PEAEX)" के अंतर्गत एक ऐसे क्षेत्र में 165,000 हेक्टेयर भूमि शामिल है, जिस पर पारंपरिक रूप से नदी और वन समुदाय कब्जा करते हैं। इन क्षेत्रों का स्वामित्व पैरा राज्य के पास है और उन आबादियों के लिए सामूहिक उपयोग के मान्यता प्राप्त अधिकार हैं, जो कारीगरों द्वारा मछली पकड़ने, जीवन निर्वाह कृषि, फल इकट्ठा करने, तेल निकालने और गैर-लकड़ी वाले वनों से बने उत्पादों पर आधारित हैं। ये समुदाय जंगल और नदियों के साथ ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध बनाए रखते हैं और अपनी आजीविका और सामाजिक-सांस्कृतिक परम्पराओं के लिए स्थानीय प्राकृतिक संसाधनों पर भरोसा करते हैं।

यह परियोजना 2016 में स्वैच्छिक कार्बन बाज़ार (कार्बन मार्केट) में शुरू हुआ था, जिसका लक्ष्य सामूहिक रूप से इस्तेमाल किए जाने वाले क्षेत्रों में वनों की कटाई और वनों के क्षरण से होने वाले उत्सर्जन को कम करके क्रेडिट बनाना था।[2] यह परियोजना VCS 2252 कोड के तहत, Verra के साथ रजिस्टर किया गया था और फिलहाल यह "ऑन होल्ड" रोका गया है के रूप में सूचीबद्ध है। यह विवाद परियोजना के लागू होने से पहले ILO कन्वेंशन नंबर 169 के अनुसार मुफ़्त, अग्रिम, सूचित परामर्श (FPIC) की कथित अनुपस्थिति में निहित है। जबकि कंपनियां और अन्य प्रतिवादी दावा करते हैं कि उन्होंने मीटिंग, सार्वजनिक सुनवाई और सूचना सामग्री के वितरण के माध्यम से स्वतंत्र, पूर्व, सूचित सहमति को अंजाम दिया है, राज्य के पब्लिक डिफेंडर के कार्यालय ने समुदायों की ओर से स्वतंत्र, पूर्व, सूचित सहमति प्रक्रिया और नगरपालिका सरकार को इसके अधिकार का उल्लंघन करने के लिए चुनौती देते हुए मुकदमेबाजी की।

2 इस पहल को BLB Florestal Representação no Brasil Ltda के नेतृत्व वाली कंपनियों के एक कंसोर्टियम द्वारा विकसित किया गया था, जो "Amigos dos Ribeirinhos Assessoria Ambiental Ltda" और पोर्टेल में स्थित एसोसिएशन ऑफ़ रिवरसाइड रेजिडेंट्स एंड इनहैबिटेंट्स के साथ साझेदारी में है।

न्याय की समस्या

मुख्य मुद्दा PEAEX क्षेत्रों में उचित स्वतंत्र, पूर्व, सूचित सहमति और सक्षम एजेंसियों की पूर्व अनुमति के बिना कार्बन वेंचर के कार्यान्वयन में निहित है, ख़ासकर इस तथ्य को देखते हुए कि नगरपालिका का राज्य के स्वामित्व वाली भूमि पर अधिकार क्षेत्र नहीं है।

कंपनियों के कंसोर्टियम ने दावा किया कि उसने आमने-सामने मीटिंग, सार्वजनिक सुनवाई, और तकनीकी सामग्री के प्रावधान के ज़रिये, सामुदायिक संगठनों के साथ संविदा स्थापित करके, जिसमें लाभ साझा करना और अन्य प्रतिबद्धताएँ शामिल थीं, स्वतंत्र, पूर्व, सूचित सहमति प्रक्रिया को अंजाम दिया था। हालाँकि, समुदायों के साथ मीटिंग्स और कंपनियों द्वारा आयोजित सार्वजनिक सुनवाई परियोजना को लागू करने के निर्णय के बाद ही हुई, इस तरह समुदायों की प्रभावी, मुफ़्त और सांस्कृतिक रूप से उचित भागीदारी की गारंटी नहीं दी जा सकी। इसके कारण समुदायों में कार्बन परियोजना को लागू करने में शामिल संस्थाओं के प्रति अविश्वास पैदा हो गया। समुदायों ने कुछ फ़ायदे लेने से भी इनकार कर दिया क्योंकि उन्हें अपने क्षेत्र के इस्तेमाल पर कई प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा था और उन्हें ऐसी जानकारी मिली थी जिससे पता चलता है कि वादा की गई राशियों के बारे में उन्हें गुमराह किया जा रहा है। पब्लिक डिफेंडर के कार्यालय और समुदायों का तर्क यह है कि इस अभिगम से आलोचनात्मक विश्लेषण के लिए पर्याप्त समय या परिस्थिति की गारंटी नहीं मिलती और ना ही उन्होंने स्थानयी सामाजिक-सांस्कृतिक विभिन्नता को संबोधित किया है। समुदायों ने बताया कि उन पर दस्तावेज़ों पर हस्ताक्षर करने के लिए दबाव डाला गया था और कंपनियों द्वारा की गई प्रतिबद्धताएं आज तक केवल आंशिक रूप से पूरी हुई हैं। पैरा लैंड इंस्टीट्यूट (ITERPA) और पैरा स्टेट के एटर्नी जनरल जैसी एजेंसियों ने इस क्षेत्र के इस्तेमाल के लिए औपचारिक अनुमति की कमी की पुष्टि की, जिससे परियोजना की कानूनी कमजोरी और बढ़ गई और जब तक कि सभी लागू कानूनी और अंतरराष्ट्रीय ज़रूरतें पूरी तरह से पूरी नहीं हो जातीं, तब तक इसे निलंबित करने की ज़रूरत है।

समुदायों की प्रतिक्रिया

PEAEX इलाक़ों के नदी और वन समुदायों ने परियोजना का शुरू से ही विरोध करने के लिए समन्वित उपायों का एक सेट लागू किया है। ये कार्रवाइयां आंतरिक सभाओं और अंतर-सामुदायिक मीटिंगों से शुरू हुईं, जहाँ स्थानीय नेताओं ने कंपनियों और नगर पालिका से प्राप्त खंडित जानकारी साझा की। इन मौकों पर, उन्होंने परामर्श प्रक्रिया से अपना असंतोष औपचारिक रूप से रिकॉर्ड करने और संभावित कानूनी कार्रवाइयों की सहायता के लिए सबूत इकट्ठा करने जैसे कि कार्यवृत्त, हाजरी सूची, और फ़ोटोग्राफ़िक

रिकॉर्ड जैसे सबूत इकट्ठा करने का फ़ैसला किया। ये शिकायतें स्वतंत्र, पूर्व, सूचित सहमति की अनुपस्थिति और वादा किए गए लाभों को आंशिक रूप से पूरा करने पर केंद्रित थीं, जैसे कि सामुदायिक अवसंरचना में सुधार और सामुदायिक आजीविका के लिए सहायता।

पब्लिक डिफेंडर के कार्यालय ने समुदायों के मुख्य सहयोगी के रूप में काम किया, अदालत में उनका प्रतिनिधित्व किया और परियोजना को निलंबित करने और नगरपालिका के अधिनियमों को रद्द करने के लिए सरकारी एजेंसियों से अनुरोध समन्वयित किए। परियोजना के कार्यान्वयन के समय, समुदायों के पास कार्बन क्रेडिट की बिक्री से मिलने वाले वित्तीय संसाधनों का प्रबंधन करने के लिए कोई प्रशासनिक ढांचा स्थापित नहीं था। उनके पास स्पष्ट शासन विधियों, जवाबदेही प्रक्रियाओं और सभी निवासियों द्वारा मान्यता प्राप्त प्रतिनिधित्व के साथ औपचारिक जुड़ाव का अभाव था। कुछ नेताओं द्वारा समझौते पर हस्ताक्षर करने की वैधता और निर्णय लेने की शक्ति को लेकर असहमतियां थीं, जिससे समुदाय बाहरी दबावों के प्रति ज़्यादा संवेदनशील हो गए थे। समुदायों के पास बड़े पैमाने पर और लंबी अवधि के भुगतानों के लिए पर्याप्त वित्तीय प्रबंधन प्रणालियों की कमी थी, साथ ही कंपनियों और नगर पालिका द्वारा अनुपालन की पुष्टि करने के लिए निगरानी और मूल्यांकन उपकरणों का भी अभाव था। इसके अलावा, परामर्श और सहमति के लिए कोई स्वायत्त सामुदायिक प्रोटोकॉल नहीं था, जो समुदायों को स्वतंत्र, पूर्व, सूचित सहमति प्रक्रिया को परिभाषित करने की अनुमति देता और यह सुनिश्चित करता कि यह कभी-कभार होने वाली मीटिंगों और देर से होने वाली सार्वजनिक सुनवाइयों तक सीमित न रहे। समुदायों के पास निरंतर और स्वतंत्र तकनीकी और कानूनी सहायता का भी अभाव था, जिसका मतलब था कि परियोजना के बारे में जानकारी को समर्थकों ने ख़ुद ऐसे तरीके से नियंत्रित किया था, जिससे समुदाय की सोच-समझकर निर्णय लेने की क्षमता कम हो जाती थी।

नतीजे और अगले चरण

PEAEX के नदी और वन समुदायों द्वारा अपनाए गए उपायों का असर पड़ा, हालाँकि बड़े संरचनात्मक और संस्थागत अवरोधों के कारण वे केवल आंशिक रूप से प्रभावी थे। कानूनी-कार्रवाई से पहले के चरण में, आंतरिक सभाओं और अंतर-सामुदायिक मीटिंग्स से एक मजबूत दस्तावेजी रिकॉर्ड (मिनट, उपस्थिति सूची, फ़ोटोग्राफ़िक रिकॉर्ड और आधिकारिक पत्र) तैयार किए गए, जिन्होंने कानूनी कार्रवाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इसके कारण Verra ने परियोजना को निलंबित कर दिया। इन दस्तावेज़ों ने स्वतंत्र, पूर्व, सूचित सहमति की अनुपस्थिति के बारे में तर्क को मजबूत किया, जिससे पता चलता है कि सार्वजनिक सुनवाई और दूसरी मीटिंग्स परियोजना को लागू करने के निर्णय के बाद ही हुईं। सामुदायिक कार्रवाई सबूत बनाने और उनकी चिंताओं को स्पष्ट रूप से बताने में बहुत प्रभावी साबित हुई।

फिर भी समुदायों की प्रभावी ढंग से संगठित होने की क्षमता जानकारी की विषमताओं, परियोजना अनुबंधों को समझने में चुनौतियों और निरंतर कार्रवाई के लिए दुर्लभ संसाधनों के कारण सीमित थी। साथ ही, समुदाय परियोजना के तात्कालिक प्रभावों को केवल आंशिक रूप से दूर कर पाए हैं। इकट्ठा की गई सामग्री और स्थापित संस्थागत गठबंधनों से परियोजना के बारे में आने वाली वार्ताओं के लिए रणनीतिक संपत्ति का गठन किया जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा नतीजे पाने के लिए कानूनी, राजनीतिक और सामुदायिक प्रयासों में तालमेल बिठाना ज़रूरी है।

इस प्रकृति के विवादों को संबोधित करने के लिए निम्नलिखित प्राथमिकताएं सामने आती हैं (i) खास, स्वतंत्र तकनीकी और कानून सहायता जो कार्बन अनुबंधों, पर्यावरण संबंधी विधेयकों, भूमि से जुड़े अधिकारों और अंतर्राष्ट्री स्वतंत्र, पूर्व, सूचित सहमति मानकों पर केन्द्रित हो; (ii) शासन और आर्थिक प्रबंधन में समुदाय के लिए प्रशिक्षण, जिसके तरीकों को स्थानीय वास्तविकताओं के अनुकूल किया गया हो; (iii) परामर्श और सहमति के लिए स्वायत्त सामुदायिक प्रोटोकॉल करी रचना और सत्यापन करना, जिसमें निर्णय लेने की स्वायत्ता और बातचीत के लिए स्पष्ट मानदंड स्थापित करने की क्षमता हो; (iv) भूमिभूमि अधिकारोंकी स्वतंत्र देखरेख जिसमें पार्टिसिपेटरी मैपिंग, परंपरागत उपयोग और कबज़े पर रिपोर्ट और भूमि के नियमन के लिए सलाहकार सेवाएं हों; और (v) राजनीतिक अभिव्यक्ति और सार्जवनिक दृश्यता, गैर-सरकारी संगठनों, विश्व विद्यालयों, सामाजिक आंदोलनों और देखरेख निकायों से जुड़ाव को मज़बूत बनाना, ताकि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर समुदाय के अधिकारों की रक्षा हो सके, खास कर कार्बन मार्केटों के बारे में चर्चा के दौरान।

अनुलग्नक सी: अतिरिक्त संसाधन

कार्बन बाज़ार (कार्बन मार्केट)

Forest Peoples Programme (फॉरेस्ट पीपल प्रोग्राम) से कार्बन मार्केट्स के बारे में परिचय वीडियो

कार्बन अधिकार: शुरूआत करने के लिए समुदायों को किन चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए

कार्बन न्याय 101 कोर्स

स्वतंत्र, पूर्व, सूचित सहमति प्रोटोकॉल

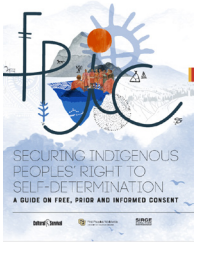

स्वतंत्र, पूर्व और सूचित सहमति के बारे में एक मार्गदर्शिका

बातचीत

सामुदायिक-निवेशक बातचीत मार्गदर्शिका 1: पहले से तैयारी करना

सामुदायिक-निवेशक बातचीत मार्गदर्शिका 2: अनुबंधों के बारे में समझौते करना

समुदाय के उप-नियम

[भूमि और प्राकृतिक संसाधनों के सामुदायिक शासन को मजबूत करना]

[भूमि शासन के लिए नियम बनाना]

[समुदाय के उप-नियमों का मसौदा बनाना]

किसी समझौते की शर्तों की निगरानी करना और उन्हें लागू करना

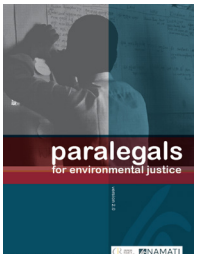

[पर्यावरण न्याय पैरालीगल्स के लिए अभ्यास मार्गदर्शिका]

[न्याय के लिए सबूत कैसे तैयार करें — पर्यावरणीय अनुपालन का वास्तविक सत्यापन करना]

[वेरा शिकायत निवारण नीति]

Grassroots Justice Network

BUILDING POWER TOGETHER

हम एक ऐसी दुनिया बना रहे हैं, जहाँ अन्याय से सबसे ज़्यादा प्रभावित समुदाय अपने अधिकारों की रक्षा कर सकें और उन्हें प्रभावित करने वाले फ़ैसले लेने में हिस्सा ले सकें। लोगों को क़ानून को जानने, इस्तेमाल करने और उसे आकार देने में मदद करने — एक प्रक्रिया जिसे कानूनी सशक्तिकरण कहा जाता है — की हमारी प्रतिबद्धता हमें एकजुट करती है।

Grassroots Justice Network का आयोजन Namati ने किया है

community@namati.org @grassrootsJN grassrootsjusticenetwork.org